THE UNION BUDGET, 2021-22*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) : माननीय सभापति जी, इस बजट में आशा दिखती है। आशा दिखती है एक नए भारत की, सशक्त भारत की, आत्मनिर्भर भारत की। I see a hope, hope for a new India, a stronger India and a self-reliant India. It will set us on the path of economic and manufacturing powerhouse. इसमें विशेष तौर पर देखा जाए, तो capital expenditure में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो अपने आपमें एक रिकॉर्ड है। इसमें लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा capital expenditure किया जाएगा।

सर, जब मुझसे विपक्ष के नेताओं में मनोज जी कह रहे थे कि 'आम बजट या खास बजट', तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी प्रधान मंत्री ने सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, तो उनका नाम नरेन्द्र मोदी है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा किया है। ...(**व्यवधान**)... सर, देखिए, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को शौचालय देना, हर परिवार को पक्का मकान देना, हर गाँव तक बिजली पहुँचाना, हर गरीब को मुफ्त में बिजली देना, 4-4 एलईडी के बल्ब देना तथा अब हर घर नल और नल से स्वच्छ जल देने का काम भी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार करने जा रही है। यही नहीं, अनुसूचित जाति को आप किसमें गिनते हैं, खास में या आम में, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ? सर, अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए, तो across ministries, 51.65 प्रतिशत की बजट में वृद्धि की गई है। इसको लगभग 83 हजार करोड़ से बढ़ा कर 1 लाख, 26 हजार करोड़ से ज्यादा किया गया है। सर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके लिए काम करता है, सामाजिक न्याय किसके लिए - उस पिछड़े के लिए, जिसको पहले लाभ नहीं मिलता था। अगर उसके लिए उस बजट में 28 प्रतिशत की वृद्धि की, तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा करने का काम किया है। यही नहीं, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आप उनको किसमें गिनते हैं, आम में या खास में, उनके लिए भी बजट में 30 प्रतिशत की वृद्धि करके उसमें 1,171 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। इसी तरह से 'मिशन शक्ति' है। आप महिलाओं को किसमें गिनते हैं, अगर 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो इसमें की गई है। 'पोषण-2.0 अभियान' किनके लिए है, उन बच्चों के लिए, जो कुपोषण का शिकार होते थे। यह उन्हीं के लिए शुरू किया गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : प्लीज़, प्लीज़। आप अपनी-अपनी जगह पर बैठिए, बात मत कीजिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : वे महिलाएँ, जो anaemic रहती थीं, फिर टीबी मुक्त भारत किसके लिए, ताकि हमने हिन्दुस्तान में दुनिया से पहले जो टारगेट रखा है कि 2030 नहीं, बल्कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त बनाएँगे, यह भी किसी ने रखा, तो नरेन्द्र मोदी जी ने रखा।

---

* Further discussion continued from 11.02.2021.

सर, यहाँ यह आरोप लगाया गया कि हम family silver बेचने जा रहे हैं। एक तो इनके नेता ने कहा कि 'हम दो, हमारे दो', मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन वे कौन सी दो कंपनियाँ थीं, जिनको आपने देश के चार बड़े एयरपोर्ट्स दे दिए! न आपने दिल्ली छोड़ी, न मुम्बई, न हैदराबाद, न बेंगलुरु। क्या आप जवाब देंगे कि इन 6 एयरपोर्ट्स को privatize करने का काम आपके समय शुरू हुआ था, जो इसके बाद मिला है? एयर इंडिया की दुर्गति किसने की? क्या हालत थी एयर इंडिया की, क्या देश नहीं जानता! किन हाथों में आपको देकर गए थे और आपने 28 की बजाय 58 एयरक्राफ्ट्स खरीदने की बात की। 7 हजार करोड़ का revenue आता था, लेकिन आपने 50 हजार करोड़ का कर्ज ले लिया। आप एयर इंडिया को डुबा कर चले गए, अब आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के taxpayers का पैसा, हर साल 6-6 हजार करोड़ रुपया उसके लिए डाला जाए, लेकिन देश की गरीब जनता के विकास के लिए न दिया जाए! क्या करना चाहिए, आप प्राथमिकता तय कर लीजिए।

माननीय सभापति जी, यही नहीं, दुर्भाग्य इस बात का है कि गलतियां ये करके जाएं और.... आपकी सरकार के समय में दस साल तक महंगाई की दर 11%-12% रही थी, लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में average inflation 4% है। हमारी सरकार ने यह काम करके दिखाया है। आप fiscal deficit को 5.6% पर छोड़ कर गए, लेकिन हमने उसको कम करके 3.5% से कम पर लाने का काम किया है। अगर देखा जाए, तो आपने हिन्दुस्तान के बैंकों को लगातार, एक के बाद एक aggressive lending करवा के, उन लोगों को पैसा देने के लिए मजबूर किया। पैसा लेकर आज वे लोग विदेशों में भाग खड़े हुए हैं, लेकिन तब भी आपने उनके लिए कोई कड़ा कानून नहीं बनाया। इस सम्बन्ध में जो कड़ा कानून, Fugitive Economic Offenders Act बनाया, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। मोदी सरकार ने बैंकों का asset quality review करवाया और सही NPAs declare किए। उसके बाद बैंकों का 5.5 लाख करोड़ रुपये का जो recapitalization किया, वह मोदी जी की सरकार ने किया।

(उपसभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

इस साल भी बैंकों को फिर से 20,000 करोड़ रुपये देने की बात की है। आज बैंकों को जो PCA framework से बाहर लाई है, वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार लाई है। आप किसी भी विषय पर, किसी भी Department के काम पर चर्चा करें, आप देखेंगे कि देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज पूरी दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है। यही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या बात थी कि आपकी सरकार के समय में एक के बाद घोटाले आते चले गए। डॉक्टर साहब ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन नीचे के जो सब लोग थे, आप उनके काम को देखेंगे, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह कई घोटाले आते चले गए। आपके समय में शायद ही कोई डिपार्टमेंट ऐसा होगा, जहां से घोटाले की बू न आ रही हो। मोदी सरकार के सात वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन कोई सात पैसे का आरोप भी मोदी सरकार के किसी मंत्री पर नहीं लगा सका है, क्योंकि यह ईमानदारी से चलने वाली सरकार है। यही नहीं, आपमें से एक माननीय सदस्य ने कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम कुटीर उद्योगों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? हमने तो जो किया सो किया, लेकिन आप

तो उसकी definition तक को भी नहीं बदल पाए। हमने सूक्ष्म, लघु और मध्यम कुटीर उद्योग की definition बदली, उनकी turnover limit को बढ़ाया और इस आपदा के समय में बगैर किसी guarantee and collateral के 3 लाख करोड़ रुपये देने के साथ-साथ 20 per cent additional working capital दी। इसके साथ-साथ Subordinate Debt Scheme में 30,000 करोड़ रुपये दिए गए और Partial Credit Guarantee Scheme में भी पैसा दिया गया। यही नहीं, cost of lending has also gone down.

सर, आज interest rate लगातार कम हो रहा है और लोगों की खरीदारी बढ़ रही है। Real estate में वापस तेज़ी कैसे आई है? क्यों मध्यम वर्ग के लोग आज अपना घर लेना चाहते हैं? यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमने एक साल के लिए वापस उनको income tax exemption दिया है और interest subsidy को भी बढ़ा दिया है। आज गरीब लोगों को घर मिल रहा है। RERA जैसा कानून लाया गया है। पहले जब माननीय सभापति जी इस विभाग में मंत्री थे, उस समय माननीय श्री वेंकैया नायडु जी RERA का कानून लेकर आए थे। ये सब काम मोदी सरकार के समय में हुए हैं, जिनके माध्यम से गरीब लोगों को घर मिलने का काम हुआ और रुके हुए projects को भी पूरा करने का काम भी हुआ। हमने MSME के लिए restructuring allow की और 25 करोड़ तक के जो accounts थे, उनके लिए resolution लाने और restructuring करने का काम किया। कामत कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में इसमें 26 सेक्टर्स को जोड़ने की सिफारिश की, उसमें health को भी जोड़ा गया और उनको भी पैसा देने का काम किया गया।

आपमें से किसी ने कहा कि हिन्दुस्तान manufacturing hub नहीं बन सकता है। इस देश के अपर हाउस में बैठकर कर अगर कोई यह कहता है कि हमारा देश manufacturing hub नहीं बन सकता है, तो यह कहने वाले का दुर्भाग्य है। हम माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी skilled workforce भी बनाएंगे, manufacturing powerhouse भी बनाएंगे और economic powerhouse भी बनाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमने कौन-कौन से कदम उठाए। हमारी सरकार Production-Linked Incentive Scheme लेकर आई। हमारे यहां मोबाईल की केवल दो फैक्टरीज़ थीं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान इतना आगे बढ़ा कि भारत आज दुनिया में मोबाईल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन कर तैयार हो गया है, दुनिया भर की बड़ी-बड़ी कम्पनीज़ यहां आ गई हैं, 'एप्पल' की तीन से ज्यादा यूनिट्स यहां लग रही हैं। यही नहीं, अब हमने Production-Linked Incentive Scheme के लिए 10 sectors identify किए हैं, जिसके लिए हमने 1,97,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सभी सेक्टर्स में हम भारत को ऊँचाई की बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। माननीय स्मृति इरानी जी का डिपार्टमेंट 'मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क (मित्रा) योजना' लेकर आया है। हमारे देश में textile के सात बड़े पार्क आएंगे। एक-एक पार्क में 40 से 50 हजार लोगों को रोज़गार मिल सकता है, इस तरह की संभावनाएं खड़ी हो रही हैं। इसके साथ-साथ medical devices and diagnostic के चार पार्क आएंगे। हम दुनिया की एक बड़ी फार्मेसी हैं, लेकिन raw material कहीं और से आता है, इसलिए अब raw-material यहीं पर बन सके, इसके लिए तीन बड़े Bulk Drug Parks आने वाले हैं। इन पार्कों के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का investment किया जाएगा। हम फिनटेक हब यहां बनाने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, ये पूछते थे कि जॉब क्रिएशन कहां से होगी? यहीं से होगी। रीयल एस्टेट बढ़ रहा

है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, केपिटल एक्सपेन्डिचर हम साढ़े पांच लाख करोड़ ज्यादा करने जा रहे है। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा तो अढ़ाई से तीन गुणा ज्यादा होगा। क्योंकि पटनायक जी यहां बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही थी कि ओडिशा की सैल्फ हैल्प ग्रुप महिलाओं ने कैसे शानदार काम किया। सर, सुनकर मज़ा आता है कि कोई, अपने राज्य के बारे में अच्छा काम किया, उसका उल्लेख करे, हमें सीखने को मिलता है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सैल्फ हैल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए उसमें दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख रुपये किये, ताकि हमारी बहनें और ज्यादा अपने स्वयं सहायता समूह बना सकें।

यहां रेड्डी जी बैठे थे, उन्होंने टर्मरिक बोर्ड बनाने के लिए बात कही, उन्होंने यह भी कहा कि एनआरआईज. के लिए वैलफेयर बोर्ड बने। मज़ा आता है, जब कोई विपक्ष का नेता केवल आलोचना न करने की बजाय अच्छे सुझाव दे। सरकार उन पर विचार करती है और इस बजट को बनाने से पहले हमने लगातार पूरे देश के बुद्धिजीवियों से, अर्थशास्त्रियों से विचार-विमर्श किया और आपदा के समय भी नरेन्द्र मोदी जी ने जो कदम उठाये, वे दुनिया और देश के लोगों से बात करके उठाये। सभी मुख्य मंत्रियों को ऑन बोर्ड लिया। यही कारण है कि आज दुनिया के जिन देशों में सबसे कम मृत्यु दर है, तो हिन्दुस्तान उन देशों में से एक है। यही नहीं, हिन्दुस्तान में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, हम आत्मनिर्भर हुए, आज हम दुनिया भर को पीपीई किट देते हैं। हिन्दुस्तान हाथ फैलाता था, आज दुनिया के सौ से ज्यादा देशों को कोविड वैक्सीन देने का काम किया तो हिन्दुस्तान की सरकार ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। यही नहीं, हम और आगे बढ़ेंगे, सैल्फ रिलायंट बनेंगे।

सर, कुछ बातें किसानों के बारे में कहकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि बजट में 65 हजार करोड़ रुपये का एक बड़ा हिस्सा 'पीएम किसान योजना' में दिया है। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि यह क्यों कम हो गया, यह इसलिए कम हो गया, क्योंकि तृणमूल की सरकार ने पश्चिमी बंगाल के किसानों को जो 14 हजार रुपये प्रति किसान मिलने थे, उन्होंने देने से मना कर दिया कि हम अपने प्रदेश के किसानों को नहीं देंगे। पश्चिमी बंगाल के किसानों को यह पैसा मिल सकता था, लेकिन ममता जी की हठधर्मी के कारण यह पैसा वहां नहीं मिल पाया। चाहे 'आयुष्मान भारत योजना' हो, वह पश्चिमी बंगाल में नहीं मिल पाई। वहां हिंसा का दौर चलता है, वहां लोकतंत्र की हत्या होती है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने फिर भी किसानों के उत्थान के लिए कदम उठाये। कौन कहता है कि वह हमसे ज्यादा किसानों के लिए कर पाया? मैं इस खुले मंच से पूछना चाहता हूं - ये लोग कहते हैं कि काला कानून है, जिनकी नज़र ही काली होगी, सोच ही वैसी होगी, उनको यह कानून काला ही नज़र आएगा। हिन्दुस्तान के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए इस कानून को लाया गया है और हम प्रतिबद्ध है, हम हिन्दुस्तान के किसानों की आय को दोगुना करके छोड़ेंगे।

सर, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं। अगर आप देखें कि यूपीए के टाइम में गेहूं की खरीद 2013-14 में 33,874 करोड़ की हुई। हमने उससे दोगुने से ज्यादा 75 हजार करोड़ की खरीद की। धान की खरीद इन्होंने 63 हजार करोड़ की की, हमने 1,72,752 करोड़ की की। इन्होंने कपास की मात्र 90 करोड़ की खरीद की, लेकिन मोदी सरकार में 25,974 करोड़ की खरीद हुई। कहां 90 करोड़ और कहां 25,974 करोड़। यही नहीं दलहन के लिए 235 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये तो हमने 10,530 करोड़, 40 गुणा से ज्यादा खर्च किये।

सर, अंत में केवल दो बातें कहकर मुझे अपनी बात खत्म करनी है। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ताकि पेरिशेबल गुड्स खत्म न हों। आपने 65 सालों तक क्यों नहीं बनाया? मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल आदि किसी के दाम नहीं बढ़ेंगे। बड़े-बड़े बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री पिछली सरकार में थे, मैं खुली चुनौती देता हूं, उनमें कोई एक व्यक्ति आकर कहे कि कैसे सेस लगाने से दाम बढ़ सकता है। इस सदन में आकर वह गलत आंकड़ा देकर चले गये। दूसरे सदन में जाएं या इस सदन में कहें, आप लोग कहते हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी। मेरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खुली चुनौती है, कोई बताये, किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी? कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा? है किसी कांग्रेस के नेता में दम या विपक्षी दल के नेता में दम, जो यह बतायें कि कृषि कानून में कहीं पर भी लिखा है कि मंडी बंद होगी या एमएसपी बंद होगा। देश के गरीब किसानों को, भोले-भाले किसानों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। किसानों की आय को दोगुना करने का काम हमने लिया है और करके छोड़ेंगे। आप जितना मर्जी भ्रमित कीजिए, महात्मा गांधी के इस देश में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हिन्दुस्तान को आगे लेकर जाएंगे - आत्मनिर्भर बनायेंगे और मैं इतना ही कहता हूं कि आप जो मंडी खत्म करने की बात करते थे, हम हज़ार मंडियों का और सशक्तिकरण करने जा रहे हैं। आपके पास न तर्क है, न तथ्य है, आप केवल टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ऐसी बात बोलो - हैडलाइन बने, नेगेटिव न्यूज़ चलती रहे। हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहते हैं। हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ पर देश के नौजवान, महिला, मजदूर, किसान, जवान, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। जब आप इस अर्थव्यवस्था को छोड़ कर गये थे - मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि जब 2014 में हमने सत्ता ली, तब भारत दुनिया की पाँच लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने हिन्दुस्तान को दुनिया की पहली छः अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा किया है। India was among the fragile five economies. Today, India is among the top six economies of the world. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम हिन्दुस्तान को आगे ले जाने के लिए समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। आप विपक्ष की भूमिका निभाइये, सकारात्मक सोच के साथ आप सहयोग दीजिए। जब आप सत्ता में थे, तब हम भी देते थे, आज आप भी दीजिए, हम इकट्ठे मिल कर भारत को मजबूत बनायें। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I thank you for allowing me to speak. *"Bahujana Hitay, Bahujan Sukhay"* is a dictum enunciated in Rigveda which emphasizes that public welfare lies in the happiness of the masses. Kautilya Chanakya has said: *"Praja Sukhe Sukham, Rajyaha Prajanamcha hitehitam."* It means, in the happiness of his public rests the king's happiness, in their welfare, his welfare. He shall not consider as good only that which pleases him but treat as beneficial to him whatever pleases his people.

The economy has shrunk and revenues plunged with fiscal deficit tripling to 9.5 per cent of GDP as against the budgeted 3.5 per cent. Receipts under all three

heads, tax revenues, non-tax revenues and non-debt capital, fell short in the current fiscal as compared to their budgeted targets. There was a colossal level of expectation on the Union Budget 2021, as it had the opportunity as well as capability to provide a boost to the economy; whereas, it provided no remedy for the struggling economy. The sectors with huge appetite such as Education, Health, Agriculture and Defence have received comparatively lesser funds, most astonishingly. The primary concerns for the growth of the country, unemployment and inequality have gone out of focus. Most importantly, there has been no announcement on sector-specific revival packages for ailing sectors like telecommunication, power, construction, mining, aviation and travel, tourism and hospitality. These only reflect that the state of affairs are averse to the dictum of the Rigveda or utterances of Kautilya Chanakya, under the current regime. The Budget Statement of 2021-22 only confirmed that the Government is committed to an institutionalized programme to increase the income inequality while allowing for the unbridled growth of corporate private capital. Its growth model is of an economy driven by the sheer brute power of private capital on the back of rising mass poverty. The hon. Finance Minister felt no need to explain in the Budget, how and why the fiscal deficit is nearly twice of what it was in the previous year. Also, she felt no need to explain where this shortfall in taxes occurred. These are important questions to understand for one who is bearing the costs of the pandemic. The shortfall in collection of taxes was 35 per cent from corporate taxes, 29 per cent from income tax and only 15 per cent from indirect taxes, that is, goods and services tax, excise on petrol and diesel etc. This suggests that the companies and the rich who pay income tax suffered more from the pandemic as they paid less taxes than expected! But the poor, who lost jobs, suffered the most during pandemic, also paid way more taxes in proportion to their income than the rich. They not just paid GST on every essential commodity they consumed, but the high taxes on petrol and diesel pushed the price up of these commodities further, leading the poor to bear a larger cost of the pandemic. You would be sad to know that we have repeated the event of first Budget, 73 years ago, way back in 1947-48, where corporate taxes were estimated to be less than income tax. This is our progress. We are moving backwards. We know that the poorest suffered the most from the pandemic and continue to suffer but this Budget reveals that even the Government extracted more from them.

Sir, I would say, they were being made to pay through their nose. All this is to make further easier for the rich and super rich of the country. The Budget announces that it will reduce the investigation period for tax evasion from six years to three years, and also raise the limit for serious fraud cases to an annual income of Rs.

50 lakh and above. This effectively puts an end to a substantial number of earlier income tax evasion cases. In this regard, I would just say that we all know, and you will be pleased to know, and you will appreciate, that the founding principles of democracy reiterate the phrase, "of the people, for the people & by the people". However, this Government is guided by different principles which are poles apart from that and it is, I feel, "for the capitalists, by the capitalists, and of the capitalists". I would also say that the Government has only one magical answer to all problems and what is it? It is to privatise the public sector and monetize the public assets, including lands, public works, highways, electricity lines, whatever. The Budget announced that it will, in the year ahead, privatise two public sector banks. It has decided this without even naming which banks it plans to privatise. This indicates that there is no rationale or reason other than brazen commitment to the private sector. Sir, also, we know that the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India ensures only up to Rs. 5 lakhs which is inducing a fear psychosis about investing any further in the public sector banks. This is a process for the capital to go elsewhere. The message from the Budget is that if you suffered so be it, don't complain, don't expect anything, just get on with it. This is the notion of self-reliance; self-reliance of individuals, not that of the country, and thus, Government opened the insurance industry to complete foreign ownership and control. The Life Insurance Corporation of India has been sacrificed, I feel, on the altar of crony capitalism. Now, we are having certain electoral lurings. The Government has announced Rs. 100 crore package for tea plantation workers in Assam and West Bengal. Of course, it is a welcome move, but for tea plantation workers who are beyond destitution have been so far suffering for decades. This is nice if we look into the facts exactly how far will this money go:- If it is divided equally among the five lakh tea plantation workers in the two States, it amounts to Rs. 2,000 per worker for the whole year. Should I repeat, Sir? It is for the whole year. So, it is well-imaginable as to how far it will solve their problems. In this regard, also, I would like to bring to your notice that during the last Lok Sabha polls in Bengal, there were electoral promises of 7 tea estates being put under acquisition and till date, noting has transpired and the labour is continue to suffer.

Sir, now, I will mention the sector-wise problems that have been created. The education sector observed a dip in terms of fund allocation. The allocated fund to Education Ministry has been brought down by Rs. 6,086-plus crores. That means, now, it is Rs. 93,224-plus crores in 2021-22. The fund for essential schemes like *Samagra Shiksha Abhiyaan* also has been brought down from Rs. 38,750 crores to Rs. 31,050-plus crores. The fund allocation for

National Scheme for Incentive to Girls for Secondary Education has been decreased by Rs. 100 crores. All these are deplorable steps. Surprisingly, there has been no announcement on digital infrastructure despite a mammoth increase on online learning as schools, colleges and coaching institutes had to remain shut due to the pandemic. In this regard, I would like to mention that the Bengal Government, under the leadership of hon. Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, provided Rs. 10,000 to 9.5 lakh students of Class XII to buy smart phones for online education. For the agricultural sector, the Budget did not enhance any support to the agricultural sector. There is no such increase in the outlays on any of the existing central sector schemes on agriculture, including that on crop insurance, or those centrally-sponsored schemes transferred to the States like on irrigation, the RKVY or the Food Security Mission.Out of the Budget outlay of Rs.1.30 trillion for 2019-20, the actual spending was Rs.94,251 crores. In 2020-21, out of Rs.1.34 trillion, the spending was Rs.1.17 trillion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Abir Ranjan*ji*, please conclude.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Sir, I will take two minutes more and then conclude. Most astonishingly, this year, from the much hyped about scheme, this Government's flagship scheme, PM-Kisan, Rs.10,000 crores have been slashed in that account. While this Government lauds the *Kisan* as *Annadata*, but this does not reciprocate in its actions. So this is not expected. Whereas, while allocating Rs.900 crores for the newly-created Agricultural Infrastructure Fund for 2020-21, there has been a cut of Rs.1,700 crores on the Interest Subsidy Scheme for farm loans. For the defence sector, it has remained more or less the same. We know the threat of China and Pakistan looms large. We also know that they are joining hands in trying to put us in uneasiness. But in spite of that, there has been only a marginal increase of Rs.3,266 crores. The Defence pension needs to be mentioned. It has dipped from Rs.1.3 lakh crores in Budget estimates to...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Sir, I will take one minute more. Currently, it has been decreased by Rs.17,775 crores or 13.4 per cent. I can go on saying this but because of paucity of time, I will just conclude. There are disregarded sectors. The focus on inequality was completely missing ignoring the poor, the migrant workers, the daily wage earners...(*Interruptions*)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. I am calling the next speaker now. ...(*Interruptions*)...

SHRI ABIR RANJAN BISWAS: Sir, I will take just half-a-minute. I will say one thing and conclude. If India's top 11 billionaires are taxed at just one per cent of their wealth, it would pay the average wage of nine lakh ASHA workers for five years. ...(*Interruptions*)... Sir, with these words, I conclude...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri M.V. Shreyams Kumar. ...(*Interruptions*)...

SHRI M.V. SHREYAMS KUMAR (Kerala): Sir, the Finance Minister has stated that the Budget proposal rests on six pillars. However, in reality these six pillars rest on six enemies of the mind, that is, *kama*, *krodha*, *lobha*, *moha*, *mada* and *matsarya*. *Kama*-with the lust for more power, and *lobha*-greed to capture power; the Finance Minister has eyed on the ensuing elections in West Bengal, Kerala, Assam and Tamil Nadu and promised allocation for road infrastructure. The people of these States cannot be swayed away by the *moha* created by the Finance Minister. The Budget has shown *krodha*, *mada*, that is, false pride or ego, and *matsarya*, that is, envy, on the flagship programme of UPA Government and the world's largest Rural Employment Generation programme, MGNREGA, with a reduced allocation of Rs.38,500 crores, that is, a 34 per cent reduction. If this is any indication, the next Budget will be the last nail in the coffin of MGNREGA.

The proposal for privatizing the largest and most trusted insurance company in India, LIC and sale of Central PSUs, two public sector banks and one general insurance company militates against the establishment of a socialistic pattern of society envisaged by our founding fathers. Article 39(C) of the Constitution of India provides for regulating the economic system of the country so as to prevent concentration of wealth and resources in a few hands. Yesterday, Mr. Chidambaram was mentioning that 73 per cent of the wealthiest constitute one per cent of the population.

The allocation of Rs.65,000 crores for 1,100 kilometres of national highway works in Kerala is welcome. But several other demands from the State of Kerala have not been considered. Kerala wanted the Centre to increase its share in various welfare pension schemes, presently ranging from Rs.300-500 per month to, at least, Rs.1,000 per month. Kerala is currently giving a welfare pension of Rs.1,600 per month to 49 lakh pensioners with Direct Benefit Transfer of Rs.30,734 crores. Price

stability for commercial cash crops has not been considered. Even though Rs.1,000 crores were allocated for the welfare of tea workers in Assam and West Bengal, but Kerala is totally ignored. Kerala produces 60 million odd kilograms of tea every year and is ranked fourth in India.

11.00 A.M.

Kerala's demand for Trivandrum - Kasaragod semi high rail project, setting up of All India Institute of Medical Science (AIIMS), Sabari Rail Project, which aims to put the hill shrine into the railway network have been totally ignored. The long pending demand for special railway zone for Kerala is not considered. There is nothing in this Budget which addresses the key aspect of indigenisation of solar hardware. India's current annual demand for solar cell manufacturing is 20 gigawatts whereas its current average annual capacity is just 3 gigawatts. You have increased the duty from 5 to 15 per cent. The Finance Minister claims that there is an increase of 137 per cent in the Budget outlay for health. This is nothing but jugglery of figures. Budget estimates for Health is Rs.74,602 crores only, which is actually lower by Rs.7,843 crores, that is, lower by 9.5 per cent than the Revised Estimates and not as claimed by the Finance Minister. 95 per cent reduction for Women Empowerment Mission; a Budget outlay of just Rs.48 crores as against previous outlay of Rs.1,163 crores. Reduction of Rs.425 crores for the outlay of anganwadis. Sir, I will conclude in one minute. On the night of 24th March, the hon. Prime Minister, without consulting any of the States, suddenly announced a lockdown, pushing tens of thousands of daily wage migrant workers get stranded on the roads of cities, which they helped to build once. With the looming fear of hunger, men, women and children travelled hundreds of kilometres on barefoot to reach their homes. Infants and pregnant women suffered the most. Hundreds of them lost their lives during the tough journey. All States were stunned due to the sudden announcement of lockdown, with people groping in the dark. No help was forthcoming from the Centre. The Finance Minister has now announced 'One Nation One Ration Card' and a portal for migrant labourers, which is nothing but crocodile tears and is much too little, much too late. Sir, I would also like to urge upon the Finance Minister to reinstate the MPLADS fund. In Kerala, where I come from, and Tamil Nadu and Maharashtra, the MLAs have their Local Area Development Fund. In Kerala, it is Rs.5 crores. The MPs cannot help the local community and the local institutions without this Fund. I would like to conclude by saying that the Budget has no strategy for increasing revenues. With a poor track record in generating non-tax revenues, the

BJP Government's Budget makes several false and lofty promises for increased spending on infrastructure etc. with hardly anything at hand to spend. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shreyams Kumar*ji*. Ex-Prime Minister, H.D. Devegowda*ji*; he is not present. Now, Ashok Siddharth*ji*.

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपनी पार्टी की नेता, आदरणीय बहन जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया।

मान्यवर, किसी भी सरकार के बजट की अच्छाइयाँ और कमियाँ उसमें किए गए प्रावधानों से उजागर होती हैं और जिस तरह के प्रावधान इस बजट में हैं, इस देश के किसानों, मज़दूरों, बेरोजगारों, दलितों, आदिवासियों, नौकरी-पेशा मध्यम वर्ग, रेहड़ी-पटरी कारोबारी या सेना के जवानों तथा उनके परिवारों के बुझे चेहरे और नम आँखें इस बात को दर्शाती हैं कि इस देश की बहुसंख्यक अवाम के लिए इस आम बजट में कुछ खास नहीं है।

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले लगभग एक वर्ष से कोरोना महामारी से उत्पन्न हालात ने भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुँचाया है, जिसके कारण मंदी की मार झेल रहा देश महामंदी की गिरफ्त में आ गया है। ऐसे में भारत की 130 करोड़ जनता यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि सरकार बजट में कुछ ऐसे कदम उठाएगी, जो राहत पहुँचाने वाले होंगे, लेकिन बजट में ऐसे उपाय नदारद हैं, जो लम्बे समय से आर्थिक मार झेल रहे लोगों के लिए मरहम का काम कर सकते। मान्यवर, इस बजट ने देश के लोगों को, खासकर गरीबों, कामकाजी तबकों, मज़दूरों, किसानों या स्थायी रूप से बंद हुई औद्योगिक इकाइयों से हुए बेरोजगार लोगों को निराश करने का काम किया है।

माननीय उपसभापति महोदय, जब बजट लोक सभा में पेश होता है, तो हर समाज, हर तबके, हर वर्ग के लोग उत्सुकता के साथ उसमें अपने और अपने समाज के बारे में सोचने का काम करते हैं कि उनके लिए क्या-क्या है। मैंने इस बजट स्पीच को बहुत गंभीरता और ध्यान से पढ़ने का काम किया है और मुझे भी इसमें निराशा हाथ लगी है। मान्यवर, सरकार ने जिस आक्रामक तेवर को अपनाते हुए नीति आयोग को भी निवेश के लिए नई कंपनियों को सूचीबद्ध करने एवं सरकारी संपत्तियों को मुद्रित करने के लिए कहा है, वह इस बात को दर्शाता है कि यह सरकार गरीबों को और गरीब तथा अमीरों को और अमीर बनाना चाहती है। यदि ऐसा न होता तो सरकार ने बजट में विनिवेश के माध्यम से इस वर्ष भी पिछले वर्ष के 2 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 1.75 हज़ार करोड़ रुपये जुटाने के लिए सरकारी उपक्रम, जैसे Air India, Shipping Corporation of India, Bharat Earth Movers Limited, BPCL, Container Corporation of India, BEML, Pawan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, IDBI bank के अलावा दो सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण करने का जो प्रस्ताव रखा है वह न होता। महोदय, प्राइवेट कंपनियों को बिजली वितरण के लिए भी आह्वान किया गया है, Central

Warehousing Corporation को किराए पर देने या बेचने की बात कही गई है, माल-भाड़ा ढोने वाली रेल गाड़ी या corridor बनाने का काम, उसको भी प्राइवेट करने का काम किया गया है।

मान्यवर, घाटे को पूरा करने के लिए पैसे जुटाना सरकार की मजबूरी है, लेकिन उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, खास तौर से दलित, शोषित और पिछड़ों की हिस्सेदारी पर डाका डालना किसी प्रकार उचित नहीं है। हमारे जो उद्योग नवरत्न कहलाते थे, वे फायदे में चल रहे थे, चाहे BPCL हो, CONCOR हो, फायदे में चलने वाले उद्योगों को, HPCL की पाइपलाइन हो, GAIL की पाइपलाइन हो, इन सबको आप जब प्राइवेट सेक्टर में देंगे, तो स्पष्ट है और सरकार इस बात को जानती है कि इस देश में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है और जब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है तो बड़े पैमाने पर इसमें लाखों की संख्या में SC, ST और OBC के लोग, जिनको आरक्षण का लाभ मिलता था, क्या सरकार उस आरक्षण को देने का काम करेगी या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए कोई संशोधन लाने का काम करेगी? अगर सरकार की नीयत साफ हो तो उन्हें उत्तर प्रदेश की वर्ष 2007-2012 की सरकार में हमारी पार्टी की मुख्य मंत्री परम आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी से उदाहरण लेना चाहिए, जिन्होंने अपनी सरकार में प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशन करने का काम किया और न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशन करने का काम किया, बल्कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी रिज़र्वेशन देने का काम किया। यह सरकार भले ही पैसे जुटाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि पहले प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशन लाए, जिससे SC वर्ग की लगभग 25 परसेंट आबादी और ओबीसी वर्ग की लगभग 52 परसेंट आबादी को लाभ पहुंचे। भारत के संविधान में बाबासाहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस आरक्षण की व्यवस्था की थी, उस आरक्षण को आज तक आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी किसी सरकार ने, चाहे पहले यूपीए की सरकार रही हो या वर्तमान में एनडीए की सरकार जब भी आयी है, तब इन्होंने निजीकरण को फायदा पहुंचाने का काम किया है। निजीकरण से स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा नुकसान SC, ST और OBC के उन लोगों का होता है, जिनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है।

मान्यवर, सरकार ने जिस तरह से अपनी नीयत को साफ किए बिना इन लोगों को देने का काम किया है।

श्री उपसभापति : माननीय अशोक सिद्धार्थ जी, आप conclude कीजिए।

श्री अशोक सिद्धार्थ : महोदय, अभी चार मिनट हुए हैं।

श्री उपसभापति : आप अपनी बात पूरी करें, आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री अशोक सिद्धार्थ : महोदय, मंत्रीगण पूरे देश में ढिंढोरा पीटते घूम रहे हैं कि उन्होंने इस बजट में अनुसूचित जाति के लिए 1 लाख 26 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान रखा, जो 51 परसेंट से ज्यादा है, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि नीति आयोग के अनुसार अनुसूचित जाति के सब-प्लान में यह स्पष्ट कहा गया है कि इनके समग्र विकास के लिए इन समूहों की जनसंख्या के अनुपात में भारत सरकार को बजट का निर्धारण करना चाहिए। अगर हम

34.8 लाख करोड़ के बजट में हिस्सेदारी देखें, तो लगभग 6.5 लाख करोड़ की बनती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार एससी, एसटी के लिए बजट में उनकी आबादी में हिसाब से हिस्सेदारी देने का काम करे।

मान्यवर, सरकार ने दलित छात्रों की शिक्षा हेतु भी पोस्ट मैट्रिक के लिए 3,416 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, मेरा सरकार से निवेदन है कि 6 साल में 35,200 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।

श्री उपसभापति : माननीय अशोक सिद्धार्थ जी, आप conclude कीजिए।

श्री अशोक सिद्धार्थ : महोदय, उस प्रावधान में से अगर हम 6 वर्षों में बराबर बांटे, तो भी 5 हज़ार करोड़ रुपये बनते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है...(**व्यवधान**)...मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की तकरीरें हुईं, चुनौतियां देने का काम किया गया, मंडियां खत्म करने की बात की गई, मैं इन चार लाइनों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा।

श्री उपसभापति : माननीय अशोक सिद्धार्थ जी, आपका समय बहुत पहले पूरा हो चुका है ।

श्री अशोक सिद्धार्थ : महोदय, 10 सेकंड दे दीजिए। मैं चार लाइनों से साथ अपनी बात समाप्त करूंगा:-

"नीम के रस में मिला ज़हर तो मीठा हो गया,
झूठ उसने इस कदर बोला कि सच्चा हो गया,
इतना उजला था लिबास-ए-लफ़्ज़ उस तकरीर का,
लोग थोड़ी देर को समझे कि सवेरा हो गया।"

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, in one of his very famous writings, Karl Marx wrote, 'at a higher stage of capitalist development, the Government will become an executive committee of the bourgeois.' I repeat, 'at a higher stage of capitalist development, the Government will become an executive committee of the bourgeois.' Exactly, that is what is happening today in the country. The Government speaks a lot about the poor, about the peasants, about the unemployed, no dearth of words. Naturally, the Government is serving the interest of the big capital in the country and outside the country too. The Budget speaks voluminously about that. Sir, hence this Budget can be called as a Budget of the Government which in the name of Atmanirbhar Bharat is wholly, surely and very clearly serving all the greed of the capitalists inside the country and outside the country. So, this Budget is a Budget driven by FDI. This Government always talks about Swadeshi and that Swadeshi gave a shape to the Atmanirbhar Bharat. I would like to ask my friends in the BJP if this is the model of the Atmanirbhar Bharat. You

surrendered all the vitals of the economy to the FDI, everything, everything. In the name of COVID a series of packages you proclaimed. What have you done actually? You surrendered the heart and soul of India before the FDI. Sir, the banks for the FDI, the insurance for the FDI, the port for the FDI, airports for the FDI, the mines for the FDI, the sky, the earth and *bhumi, akasham, patalam, yellam FDI*. This Government can be called as a Government of the FDI, the foreign capital. I request the Minister and the friends in the BJP please don't try to cheat the people. Tell the people who you are and what you are. It is high time the people understood this. Sir, the pandemic of the day shook the whole world. It taught lessons also to the world. It brought a lesson with that. The market model, it fails everywhere, everywhere, including America it fails. When the people were starving to death, without medicines even, even in the US, the haven of the capitalism, the Government was helpless. People were dying. There is no need to tell about that. That model is a failed model. But, this Government is blindly following it in this Budget also. Sir, the Government claims, the FM claims that there is an increase of 137 per cent for the health sector. Is it true? You put together sanitation, nutrition and everything in the one basket and tell that there is a big increase of great 137 per cent. And true it is! Sir, Rs.71,268 crores were given to the Health and Family Welfare. The Revised Estimate for the previous year, 2020-21, was Rs.78,866 crores. In fact, there is a decrease of 10 per cent. In the days of the pandemic, in the days of Covid, the Budget of Government of India led by the BJP, has a decrease of 9 per cent! This is what I researched in the documents. You may claim. The Economic Survey also suggested an expenditure of at least 2.5 to 3 per cent on the health sector. How much percentage have you allocated? I request the Government, the Minister, to just inform the House as to the percentage you have spent on the health sector during these days. Also, inform this House what the secrets behind putting everything and to project a figure of 137 per cent increase, are; myth! I feel very sorry about this, Sir. ...(*Interruptions*)...

Sir, on employment, how much did you spend? On MNREGA, the Budget promised was Rs.73,000 crore. The previous year, it was Rs.1.1 lakh crore. In fact, it is 34 per cent less. And you say that you are for creating employment opportunities! You are destroying the rural economy. You are cheating the rural poor. You are killing one of the greatest schemes of the country, called MNREGA. That is what is happening here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now. Your time is up.

SHRI BINOY VISWAM: In the banking sector, what a gimmick you have done! A new type of banks, called 'Bad Banks', are being created. It is a Government of bad banks, a Government of bad economy, a Government of bad economists and a Government of bad governance!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, please conclude. I will be calling the other speaker now. Your time is already up. Please conclude. The time is not in my hands.

SHRI BINOY VISWAM: A bad bank is meant for whom? It is for the bad loans. Who are the creators of bad loans? Who are they? All the NPA holders are their friends, Sir!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Binoyji.

SHRI BINOY VISWAM: The bank employees are on the path of a strike. On 16th of March, they will be on strike.

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): माननीय उपसभापति महोदय, जब पूरा देश जीएसटी, नोटबंदी और कुछ गलत नीतियों की वजह से एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उसी वक्त पर कोरोना की महामारी ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था, जिससे बहुत लोग बरबाद हो गए हैं। एक उम्मीद की किरण जागी थी कि भारत सरकार का बजट आएगा, तो हमारे लिए कुछ सुनहरा चांद खिल जाएगा। मुझे कहना होगा कि यह सरकार देशवासियों की उम्मीदों को धूमिल कर देने वाला बजट लेकर आई है। सर, कमाई करो, उस पर टैक्स भरो और खर्च करो, तो उसके ऊपर भी टैक्स भरो, ऐसा कहने वाला बजट यह सरकार लेकर आई है।

माननीय उपसभापति महोदय, एक ही मां के दो बच्चे होते हैं। एक छोटा बेटा होता है और दूसरा उम्र में बड़ा मज़बूत बेटा होता है। दोनों बेटे अपने होते हुए मां छोटे बेटे को गोद में बैठाकर खिलाती है और अगर बड़े बेटे के पास ज्यादा है, तो उससे लेकर छोटे बेटे को दे देती है। मां छोटे बेटे को यह नहीं कहती है कि आत्मनिर्भर बन जा, आत्मनिर्भर बन जा, तेरी सुरक्षा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यहां तो उलटा हुआ है। कमज़ोर लोगों को कहते हैं, गरीब लोगों को कहते हैं, मिडिल क्लास को कहते हैं और government employees को कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन जाओ और बड़े-बड़े दोस्तों को कहते हैं कि मेरा संरक्षण है। मित्रो, चिंता मत करना, मैं हूं न! ऐसी परिस्थिति वाला यह बजट आया है। माननीय उपसभापति महोदय, जो पार्टी आज पावर में है, वह यहां पर Opposition में भी थी। वे बार-बार कहते थे, our country is a developing country, लोगों की आय बढ़ती है, तो इन्कम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए और कम से कम 10 लाख हो जाना चाहिए। आपने उस स्लैब में कोई बढ़ोतरी नहीं की, आपने 80सी में कोई बढ़ोतरी नहीं की। हां, आपने कुछ-कुछ किया। वह कैसा किया - जैसे इंटरनेट पर देखते हैं, तो कहीं-कहीं बहुत attractive proposal लगता है, चलो इसको खरीद लो, बहुत बढ़िया है, पर फिर उसमें धीरे से

लिखा होता है कि "T&C apply", terms and conditions apply और जब उन terms and conditions में जाओगे, तो पाओगे कि यहां तो ठगे गए हो, कुछ मिलेगा नहीं। इस बजट में भी ऐसा है। लफ्ज़ है, senior citizen. Senior citizen तो 60 साल में हो जाता है। ये नई definition लेकर आए - 75 साल। जोर-जोर से कहा गया कि उसको टैक्स नहीं भरना होगा, रिटर्न नहीं भरना होगा और फिर terms and conditions आईं कि जो pensioners हैं और जिनकी सिर्फ इन्टरेस्ट की इन्कम है, वही, बाकी तो 80 साल के बूढ़े की वही की वही हालत है। यह इस बजट की असलियत है। भावनगर में शिप ब्रेकिंग यार्ड है। आप शिप ब्रेकिंग को डबल करने की बात करते हो। आप पांच साल का average देखो। 55-75 plots ही operational हैं, क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसी बीच में आ गई। बाहर से scrap आता है, आप उसकी ड्यूटी ज़ीरो करते हो और जहां पर जो इंडस्ट्री employment generate करती है, उस शिप ब्रेकिंग पर आप ढाई प्रतिशत ड्यूटी लगाते हो। यह कैसे चलेगा? वहां पर re-rolling mills चल रही हैं। वे बहुत अच्छी चलती थीं, अभी वहां पर आपका एक आदेश आया, Steel Products Quality Control Order, उसकी वजह से शिप का जो स्क्रैप निकलता है, वहां से आप steel bars नहीं बना सकते हैं। मैं कहता हूं कि क्वॉलिटी जरूर मेन्टेन करें, किंतु 20 mm तक के स्टील बार बनाने के लिए इसमें मंजूरी मिल जानी चाहिए। इस बजट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूती कपड़े, सिल्क, प्लास्टिक, लेदर, ऊर्जा उपकरण, कपड़े, एलईडी बल्ब, फ्रिज, एसी आप सब कुछ महंगा करने जा रहे हैं। यह सब महंगा होगा, उसके ऊपर आपके टैक्स का डंडा पड़ रहा है।

*[**उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा)** पीठासीन हुए]*

हम सब यहां पर स्टेट्स को represent करते हैं, हम राज्य सभा के मेम्बर्स हैं, स्टेट के इन्टरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की हमारी जिम्मेवारी है। यह सरकार क्या कर रही है? 14वें वित्त आयोग ने कहा है कि भारत सरकार जो भी टैक्स लेगी, 40 परसेंट स्टेट को देना पड़ेगा। यह सरकार टैक्स की बजाय सेस लेने जा रही है। इसलिए कि सेस से पैसा आएगा, उसका हिस्सा राज्य सरकार को नहीं देना पड़ेगा। यह जो पॉलिसी अपनाई है, मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय महोदय, मैं यह जरूर कहूंगा कि वित्त मंत्री जी तो बहुत शालीन हैं, बहुत अच्छी हैं, वे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, जेएनयू, जिसको आजकल ये लोग देशद्रोहियों का अड्डा कहते हैं, वहां से बड़े-बड़े अच्छे लोग निकले हैं। इस बजट में दिक्कतें हैं, इसमें वित्त मंत्री का दोष नहीं है। जिस कैबिनेट में मंत्री अपना पीए या पीएस नियुक्त करने में आत्मनिर्भर नहीं हो, वह बजट आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, तो उसमें मैं वित्त मंत्री जी का दोष नहीं मानता हूं। उन्होंने तो उसी जेएनयू में से जीवनसाथी भी पसंद किया और वे जीवनसाथी हैं, जिनके संस्कार और background सारे कांग्रेस के खानदान के रहे हैं। उन्हें ऐसा जीवनसाथी भी जेएनयू से मिला है। महोदय, मैं कहूंगा कि अभी खेल के पैसे काटे हैं। मैं वित्त राज्य मंत्री जी को आपके जरिए कहना चाहूंगा कि ज़रा कभी-कभी वह ठाकुरपन अपने में भी दिखाओ, आप तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। वे पैसे काट रहे हैं, तो उधर भी थोड़ा ठाकुरपन दिखाना पड़ेगा। कभी-कभी अंदर वालों को भी वह दिखाना जरूरी होता है।

माननीय महोदय, यहां पर कहा गया कि मंडी बंद नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि क्यों बंद होगी। एक काला कानून आने की वजह से जो एपीएमसीज़ चलती हैं, वे किसके ऊपर चलती

हैं, आप कहीं पर भी सामान बेचो, एपीएमसी का टैक्स भरना पड़ता है। इससे मंडी चलती है। आप इस काले कानून में लाए हो - ऑनलाइन और मंडी के बाहर भी सामान बेचेगा, APMC का सेस उसको नहीं मिलेगा - आप मुझे बताओ कि APMC कैसे जिंदा रहेगी, जिसके पास और कोई चारा ही नहीं है। एक किसान को मत समझो आप - वह कुदरत का दिमाग भी पहचान लेता है, तो तुम्हारा काला कानून कैसे भूल पाएगा, वह जरूर पहचान लेता है। यह मत कहो कि उसने कानून को समझा नहीं है। यह कहो कि हमारे कानूनों को किसान अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसलिए वे आंदोलित हुए हैं, इसलिए वे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वे आपके खिलाफ लड़ रहे हैं।

महोदय, इसका जिक्र हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट टीम जीतकर आई। हमें भी खुशी है, इतिहास रच दिया, हमारी क्रिकेट टीम को बहुत-बहुत बधाई, परन्तु ट्वीट करने वाले और बजट में रखने वाले वही नेता इतना बोल देते कि वह क्रिकेट टीम इतिहास इसलिए रचकर आई क्योंकि बेस्ट परफॉर्मर चार हिन्दुस्तानी क्रिकेटर्स में एक सिख था, एक मुसलमान था, एक हिन्दू था और चौथा ईसाई था। ये एक-साथ टीम बनकर लड़े थे, तब हम जीतकर आए थे और जिसको ये तोड़ने की बात करते हैं ...(**व्यवधान**).... इन दिलों को जो तोड़ने की बात करते हैं, उनको यह समझना होगा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: ये सब हिन्दुस्तानी हैं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please maintain silence. ...(Interruptions)...Please maintain silence. ...(Interruptions)...Please maintain silence. अनुराग जी, आप बैठ जाइए। जया जी, आप बैठ जाइए। ....(**व्यवधान**)... अनुराग जी, आप बैठ जाइए। ....(**व्यवधान**)...

श्री शक्तिसिंह गोहिल: उपसभाध्यक्ष महोदय, जब सच कहा जाता है, तो मिर्ची लगती है।...(**व्यवधान**)...महोदय, सच सुनने की तैयारी रखनी चाहिए। हमने भी मंत्री जी को सुना था। ....(**व्यवधान**)... थोड़ी-थोड़ी मिर्ची लगती है और वह जरूरी है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): गोहिल जी की बात रिकॉर्ड पर जा रही है। Nothing else is going on record. Please, let us maintain decorum.

श्री शक्तिसिंह गोहिल: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने इसी हाउस में सुना कि सच सुनने की तैयारी रखनी चाहिए। सच सुनने से मोक्ष मिलता है, तो मैं उसी लाइन को दोहराते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष महोदय, 2011 में आज के प्रधान मंत्री गुजरात के मुख्य मंत्री थे। डा. मनमोहन सिंह जी निष्ठावान, प्रामाणिक आदमी हैं, वे यहां बैठे हैं, वे उस समय प्रधान मंत्री थे। उन्होंने विरोधी दल के एक चीफ मिनिस्टर को कमेटी की जिम्मेदारी दी और उस कमेटी ने 2011 में एक रिपोर्ट सब्मिट की और उसमें लिखा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून नहीं बनेगा, तो किसान को फायदा नहीं है - MSP कानून होना चाहिए, यह मोदी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कहा था । आज आप उस बात को भूल गए और आप डा. मनमोहन सिंह जी को

क्वोट करते हैं, आप शरद पवार जी को क्वोट करते हैं, out of context क्वोट करते है! उनकी सही बात मानो तो उन्होंने कहा था कि जरूर ये चीज़ होगी, परन्तु उसके साथ-साथ किसानों की सुरक्षा वाले कानून की बात थी, उसमें से दो प्वाइंट उठाकर कांग्रेस के मेनिफेस्टो की बात करो, तो उसमें भी हमने किसान की सुरक्षा पूरी तरह से रखी थी। मेरी पार्टी के साथी को ज्यादा टाइम मिले, इसलिए मैं लम्बी बात नहीं करते हुए, आखिरी चार पंक्तियां बोलकर, मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मेरा बचा हुआ वक्त मेरी पार्टी के साथी को मिले, इसलिए मैं छोड़ता हूं।

"किसान अपने ढेरों दुखों का दुखड़ा,
सरकार आपके द्वार फोड़ता है,
मजदूर अभी भी पत्थर तोड़ता है,
पूंजीपति आपके साथ दौड़ता है, मज़े करता है,
रह गये वो जो मेरे भारत का नारा लगाते हैं,
रह गए वो जो कहते हैं "जय जवान-जय किसान",
उसे आप कहते हो तेरे लिए कुछ नहीं,
तुम तो दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ,
आत्मनिर्भर इनके पाले नहीं पड़ता।"

धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष: श्री भूपेन्द्र यादव जी।

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान)**:** सम्माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक संजोग है कि पिछले वर्ष, जब बजट आया और सरकार ने इसको संसद में प्रस्तुत किया, तब उसके तुरंत बाद ही देश में लॉकडाउन लागू हुआ और हम एक वैश्विक महामारी के संकट में उलझ गए। हम पूरे एक वर्ष एक चुनौती से उलझे रहे, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने न केवल इस संकट से निर्मित लड़ाई को जीता, बल्कि देश के लिए आत्मनिर्भर भारत की नई संभावनाओं के द्वार भी खोले। हमने आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद खड़ी की, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में भी वे देश के लिए आशाओं का एक बजट लेकर आए हैं, जो आज सदन में हमारे सामने चर्चा के लिए प्रस्तुत है।

उपसभाध्यक्ष जी, जब हम पूरे एक वर्ष के कोविड संकट के समय पर विचार करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ रहीं, जिनका समाधान इस बजट को देखने और इस सरकार की दृष्टि को देखने में नज़र आता है। जो पहली चुनौती रही, वह कोविड-19 से अचानक पैदा हुए ठहराव से जीवन और जीवनयापन की चुनौती थी। लॉकडाउन लागू होने के 48 घंटे के अंदर ही - जब तक लॉकडाउन चला, तब तक देश के 80 करोड़ लोगों को, चाहे मुफ्त राशन पहुंचाना हो, चाहे देश की 8 करोड़ महिलाओं को "उज्ज्वला" की सब्सिडी और गैस पहुंचानी हो, चाहे देश के 40 करोड़ किसानों, महिलाओं, बुज़ुर्गों, गरीबों, जरूरतमंद लोगों को सीधे नगद धनराशि उपलब्ध करानी हो, यह सरकार "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" के माध्यम से उनमें कामयाब रही है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के इस कार्यकाल में

"आत्मनिर्भर भारत" के पैकेज - 1.0, 2.0, 3.0 में रिज़र्व बैंक द्वारा जो उपाय किए गए, यह सरकार देश के कुल वित्तीय प्रभाव के 27.1 लाख करोड़ रुपये, जो हमारी जीडीपी के 13 परसेंट होते हैं, उनको देने में कामयाब रही है।

महोदय, कोविड-19 के बाद जो दूसरी बड़ी चुनौती रही, वह स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा है। हम सब जानते हैं कि जान है तो जहान है। आप दुनिया में जीडीपी को तो वापस रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को वापस रिकवर नहीं कर सकते। हम लोग न केवल स्वास्थ्य के संकट से उबरे हैं, बल्कि हमने इस क्षेत्र में एक नई दिशा और पहल भी की है। महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137 प्रतिशत बजट की बढ़ोतरी की गई है। इसमें 2 लाख, 38 हज़ार करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि 1946 की भोरे कमेटी की स्वास्थ्य की जो सिफारिशें थीं, उनके आधार पर आप देश को 50-60 साल तक तीन स्तर की मेडिकल सुविधाओं के साथ चलाते रहे, लेकिन यह जो आप पूरे 50-60 साल तक स्वास्थ्य के क्षेत्र को चलाते रहे, उससे वास्तव में यह स्थिति उत्पन्न हुई कि देश की जो तीन-चौथाई आबादी रही, वह out of pocket health expenditure पर चली गई। हम health को नीचे तक, जहाँ तक लोगों को पहुंचाना था, वहाँ तक पहुंचाने की सुविधा नहीं दे पाए। सरकार में आने के बाद "आयुष्मान् भारत योजना" को, "नेशनल हेल्थ मिशन" को आगे बढ़ाया गया। इस बजट के द्वारा हेल्थ में अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ की गई, तो वह स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंतर्गत केवल curative नहीं, बल्कि जो preventive and reformative steps हैं, जो देश के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, उनको भी इस बजट में शामिल किया गया।

महोदय, राम गोपाल जी जो यहाँ कह रहे थे और जयराम जी का भी जो इशारा था वह यही था - किस प्रकार से? आज तक Public Policy में जो health का issue है, उसमें जो public goods हैं, जब मैं बात करता हूँ preventive की, जब मैं बात करता हूँ reformative की, तो preventive का अर्थ है कि एक सामान्य व्यक्ति की यह ताकत नहीं होती कि वह air pollution को, कचरे को, हवा को, साफ पानी को, जो कि किसी भी देश की स्वास्थ्य की पॉलिसी की बुनियाद है, उसको कोई individual व्यक्ति किसी प्रकार से control नहीं कर सकता। वह हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसलिए बजट में हमने 137 परसेंट स्वास्थ्य में खर्च किया है, तो वह स्वास्थ्य के साथ wellness भी है। इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं में इस देश की health और wellness को मिला कर सरकार ने जो बजट को आगे बढ़ाने का काम किया है, इससे मुझे लगता है कि बजट ने यह बुनियाद रखी है कि आने वाले समय की हमारी Public Policy में health में public goods को सुधारने का जो काम है, उस तरफ इस सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कभी-कभी हम एक अच्छे वकील होने के नाते आँकड़ों को इस प्रकार से पढ़ देते हैं कि कई बार ऐसा लगने लगता है कि हम एक अच्छे विषय को भी इस प्रकार से आँकड़ों में घेरते हैं कि हमें लगता है कि हम लोग किसी विषय के प्रति भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। कल चिदम्बरम साहब बोल रहे थे, मैं उनके एक विषय को यहाँ quote करना चाहूँगा। For health, in the current year, the Revised Estimate is Rs.82,445 crores and for the next year, it is only Rs.74,602 crores. अगर आप आँकड़ों को देखेंगे और निश्चित रूप से अगर expenditure के major items को देखेंगे, तो यह दिखता है कि जो संशोधित अनुमान है, Revised Estimate है, वह 82,445 करोड़ है, पर सरकार ने पिछली बार जो बजट अनुमान रखा था, वह 67,484 करोड़ था। उसके बाद हम

pandemic में गए और उसमें जाने के बाद जो health में extra खर्च करना था, वह खर्च सरकार ने किया और अब सरकार ने वह जो 67 हजार करोड़ पिछली बार रखा था, उसको बढ़ा कर 74,602 करोड़ किया है। Actual में हम यह नहीं मान सकते कि यह pandemic लंबी रहेगी, चलती रहेगी। आज देश में कोरोना के आने के बाद चाहे वेंटिलेटर्स की संख्या हो, चाहे tests की laboratories की संख्या हो, चाहे testing facility का विषय हो, हमने सबको बढ़ाया है। अब हम general condition में जाने लगे हैं। सरकार ने 35 हजार करोड़ अलग से टीकाकरण के लिए रखा है। इसलिए आँकड़ों को इस प्रकार से पढ़ देना और यह कह देना कि सरकार ने health expenditure में पैसा कम कर दिया है, मुझे लगता है कि यह एक किस्म से बौद्धिक ईमानदारी नहीं है।

महोदय, इस पूरे कोरोना के काल में जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती रही और जिसको लेकर बजट में सरकार एक नई नीति के साथ आई है, हम सब जानते हैं कि कोरोना में health के क्षेत्र में जो एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, वह यह है कि infrastructure पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कामगारों के लिए रोजगार का विषय, वह एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के 1.0, 2.0 और 3.0 पैकेज से आगे बढ़ कर सरकार ने बजट में 5.4 लाख करोड़ का पैकेज देकर 37 परसेंट की वृद्धि की है। इससे देश में आशा और विश्वास का वातावरण बना है।

महोदय, सरकार के सामने जो चौथा सबसे बड़ा संकट था, जिसका समाधान बजट में सरकार अपने इस दृष्टि-पत्र में लेकर आई है, वह देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना है। MSME से जुड़े कारोबारियों को नई ताकत प्रदान करना और मजदूरों का संरक्षण करना, यह सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। हम जानते हैं कि इस पूरे कार्यकाल के दौरान सरकार Four Labour Codes लेकर आई। हम लोगों के देश में लगभग 20 वर्षों से यह माँग चल रही थी कि Labour Codes का सरलीकरण किया जाए। मजदूरों के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे विषय थे, उनमें सभी को सामाजिक सुरक्षा देने का विषय था, महिला-पुरुष को समान वेतन देने का विषय था, महिलाओं को रात्रि की पाली में भी काम करने का अवसर देना था, single registration का सिस्टम करना था, लाइसेंस में सरलीकरण करना था, रिटर्न ऑनलाइन करना था। आज जो हम चारों Labour Codes लेकर आए हैं, चाहे वह Industrial Relation का हो, चाहे वह Occupational Safety का हो, चाहे वह Social Security का हो, चाहे वह Payment of Wages का हो ... इन चारों Labour Codes के माध्यम से कामगारों को संरक्षण देने के साथ-साथ देश के औद्योगिक वातावरण को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। व्यापार के क्षेत्र में छोटे करदाताओं को मुकदमेबाज़ी से बचाने के लिए इस बजट में कर विभाग की एक समिति का अच्छा प्रपोज़ल आया है। सरकार ने Faceless ITAT का गठन किया और साथ ही 75 साल से ऊपर के लोगों को करों में रियायत की सुविधा दी। आवास बनाने के लिए गरीब लोगों को किफायती आवास परियोजनाओं में इस सरकार में विशेष exemption दिया गया है। 2022 तक हर परिवार को छत देने का जो संकल्प हमने लिया है, उसको पूरा करने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया है। इसके साथ ही साथ दुनिया भर से भारत में निवेश आए, इसके लिए 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र' के निवेश को सरकार ने छूट दी है। इस बजट में सरकार ने Company Law का criminalization रोकने के माध्यम से 'Ease of Doing Business' को आगे बढ़ाने का काम किया है।

महोदय, पाँचवीं जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, वह है, हमारा बैंकिंग और विनिवेश। हमारे बिनोय विस्वम जी यहां पर पब्लिक सेक्टर का विषय रख रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश के पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में, जिसको हम Nehruvian model भी कहते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की क्या राय थी? दीपेन्द्र भाई, चौधरी साहब ने 1980 में एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था, 'Economic Nightmare of India – Its Cause and Cure'. उसमें चौधरी साहब ने public undertakings के लिए जो कहा है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा, "The poor performance of public sector enterprises is attributable to over-capitalization, delays in completion of major projects, under-utilization of capacity and, above all, to mismanagement and corruption." उन्होंने 1980 में आपको चेतावनी दी थी, लेकिन आपने 70 साल तक ये सफेद हाथी खड़े करके रखे। आगे उन्होंने जो कहा, वह भी मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा, "Had the public sector undertakings been private concerns, they would have, on the one hand, yielded a tax of hundred of crores per year to the Government, and, on the other, a profit of hundreds of crores to the proprietors or shareholders. On the contrary, the public has had to pay, and is even now paying crores of rupees to meet losses almost every year, in a way, in obeisance to these monuments of their Government's folly -- 'modern temples of India', as Jawaharhal Nehru once called them." ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let's keep silence in the House, please.

श्री भूपेन्द्र यादव : लम्बे समय तक हम लोग पब्लिक सेक्टर की उन यूनिट्स को ,जो यूनिट्स लगातार घाटे में जाती रहीं और जिन यूनिट्स के माध्यम से रोज़गार का सृजन तो नहीं हुआ , बल्कि उनके उस घाटे को सरकार बरदाश्त करती रही। किसानों की बात करने वाले और किसानों के विषय को रखने वाले इन लोगों ने कभी भी स्वयं किसान नेताओं की बातों को ध्यान से सुना ही नहीं। कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि चाहे लोहिया जी रहे हों ,चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हों ,चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हों ,भारत की जड़ों से जुड़े हुए इन लोगों की अच्छी बातों को आपने इग्नोर करने का काम किया है। आज इस सर्वस्पर्शी बजट को लाकर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन सब विषयों को छूने का काम किया है। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है। वित्त मंत्री जी ने *SEBI Act, Depositories Act, Securities Regulation Act और Government Securities Act में Single Securities Code* बनाने की जो बात कही है ,मुझे लगता है हम जो *'Minimum Government' और 'Maximum Governance'* की बात कहते हैं ,उस दिशा में यह एक बहुत मज़बूत कदम है। आज निवेश के लिए इन *Acts* को मिलाकर एक सरलीकृत *Code* बना कर बहुत बड़ा काम किया गया है।

महोदय ,हम सब जानते हैं कि *infrastructure sector* में जो *banking* का निवेश रहता है , उसमें कई बार *maturity mismatch* का प्रश्न आता है। इस सरकार ने *corporate bond market* में विश्वास पैदा करने के लिए स्थायी संस्थान बनाने का जो *framework* इस बजट में दिया है ,वह एक स्वागत योग्य कदम है। इस पूरे बजट के अंतर्गत भारत की जो सबसे मज़बूत रीढ़ है ,जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है ,भारत का कृषि क्षेत्र है ,उन सबको सर्वाधिक महत्व दिया है। ग्रामीण क्षेत्र की जो अवसंरचना है ,जो *infrastructure* है ,उसको सुधारने के लिए पिछले छ :साल में सरकार के द्वारा बहुत बड़े-बड़े कदम उठाए गए हैं।

चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में 'प्रधानमंत्री सड़क योजना' को पहुंचाने का विषय हो, चाहे हर गांव को बिजली पहुंचाने का विषय हो, चाहे हर गांव में पक्के मकान देने का विषय हो, चाहे हर गांव तक 'उज्ज्वला योजना' पहुंचाने का विषय हो, यह सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने में कामयाब रही है। इसलिए इस बजट के अंतर्गत भी जो 'माइक्रो सिंचाई परियोजना' है, कृषि ऋण के लिए जो 16.5 लाख करोड़ रुपये सरकार के द्वारा रखे गये हैं, किसानों की 'फसल बीमा योजना' है और पूर्व में सरकार के द्वारा जो 'किसान सम्मान निधि' को लागू करने का काम किया है, इस बजट के द्वारा उन स्वागत योग्य विषयों को भी बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे डेयरी का विषय हो, मत्स्य पालन का विषय हो, पशुपालन का विषय हो या हॉर्टिकल्चर का विषय हो, सब विषयों का इस बजट के माध्यम से विशेष ध्यान रखा गया है।

महोदय, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए आज तीन सबसे बड़ी समस्याएं किसानों के सामने हैं। उनका उत्पादन बढ़े, उनका भंडारण बढ़े और उसका प्रसंस्करण हो, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, जिनमें आज किसानों को हमें एक नया कानून देने की आवश्यकता है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों तक हम इन्फ्रास्ट्रक्चर की सारी सुविधाओं को पहुंचाने के बाद यदि इन तीनों विषयों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो देश और गांवों में समृद्धि आ सकती है।

आज सरकार जो तीन कृषि बिल लेकर आई है, उनमें इन तीन विषयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एक नये जीवन की आशा का संचार हुआ है और इसलिए यह सरकार बड़े खुले मन के साथ आज किसानों के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार है, सरकार के द्वारा उन्हें आमंत्रण भी दिया गया है। सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाकर भारत की जो मज़बूत अर्थव्यवस्था है, उसे आगे बढ़ाने का काम किया गया है। इसलिए महोदय, मैं अपने विषय को समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगा कि इस बजट के माध्यम से, जो पांचों चुनौतियां कोरोना के माध्यम से हमारे सामने आईं, कोविड-19 के कारण जो जीवन में ठहराव आया, जो हैल्थ सेक्टर में चुनौतियां आईं, जो कारोबारियों को चुनौतियां आईं, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर में चुनौतियां आईं, जो बैंकिंग क्षेत्र में विनिवेश की जरूरत थी और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, उन सब आयामों को, सभी पक्षों को इस बजट में शामिल किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सभी विषयों को छुआ है और निश्चित रूप से यह बजट बताता है कि देश माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 'आत्मनिर्भर भारत' की तरफ बढ़ चुका है और हम 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे, जय हिन्द, जय भारत।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, we have the hon. former Prime Minister, hon. Member, Shri H.D. Devegowda. Sir, you have ten minutes.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Sir, there was some mistake committed by me. When the hon. Chairman called out my name, I had gone home. I do not wish to spell out the reason for which I went home. Despite the mistake committed by me, I have been permitted to speak, for which I am grateful to the Chair. Sir, I do not wish to encroach upon the time allotted and I would try my best to conclude my speech within the time given to me.

Sir, I would like to compliment the Government on the Budget presented for 2021. Madam Nirmala Sitharaman*ji* has done her best, along with her colleagues and senior officers, to find resources to deal with problems caused by the Covid-19 pandemic. It was one of the biggest blows to our country, though it has been managed well by the hon. Prime Minister to bring down the level of deaths in the country. It is one of the worst diseases to have hit the entire world. I do not wish to speak much on this issue and I come straight to the point.

Sir, one of the key takeaways of this Government's Budget post the battering received due to Covid-19 was in tackling a GDP that shrunk for the first time in two decades, highest unemployment levels in the last 50 years and a severely distressed banking sector. The Government has earmarked infrastructure and healthcare spending to spur economic activities.

MGNREGS, which proved to be one of the saving graces of our country's economy, creating employment through the pandemic, it is a surprise the Budget cuts this spending by 34.5 percent, especially when the economy is still reeling under the prevailing conditions. Additionally, the Government did little after axing the main safety net for rural India's employment, especially after failing to deliver on the May 2020 stimulus package. Overall, structural decline caused in India's economy since demonetization and the multi-decade high unemployment ratio cannot be reversed so quickly. CMIE data shows India is experiencing a substantial increase in employable workers opting out of the labour force. Labour participation ratio, which is the percentage of people looking for jobs in the total employable work force of about one billion, is now down to 44 per cent, whereas this ratio ranges from 60 per cent to 66 per cent in other comparable developing economies in East Asia. The lack of jobs is forcing urban migration from rural areas, and lack of affordability means these people end up squatting on Government land for decades.

Many of the Governments legitimized majority of these dwellings after

unsuccessful attempts. The Budget does not make a provision for such even after witnessing the rate of spread of COVID 19 in vulnerable areas. The Government should take initiatives to encourage slum rehabilitation both privately and within Government purview and make such an opportunity to seem like less of an onerous cost and more like a social impact investment opportunity.

The general direction of the Budget points to withdrawal of support from agriculture as a sector while a historic farmer movement is under way. The Budget slashed some major farm reforms such as PM-Kisan Yojana (a cash support scheme) and reduced interest subsidy on short-term crop loans, on the pretext of ensuring MSPs and infrastructure spending in the sector, which has seen an enormously sluggish rollout.

Undesirably, Market Intervention Scheme and Price Support Scheme (MIS-PSS) and Pradhan Mantri Annadata Aay Samrakshan Yojana (PM-AASHA), the two schemes that ensure the implementation of MSP, have seen a continuous reduction in the last 2 years. The funding for MIS-PSS was reduced to Rs. 1500 crores, half of funding available for 2019-20, and allocation for PM-AASHA came down to Rs. 400 crore from Rs. 1500 crore previously.

Certain private companies have outperformed their divestment targets. There is a definite 'need if not hope' this time around to pursue divestment objectives, as our country is in a tight spot fiscally. There are structural problems we need to overcome over the next few years. The IMF estimates that it will take up to 3 years to return to pre-COVID levels of output. There are many factors that contribute to stable economic growth but divisive social policy is certainly not one of them.

The move towards divesting ownership in strategic sectors will have long-term consequences and a potentially precarious one. Privatization does not always lead to greater competition in every case. So far, some of the public monopolies have become private monopolies.

The proposal to create an agricultural investment fund is a welcome step, but definite provisions for the agricultural investment should have been made.

The timing of the sale of public sector assets does not seem to be correct. The economy is not performing at its best and industrial asset prices are likely to be undervalued. Therefore, why should the Government, even if one assumes privatization is the best option, sell assets now? They should have waited until the economy recovered.

The major deficiency responsible for all the farmers' problems in India is the lack of data on how much to produce to meet country's domestic requirement of food and other farm produces, opportunity for storage, Value Addition Processing (VAP)

and export which needs constant revision. Our country has 127 Agro-climatic Zones and each zone is unique in terms of total annual rainfall, soil type, temperature, wind and other climatic features.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, I am concluding. I will take only one or two minutes. Undertaking farm enterprises, keeping Agro-climatic Zones in view, will help to realise increased productivity and also quality. Introduction of incentives and disincentives will regulate area and production over the period. This process will facilitate to provide assured price to all the farm produces and minimise huge wastages going on over the period. What is happening in sugarcane, tomato, onion, potato etc., over the years is mainly due to above factor.

Now, I will say only one word about Karnataka. Hon. Railway Minister has included Belur-Hassan-Chickmagalur. It is one of the loop lines to connect Mysore-Hassan railway line to Chickmagalur directly. In the Railway Pink Book, they have provided only Rs.1,000 for this project. I don't want to blame anyone. I know the financial situation, but I am only requesting about early completion of this one project about which I was struggling even in the other House. Provision is made in the Pink Book. I request the hon. Railway Minister, through you, Sir, to see that this project gets completed, at least, during my lifetime.

I could mention various things even on irrigation. The Upper Krishna Project has not been completed, though it was being funded by the Central Government during my regime and the Accelerated Irrigation Programme, which I had launched at that time. Sir, I demand, I request, I pray that the Upper Krishna Project should be taken over as a national project and the Government should see to it that it is completed as quickly as possible. With these words, I would like to express my sincerest thanks to the hon. Chairman. Thank you, Sir.

12.00 Noon

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Next speaker is Shri Sanjay Singh. Sanjay ji, you have seven minutes.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने मुझे बजट पर अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मान्यवर, मैं अपनी बात अदम गोंडवी जी की लाइनों से शुरू करना चाहूँगा -

"जो 'डलहौजी' न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे।
कमीशन दो तो हिन्दुस्तान को नीलाम कर देंगे।"

मान्यवर, यह बजट हिन्दुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इस देश की संपत्तियाँ किसी की निजी संपत्ति नहीं हैं, बल्कि इस देश की संपत्तियाँ हिन्दुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियाँ हैं। यह रेल, यह सेल, यह बीपीसीएल, यह एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं हैं, बल्कि हिन्दुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वे लोग सपूत कहलाते हैं, जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं और वे लोग कपूत कहलाते हैं, जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। सर, इस देश के अंदर कपूत सरकार चल रही है। ...(**व्यवधान**)... देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, इस सदन के अंदर देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया। ...(**व्यवधान**)... उन किसानों का, जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं। ...(**व्यवधान**)... 170 लोगों की शहादत हो चुकी है। ...(**व्यवधान**)... उनका आंदोलनजीवी कहकर मजाक उड़ाया गया। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, please keep silence.

श्री संजय सिंह : जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया, तो सत्ता में बैठे हुए सुन लीजिए, आपने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का मजाक उड़ाया। आपने सरदार वल्लभभाई पटेल का मजाक उड़ाया। ...(**व्यवधान**)... आपने डा. राममनोहर लोहिया जी का मजाक उड़ाया। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let us keep the decorum. Please keep silence.

श्री संजय सिंह : आपने शहीद-ए-आज़म भगत सिंह का मजाक उड़ाया। ...(**व्यवधान**)... आपने शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ाँ का मजाक उड़ाया। ...(**व्यवधान**)... आपने हिन्दुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिन्दुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया। ...(**व्यवधान**)... बाबासाहेब डा. भीमराव अम्बेडर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें यह संविधान दिया। ...(**व्यवधान**)... हमें यह लोकतंत्र दिया। ...(**व्यवधान**)... हमें यह संसद दी। ...(**व्यवधान**)... आपने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। ...(**व्यवधान**)... सत्ता में बैठे हुए लोगो, ज़रा सुनना सीखिए। ...(**व्यवधान**)... हमें फख्र है अपने उन क्रांतिकारियों पर, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों पर, अपने उन आंदोलनकारियों पर कि वे अंग्रेज़ों के दलाल नहीं थे। ...(**व्यवधान**)... वे अंग्रेज़ों से

माफी नहीं माँगते थे। ...(**व्यवधान**)... अंग्रेज़ों से दलाली नहीं करते थे। ...(**व्यवधान**)... अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करते थे। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let us keep the decorum. Please keep silence.

श्री संजय सिंह : और जिस विचारधारा के लोग अंग्रेज़ों की गुलामी करते हैं, अंग्रेज़ों की दलाली करते हैं, अंग्रेज़ों से माफी माँगते हैं, वे आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, 170 लोग अपने खेत के लिए मर गए। ...(**व्यवधान**)... 170 लोग अपने खेत को बचाने के लिए मर गए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : संजय जी की बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। Nothing else will go on record.

श्री संजय सिंह : उनकी जान चली गई। ...(**व्यवधान**)... उनकी शहादत हो गई और आप यहाँ उठकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें आंदोलनजीवी कह रहे हैं! ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया है। ...(**व्यवधान**)... सत्ता के लोगो, अपने कान खोलकर सुनो। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Nothing is going on record apart from what Sanjay ji is saying.

श्री संजय सिंह : आप पहले अपने कान खोलकर सुनिए। ...(**व्यवधान**)... यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया। चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी वहाँ पर बैठे हैं, जिन्हें आप खून के आंसू रुला रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप उन्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... वे भाषणजीवी नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sanjay ji, there is a point of order.

श्री संजय सिंह : वे भाषणजीवी नहीं हैं। वे जुमलाजीवी नहीं है। हाँ, वे आंदोलनजीवी हैं। ...(**व्यवधान**)... इस देश की जनता...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sanjay ji, there is a point of order. Sanjay ji, there is a point of order. I have to allow that. ...(*Interruptions*)... संजय जी, मुझे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर एलाउ करना है।...(व्यवधान)...

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, my point of order is under Rule 240. Rule 240 says that any Member, who speaks in a discussion should not speak irrelevant thing. Sir, this is a discussion on Budget. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंह : सर, यहाँ पर बंगाल हिंसा बोली गई।...(**व्यवधान**)... यहाँ पर बंगाल हिंसा बोली गई और ममता बनर्जी जी का नाम लिया गया। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sanjay ji, let him talk. उन्हें खत्म करने दीजिए। Sanjay ji, I will allow you to speak. उन्हें खत्म करने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह : कैसी बात कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... कैसी बात कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... इनको कैसे रोकना है? ...(**व्यवधान**)... यहाँ * चलेगी? ...(**व्यवधान**)... इन सदन के अंदर * चलेगी? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sanjay ji, I will allow you to speak. आप एक मिनट रुकिए। ...(**व्यवधान**)... संजय जी, वे खत्म कर दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह : यहाँ * चला रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, Rule 240 says that when an hon. Member speaks, he should not speak irrelevant things and things which are not related to the subject of discussion. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंह : यहाँ बंगाल हिंसा का नाम क्यों लिया गया? ...(व्यवधान)...यहाँ पर ममता बनर्जी का नाम कैसे लिया गया? ...(व्यवधान)...

SHRI V. MURALEEDHARAN: This discussion is on the Budget. ...(*Interruptions*)... This is related to some other discussion. So, the discussion should be on the Budget.

श्री संजय सिंह : सर, अब मैं किसान की बात करता हूँ।...(**व्यवधान**)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sanjay *ji*, Please continue....(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, what is this? He is not ...(*interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Jaya *ji*, please take your seat. ...(*Interruptions*)... I am allowing him to continue. ...(*Interruptions*)... Sanjay *ji*, please continue.

श्री संजय सिंह : सर, मुझे समझ में नहीं आता, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ - अंग्रेज़ों का दलाल, बुरा इनको लग जाता है। ये क्या है, सर? मैं कहता हूँ - अंग्रेज़ों से माफी माँगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूँ - अंग्रेज़ों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है, सर? क्यों बुरा लगता है? ...(**व्यवधान**)...सच को सुनो। मान्यवर, यहाँ पर ऑनरेबल मेम्बर, भूपेन्द्र जी के द्वारा कहा गया कि चौधरी चरण सिंह जी को याद कर लीजिए, डा. लोहिया को याद कर लीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sanjay *ji*, Please start concluding.

श्री संजय सिंह : हमको याद हैं - डा. लोहिया भी, चौधरी चरण सिंह जी भी, आप उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने आंदोलन से इस देश को आज़ाद कराया, हमें संविधान दिया, हमें संसद दी, हमें लोकतंत्र दिया, हमें यहाँ बोलने की आज़ादी दी। यहाँ पर प्रधान मंत्री जी अगर आए हैं, तो उन्हीं लोगों के बलिदान की बदौलत आए हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sanjay *ji*, please conclude. Your time is over.

श्री संजय सिंह : मैं अब कन्क्लूड कर रहा हूँ, सर। आप उनको इतना तो याद कर लो! इसीलिए बीएमएस, भारतीय मज़दूर संघ, जो आपका है। आपने चौधरी चरण सिंह को क्वोट किया, आप बीएमएस को पढ़िए, आप स्वदेशी जागरण मंच को पढ़िए। आपके संगठन खुद कहते हैं कि आप लोग देश को बेच रहे हो और क्या-क्या बेच रहे हो?

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : संजय जी, कन्क्लूड करें प्लीज़।

श्री संजय सिंह : रेल बेच रहे हो, SAIL बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, एलआईसी बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, एफसीआई बेच रहे

हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बीपीसीएल बेच रहे हो, पूरा हिन्दुस्तान बेच रहे हो। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sanjay*ji*, time is over. अब आप 30 सेकंड में कन्क्लूड करें।

श्री संजय सिंह : पूरा हिन्दुस्तान बेच दिया। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. I will have to move to the next speaker. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंह : सर, ये बोलने नहीं देते। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : संजय जी, आप कन्क्लूड करें।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह : वहाँ किसान को बोलने नहीं देते, यहाँ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने नहीं देते। यह सदन का अपमान है, सर। हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं। इन लोगों से ज्यादा राजनीति करके आए हैं, लाठी खाकर, जेल जाकर आए हैं। यहाँ * मत दिखाओ। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sanjay *ji*, please conclude. I will have to go to the next speaker.

श्री संजय सिंह : मैं खूब बोलूँगा और बार-बार बोलूँगा, धन्यवाद।

श्री मनसुख एल. मांडविया : *

श्री संजय सिंह : *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am not allowing anyone. Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)... Nothing is going on record. संजय जी, बैठें। ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी थैंक यू। श्री रामदास अठावले जी; नहीं हैं। श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार के लगभग सात वर्ष के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कथनी और करनी में इस सरकार का बड़ा अंतर रहा है

* Expunged as ordered by the Chair.

और यह बजट भी उस कथनी और करनी के अंतर को चरितार्थ करता है। 'आत्मनिर्भर भारत' की बात करने वालों ने skill development का बजट घटाने का काम किया है। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटाने का काम किया, तो 'न्यू इंडिया' की बात करने वाली सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है, तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया है। किसानों की आय दोगुनी करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है, तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया है। सर, कथनी और करनी में अंतर केवल इस बजट तक सीमित नहीं है। सात साल का कार्यकाल इसका गवाह है, बड़े-बड़े नारे दिए गए - नारा दिया था कि हर साल दो करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, सात साल में 14 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाना चाहिए था, मगर यही सरकार है जिसके कार्यकाल में 70 सालों में सबसे अधिक बेरोज़गारी की दर को सरकारी आंकड़ों के माध्यम से एनएसएसओ के सर्वे ने दिखाने का काम किया। आपने 70 साल का इकलौता बेरोज़गारी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा - 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी दर आपकी सरकार में हुई, 70 साल में सबसे ज्यादा डीज़ल-पेट्रोल आपकी सरकार में महंगा हुआ, 70 साल में डीज़ल-पेट्रोल पर सबसे ज्यादा टैक्स आपकी सरकार में लिया गया, क्योंकि पेट्रोलजीवी सरकार है। 70 साल में आपकी सरकार में डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे नीचे गिरा, सस्ता हुआ, 70 साल में एनपीए के माध्यम से बैंकों का सबसे ज्यादा कर्ज़ आपकी सरकार में डूबा और 70 साल में गरीब-अमीर के बीच में अंतर सबसे ज्यादा आपकी सरकार में बढ़ा। एक प्रतिशत सबसे अमीर व्यक्तियों के पास 73 प्रतिशत सम्पत्ति है। केवल कोरोना काल में 11 सबसे अमीर हिन्दुस्तानी उद्योगपतियों की सम्पत्ति में 13 लाख करोड़ रुपये का इज़ाफा हुआ। एमएसपी को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है, हरि दामोदरन जी का एक लेख आया कि केवल डेढ़ से दो लाख करोड़ रुपये में - क्योंकि जितना खरीदा जाएगा, उसमें से कुछ बेचा भी जाएगा, डेढ़ से दो लाख करोड़ रुपये के घाटे में एमएसपी पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। केवल कोरोना काल में हिन्दुस्तान के 11 सबसे अमीर व्यक्तियों की सम्पत्ति में जो 13 लाख करोड़ रुपये का इज़ाफा हुआ, उसी पर आप यदि टैक्स लगा दें तो आप किसान के लिए एमएसपी का काम पूरा कर सकते हैं।

मैं कृषि पर आऊंगा, मुझे उम्मीद थी कि यह बजट किसानों को समर्पित होगा, क्योंकि जब कोरोना काल में आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, तब किसान अपने हल को लेकर और ट्रैक्टर की स्टेयरिंग पकड़ कर निकला था और अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया था, उस समय किसानों ने अबाधित भोजन की व्यवस्था करने का काम किया था, लेकिन आपने कृषि बजट को ही घटाकर साढ़े आठ प्रतिशत कर दिया। कृषि कानून पर बड़ी चर्चा हुई। यह कहा गया कि हमने आंदोलन के बारे में बात की, लेकिन इन कानूनों में काला क्या है, यह हमें नहीं बताया गया। मैं दो-तीन बातें बताना चाहता हूं कि काला क्या है। आपने कहा कि 11 राउंड बातचीत हुई, लेकिन किसान संगठनों ने कुछ काला नहीं बताया। यह नज़रिये का फ़र्क है, आप इसको बड़े व्यवसायी के profit margin के नज़रिये से देखते हैं या आप इसको किसान के जीवन-मरण, जीविका के नज़रिये से देखते हैं? यह कहा गया कि बिन मांगे दिया गया। बिन मांगे बहुत से कानून दिए गए थे, बाल कानून बिन मांगे दिया गया था, दहेज कानून, ट्रिपल तलाक आदि कानून दिए गए थे, कई

बार अच्छे कानून बिन मांगे भी दिए जाते हैं, उनमें और इसमें फ़र्क यह है कि वे कानून जिन वर्गों के लिए दिए गए, वे वर्ग संघर्ष और आंदोलन के रास्ते पर नहीं आए। बाल कानून लागू हुआ तो दिल्ली को बच्चों ने नहीं घेरा कि बाल कानून वापस लिया जाए, दहेज का कानून आया तो महिलाएं धरने पर नहीं बैठीं कि हमें दहेज देना है, मगर यहां जिस वर्ग के लिए आप कानून लाए, वह वर्ग आज आपके दरवाज़े पर आकर दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में बैठा है। अनुराग जी ने कहा कि मंडियां खत्म नहीं हुईं। यह सही बात है, इसमें मंडी समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। महोदय, दो मंडियां बन गई हैं, उनमें से एक निजी मंडी है, जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी है, जिसमें टैक्स लगता है, दो मंडियां हैं। एक देश, एक विधान; एक देश, एक संविधान; एक देश, एक निशान; एक देश, एक चुनाव; एक देश, एक मार्केट तो एक देश, दो मंडियां क्यों? आपको किसान ही क्यों मिला? आप कह रहे हैं कि टैक्स मुक्त कर दिया, इन मंडियों में टैक्स कौन देता है, टैक्स खरीदार देता है, किसान नहीं देता है। पंजाब में किसान साढ़े 6 प्रतिशत, हरियाणा में चार प्रतिशत सरकार को देते हैं। आज हरियाणा और पंजाब का ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों है, हर गाँव में अच्छी सड़कें क्यों हैं? क्योंकि यह जो टैक्स जाता है तो ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन मंडियों और किसानों के विकास के लिए इस टैक्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए आज पंजाब और हरियाणा सबसे आगे हैं। फिर बात आयी कि एमएसपी खत्म हो गया। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा, अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा कि किसी में दम है, जो बताए कि एमएसपी चला जाएगा। सही बात है कि एमएसपी था, है और रहेगा, मगर क्या एमएसपी सभी किसानों कोमिलेगा और सभी फसलों पर मिलेगा, प्रश्न इस बात का उठता है। आपमें दम है तो आप खड़े होकर कह दें कि देश में हर किसान को एमएसपी मिलेगा। आज भी शांता कुमार कमेटी बताती है कि मात्र 6 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक किसानों को एमएसपी मिलता है, बाकी देश में बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, जहां पर एमएसपी नहीं मिलता है। आपको यह करना चाहिए था कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एमएसपी मिलता है, वही एमएसपी बिहार में भी मिले, जहां धान 800 रुपये में, 1,000 रुपये में जा रहा है। हमारे यहां 1,800 रुपये में धान मिल रहा है। आपको यह करना चाहिए था कि इसको वहां पर लेकर जाएं, मगर आप वहां के किसान की परिस्थिति हमारे यहां जैसी करने की बजाय, हरियाणा, पंजाब के किसान की परिस्थिति उस तरह की करना चाह रहे हैं।

आपने private की बात कही थी कि आप private की खिलाफत कर रहे हैं। हम private की खिलाफत नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं, private आए, मगर मंडियों में इसको आने से किसने रोका है? Private मंडियों में आए और MSP से ज्यादा में खरीदे। आप कह रहे हैं कि बाहर ज्यादा भाव मिलेगा। यदि बाहर ज्यादा भाव मिलेगा, तो आपको यह कानून बनाने में क्यों आपत्ति है? अगर MSP से कम का कोई contract होगा, तो वह कानून बाध्य होगा। हम हरियाणा में 2007 में contract amendment APMC Act, के अंदर लाए। उसमें निजी कम्पनियों को allow किया मगर साथ में कानून लिख दिया कि अगर contract MSP से नीचे किया जाएगा, तो वह गैर-कानूनी होगा और जो लोग इस तरह का contract करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आप कह रहे हैं, ज्यादा मिलेगा, तो आप यह कर दीजिए, आप कानूनी प्रावधान देने का काम करें। आपने कहा कि शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखी थी, आपने कहा कि मुख्य मंत्री के समय हुड्डा कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी कि APMC Act में सुधार हो, उसके अंदर बदलाव हो। मैं बताना

चाहता हूं कि हुड्डा कमेटी जिसमें प्रकाश सिंह बादल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी भी सदस्य थे, उस कमेटी ने इस पर क्या सुझाव दिया था? उन्होंने कहा था कि APMC Act में सुधार हो और इसका विस्तार हो। जिस प्रकार से हमने अपनी सरकार के समय हरियाणा में हर 10 किलोमीटर पर मंडियां स्थापित की थी, इसी तरह से पूरे देश में हर 10 किलोमीटर पर मंडियां बने। अगर कोई private आएं तो वे मंडियों के अंदर आएं, MSP से ज्यादा पर खरीदें और यदि MSP से कम पर खरीदते हैं, तो कानूनी कार्रवाई हो, इसलिए ऐसी खरीदारी allowed न हो। तीसरे, MSP की calculation C2 आधारित हो, A2 cost नहीं, C2 खर्चे के आधार पर MSP cost हो, जो आज किसानों की सबसे बड़ी मांग है। चौथा, यह है कि उसमें यह कहा गया है कि जो कर्ज़े की दर है...(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No discussion. ...(*Interruptions*)... Please, no cross talk. ...(*Interruptions*)... No discussion. ...(*Interruptions*)... किसी और की बात record में नहीं जा रही है।...(**व्यवधान**) Deepender*ji*, continue.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : यह सिफारिश थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि open market, free market अच्छी है, लेकिन मैं इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि free market हर चीज़ के लिए अच्छी नहीं है। मैं अनियंत्रित मार्केट के बारे में भी कहना चाहता हूं। आप अमरीका का उदाहरण देख लें, आज से 50-60 साल पहले वहां पर एक चौथाई लोग कृषि से जुड़े हुए थे। वहां पर free market लेकर आए। आज मात्र एक प्रतिशत अमरीका की जनसंख्या कृषि पर आधारित है। क्या free market के बाद यह concept आया?, 'Get big or get out.', बड़े-बड़े धनाढ्यों के आगे और corporate players के आगे छोटा किसान survive नहीं कर पाया। आज अमरीका के अंदर साढ़े चार सौ एकड़ की जोत वाला average किसान है। हिन्दुस्तान की तो average जोत आज मात्र 1.7 एकड़ है। हमारी तो 50 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये कैसे बड़े corporate का मुकाबला करेंगे? 'Get big or get out.', ये get out होंगे, तो कहां जाएंगे? क्या हमारी अर्थव्यवस्था है अमरीका की तरह .....(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Deepender*ji*, please start concluding.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं आखिर में अपनी दो बातें कहकर अपनी बात कन्क्लूड करना चाहूंगा। यहां बिचौलियां की बात की गई कि आपने बिचौलियों से मुक्त करा दिया, commission agents से मुक्त करा दिया। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जो बड़े-बड़े धनाढ्य लोग आएंगे, बड़े-बड़े corporate house आएंगे, टाटा, बिरला, अडाणी, अम्बानी आदि आएंगे, तो ये बिचौलिया नहीं तो किसकी श्रेणी में आएंगे? क्या ये किसान की श्रेणी में आएंगे या उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे? ये बड़े-बड़े लोग सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आएंगे, बिचौलियों की ....(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं आखिर में अपनी बात conclude करते हुए कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने एक और बात कही है कि किसान आंदोलन में कुछ पवित्र लोग हैं और कुछ अपवित्र लोग हैं। हम प्रधान मंत्री जी की बात मान लेते हैं, आप कम से कम पवित्र लोगों की बात मान लीजिए। आंदोलन में जो पवित्र लोग हैं अगर वे पवित्र भावना से अपने हक के लिए बैठे हैं, तो आप उनकी बात मान लीजिए। आप दो कदम उठाकर इसकी शुरुआत करिए। मैं मांग करता हूं कि बातचीत के जरिए उनसे बात करें। क्योंकि आप ग्यारहवें राउंड में बातचीत से भागे थे, आप बारहवीं बातचीत के दरवाज़े खोलें। यह आपकी प्रजा है, इसलिए आप अपनी प्रजा की बात मानने से छोटे नहीं होंगे। अपनी प्रजा की बात मानने से आपकी हार नहीं होगी। बातचीत के दरवाजे खोलते हुए और जिन 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान कुरबान की है, उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति लिए आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला है। कम से कम उनके परिवारों की मदद के लिए एक package की घोषणा करें, उन लोगों का आपके प्रति विश्वास बनेगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): दीपेन्द्र जी, आपका समय खत्म हो गया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : हम विश्वास बनाने वाले लोग हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि यह आपकी प्रजा है और ये आपके ही लोग हैं। आप इनकी बात मानिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिन्द।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No, no. ...(*Interruptions*)... Not required. ...(*Interruptions*)... Under which Rule? ...(*Interruptions*)... Not required. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH(Karnataka): Sir, he cannot speak again. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): It is not required. ...(*Interruptions*)... Not required. ...(*Interruptions*)... Not required. ...(*Interruptions*)... Please, Anurag*ji*, sit down. ...(*Interruptions*)... *Mananiya* Dr. Sudhanshu Trivedi. ...(*Interruptions*)... *Mananiya* Dr. Sudhanshu Trivedi. ...(*Interruptions*)... Not required. ...(*Interruptions*)... Not required. ...(*Interruptions*)... We will do it. ...(*Interruptions*)... *Mananiya* Dr. Sudhanshu Trivedi. ...(*Interruptions*)... I am not allowing anyone else. ...(*Interruptions*)... I am not allowing anyone else.

...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... मैं किसी और को allow नहीं कर रहा हूं।...(**व्यवधान**)... मैं किसी और को allow नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग क्यों खड़े हो रहे हैं? ...(**व्यवधान**).... I am not allowing anyone to stand. ...(*Interruptions*)... *Mananiya* Dr. Sudhanshu Trivedi, you are only allowed ...(*Interruptions*)... No; I am not allowing it. ...(*Interruptions*)... Not required. ...(*Interruptions*)... Anurag*ji*, not required. ...(*Interruptions*)... Shri Sudhanshu Trivedi. ...(*Interruptions*)...

SHRI SANJAY SINGH: Sir,... ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he is not allowed. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sanjay*ji*. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): What is the point of order? ...(*Interruptions*)... What is the point of order. ...(*Interruptions*)... Bhupender*ji*, what is the point of order? ...(*Interruptions*)...

श्री भूपेन्द्र यादव : संसदीय परंपरा का यह नियम है कि यदि कोई मंत्री बात स्पष्ट करना चाहते हैं, तो हमें संसदीय परंपरा के अंतर्गत allow करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... यह तो स्वाभाविक है। ...(**व्यवधान**)... अगर कोई मंत्री कुछ बात कहना चाहते हैं...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay; fine. I am just allowing him for just two minutes. ...(*Interruptions*)... उनका नाम लिया गया है।...(**व्यवधान**)... I am just allowing him for two minutes. ...(*Interruptions*)...

श्री भूपेन्द्र यादव: यह उनके विभाग का विषय है। ...(**व्यवधान**)... उनके विभाग का विषय है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): अनुराग जी, मैं आपको सिर्फ दो मिनट का समय देता हूं। ...(**व्यवधान**)... Anurag*ji*, not more than two minutes. ...(*Interruptions*)... Only two minutes. ...(*Interruptions*)...

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के दो मिनट भी नहीं लूंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं केवल एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am just allowing you for two minutes. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, do not allow him to speak. ...(*Interruptions*)...

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि...(**व्यवधान**)... ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने जितना एम.एस.पी. पांच साल में दिया, उससे ढाई गुना ज्यादा एम.एस.पी. मोदी सरकार ने दिया। हमने चार गुना से ज्यादा केन्द्र बढ़ाए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay, that is it.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए। यदि किसी ने रिपोर्ट लागू की, तो नरेन्द्र मोदी की सरकार ने लागू की।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay, thank you, Anurag*ji*. Now, *Mananiya* Dr. Sudhanshu Trivedi. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Sir, we will also reply. ...(*Interruptions*)... Why did you allow him? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No, no, see, it cannot go back and forth. ...(*Interruptions*)... Deepender*ji*, you took his name and he made a point. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Now, Dr. Sudhanshu Trivedi.

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने अपने पूर्ववर्ती वक्ताओं के बहुत-से विचार सुने। यहां पर तमाम आंकड़े, तथ्य और कथ्य बताए गए। मैं सोचता हूं कि आंकड़ों के विषय में हमें बहुत जानकारी है और सदन के सदस्यों को तो पर्याप्त जानकारी होती है। मैं इस आय-व्यय के अभिलेख, यानी बजट पर कुछ मन्तव्य और सरकार का इसमें क्या गन्तव्य है, इसे मैं दृष्टव्य करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जब कपिल सिब्बल जी ने शुरू किया, तो उन्होंने कहा था कि, context and background, यानी संदर्भ और पृष्ठभूमि। कोई चीज़ कैसे शुरू हुई, उसकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। इस संदर्भ में, मैं सबसे पहले क्वोट करना चाहूंगा कि वर्ष 2004 में जब चिदम्बरम जी ने यूपीए सरकार का पहला बजट दिया था, तो उन्होंने एक शब्द बोला था, जो उनके बजट भाषण में है - "The economic fundamentals are strong and the balance of payment is robust." यानी हमने वह पृष्ठभूमि छोड़ी थी, जिस पर वे कह रहे थे कि इकोनॉमी मजबूत थी। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा कि अरुण जेटली जी ने 2014 के बजट में कहा था - "The two successive years of sub-five per cent growth has resulted

in the challenging situation coupled with the double-digit food inflation to be lowered. " यह पृष्ठभूमि और यह संदर्भ था, जब हम छोड़ते हैं, और यह पृष्ठभूमि और यह संदर्भ है, जब आप छोड़ते हैं। हमारे बहुत से सदस्यों ने कोविड की बीमारी का उल्लेख किया, तब हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कहा कि कोविड से पहले भी तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। उनके अनुसार उसका मूल कारण मोदी सरकार की नीतियां थीं। मैं इस विषय में क्वोट करना चाहता हूं कि IMF की Director, Kristalina Georgieva ने अपनी पहली speech in the month of October, 2019 में दी थी which was based on the assessment of IMF and in July, 2019, उन्होंने अपनी स्पीच में यह बोला था कि "The global economy is now in a synchronized slowdown." Then, she added in her speech that 'the deceleration will cause global growth to slide to its lowest since the start of the decade. She blamed the slowdown on a range of issues, but clubbing them under one common theme, that is, a fracture. The trade disputes are taking a toll and global trade growth has come to a near standstill.' यानी उन्होंने कहा कि दस साल में सबसे खराब स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्था synchronized slowdown में थी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो range of issues बताए, उनमें मोदी सरकार का इश्यू कहीं नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम वैश्विक धरातल पर देखते हैं, तो कुछ हकीकत को भी देखने का प्रयास करें। इस बजट के बारे में यह कहा गया कि 1991 के बजट से तुलना करने का प्रयास किया गया। 1991 और आज के बजट में भारी अंतर है। जैसा अभी मैंने आई.एम.एफ. का क्वोट किया। हम लोग "दैहिक दैविक भौतिक ताप" के बारे में सुनते हैं। यह तो दैविक ताप था और 1991 भौतिक था।

वह man-made था, यह God disposed है। कैसे? देखिए, जब 1991 में हमारा Forex Reserve एक बिलियन के भी नीचे रह गया था, तो ऐसा नहीं है कि चार महीने की चंद्रशेखर जी की सरकार या 11 महीने की वी. पी. सिंह जी की सरकार में आ गया था। एक दशक तक स्वर्गीय इन्दिरा जी की दो-तिहाई बहुमत की सरकार, फिर 1980 से 1984 तक और फिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 1984 से 1989 की सरकार रही थी। 1980 में क्या स्थिति थी? मैं बताना चाहता हूं कि भारत का जो foreign exchange reserve था, वह 7 billion dollar था और China का 2.55 था। 1980 में चाइना कहां खड़ा था और हम कहां खड़े थे और फिर कहां खड़ा हो गया वह, और कहां खड़े हो गए हम। आप यह समझिए कि जब foreign exchange reserve 1 बिलियन डॉलर या उससे कम रह गया था, तो वह 100 बिलियन डॉलर कब हुआ था - 2004 में अटल जी सरकार में। वह 500 बिलियन डॉलर कब हुआ - मोदी जी की सरकार में। यह अंतर है कि हमने किस रूप में किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोविड काल में जो कुछ हुआ, यह तो अपने आप में अभूतपूर्व था, क्योंकि यह मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। हम सब इस बात से वाकिफ हैं। हम इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। हम इस बजट में सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात, जो वित्त मंत्री महोदया ने की - पूरी transparency की है। इसीलिए 9.5 प्रतिशत का fiscal deficit दिखाई दे रहा है। हमने वह कार्य करने का प्रयास नहीं किया कि पूर्ववर्ती समय में 1 लाख 40 हजार करोड़ के oil bonds, जो भारत सरकार के pay करने थे, परंतु वे oil companies के खाते में दिखाए गए और उस कारण से fiscal deficit कम

रहा। मगर मैं कहना चाहूंगा कि निर्मला जी ने एक हिम्मत दिखाई है, 'यथा नाम तथा गुण' के अनुसार निर्मलता के साथ पारदर्शी बजट दिया है। आप समझिए कि जब कोविड आया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी - स्वास्थ्य। जैसा कि हमारे साथ के वक्ताओं preventive, curative और सबकी wellness के बारे में बताया, तो स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना था। स्वाभाविक रूप से जो यहां पर स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हुई, तमाम वक्ता बता चुके हैं कि 137 प्रतिशत की हुई, परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम कोविड की बात करते हैं, तो कहते हैं कि medicines के साथ-साथ long-term immunity भी चाहिए, यानी हमारे शरीर की जो अंतर्निहित प्रतिरोधक क्षमता है, वह बढ़नी चाहिए। वही तो इस बजट में किया गया है। सबसे ज्यादा जोर infrastructure and capital expenditure पर दिया गया है, जो long-term intrinsic strength को बढ़ाने वाला है। देखिए, सरकारें बहुत से काम करती हैं। तीन श्रेणी के कार्य होते हैं - एक जो पिछली सरकारों ने भी किए, हमने भी किए - बेहतर किए, ज्यादा किए, जैसे, रोड, रेल, पावर, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाता हूं। हमने बहुत बेहतर किए और बगैर किसी आरोप के किए। दूसरा होता है, जो पिछली सरकारों ने प्रयास किए, परंतु किसी कारणवश वे उन्हें अंजाम तक नहीं ला पाए, जैसे - जीएसटी, agriculture laws भी कुछ लाए गए थे, लेकिन वे नहीं कर पाए, परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो पिछली सरकारों के ध्यान में नहीं आए। यदि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है, तो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होनी चाहिए थी! यदि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होनी थी, तो शायद किसी ने solar energy के बारे में तो सोचा होगा, परंतु solar alliance बनेगा और उसका नेता भारत बनेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। यह हमारी सरकार ने करके दिखाया और इस बजट में 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बजट मे एक और चीज़ की है। Hydrogen Energy Mission बनाने की शुरुआत की है, यानी clean energy की दृष्टि से भारत नए सिरे से कैसे आगे बढ़ेगा, यह एक ऐसी चीज़ है, जिसको कि उन्होंने इसमें करके दिखाया है। जब हमने हेल्थ की बात की है, तो हमने एक ऐसे कमिशन की भी बात की है, जिसमें जो health workers हैं, यानी nurses and other allied health staff, उनके कमिशन के लिए भी हमने बात की है। कृषि की बात आती है और यह आजकल बहुत चर्चा का विषय है। अभी हमारे एक सम्माननीय सदस्य अंग्रेजों के ज़माने की गुलामी की बात कह रहे थे, तो मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद तकरीबन 50 साल तक बजट शाम को पांच बजे पढ़ा जाता था, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में उस समय 11 बज रहे होते थे। यह अटल जी की सरकार ने आकर बदला कि हम गुलामी की मानसिकता से, गुलामी के समय के हिसाब से काम नहीं करेंगे और मोदी जी ने डेट बदली कि 28 फरवरी की जरूरत नहीं है - क्योंकि मानसून आता है, तो यह भारत के मानसून के अनुसार होना चाहिए। कृषि में हमने 30 हजार करोड़ से 40 हजार करोड़ बढ़ाया, 16.5 लाख के संबंध में बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। चिदम्बरम जी ने बोला था कि mountains of grain, अनाज के पहाड़ लगे हैं। आप याद करिए कि जब शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर सरकार के पास स्टोर करने के लिए नहीं रह गया है, अनाज सड़ रहा है, तो कृपया इसे गरीबों में मुफ्त में बांट दीजिए, मगर उपसभाध्यक्ष महोदय, उस समय भी Essential Commodities Act था और ये कह रहे हैं कि रहना चाहिए। यानी एक तरफ कहते हैं कि हरित क्रांति लाकर अब हमने सारी चीज़ों से मुक्ति पा ली है, उसके बावजूद हमारे पास इतना है कि mountains of grains है, फिर भी होना चाहिए। कोई बात नहीं।

महोदय, अब मैं कृषि की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। 2013 तक WTO ने जिस प्रकार का शिकंजा हमारे ऊपर कसना शुरू किया था और उसका यह दबाव था कि 2017 तक बहुत सी चीज़ें मान लें, तो शायद हम कृषि में आज सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं होते। इस संदर्भ में मैं वर्तमान वित्त मंत्री और तत्कालीन Trade and Commerce Minister, निर्मला जी का एक बयान जो इसी सदन में दिया गया था, उसको quote करना चाहूंगा। जब विपक्ष के के.सी. त्यागी जी ने पूछा था - मैं उसको क्वोट कर रहा हूं, passionately she answered Shri K.C. Tyagi that we don't allow our farmers prices or agricultural production to be determined by somebody else outside.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sudhanshu*ji*, please conclude.

डा. सुधांशु त्रिवेदी : सर, आपने कहा है तो मैं अब इसको sum-up करता हूं। भाई, हम तो WTO में जाकर लड़े, आप तो रास्ते में जो दिल्ली की सीमा पर बैरियर खड़े थे, उनको तोड़ने वालों के साथ खड़े थे। हम तो WTO का बैरियर तोड़कर किसानों के लिए सारे जहाँ से लड़ने के लिए खड़े थे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि यह सब rich के लिए है, बहुत कहा जा रहा है कि rich के लिए है। सबसे ज्यादा एक्साइज़ ड्यूटी किस पर बढ़ाई गई है- precious stones पर, इसे साढ़े सात परसेंट से बढ़ाकर 15 परसेंट कर दिया है। इसके अलावा ढाई परसेंट agriculture cess अलग से लगा है। यह किसके लिए लगा है, यह किसान के लिए लगा है। ढाई परसेंट agriculture cess किसके लिए - सोने और चांदी के लिए, यानी मणि-माणिक को महंगा किया है और अनाज को सहज किया है। मैं एक पंक्ति कहूंगा, हम प्रेरणा कहां से लेते हैं:

" मणि-माणिक महंगे किए, सहजे तृण, जल, नाज,
तुलसी सोइ जानिए, राम गरीब नवाज।"

सर, अंत में एक वाक्य और कहना चाहता हूं। इसमें अमीर गरीब सबके लिए है, इसमें कृष्ण के लिए भी है, सुदामा के लिए भी है, कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ, जिन्हें हलधर भी कहते हैं यानी किसान के लिए भी है, एकलव्य के लिए भी है और जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, पितामह भीष्म और द्रोण के लिए भी है, परन्तु एक गलती वित्त मंत्री जी ने कर दी है कि शकुनी के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। जिस कारण से पासे फेंके जा रहे हैं महाभारत करने के लिए, परन्तु आश्वस्त रहिए, यह बजट जानते हैं कहां ले जाएगा- जो हम नित्य प्रार्थना करते हैं:

" परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं,
समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्।"

धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, Shri Satish Chandra Misra; you have two minutes to speak.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. I will be speaking only on one issue. The hon. Finance Minister or the Minister of State is probably not here. But, since others are here, they will probably take note of it. Shri Bhupender Yadav had spoken on the issue of health infrastructure and health. Within health, I am speaking only on one issue and that is Cancer. Now, the situation in this country with respect to the Cancer is very alarming. It is there the world over but in India, it is very alarming. Twelve lakh new cases of Cancer per year are coming up in India; 25 lakhs are presently prevalent all over India, and out of this, 5.5 lakh deaths of cancer patients are happening every year. We have just now seen 1,50,000 deaths due to Covid. Here, साढ़े पांच लाख लोग हर साल कैंसर से मर रहे हैं, जिनको कि हम नोट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि लगातार चल रहा है। It is increasing every year. Now, the situation at present is that WHO के हिसाब से सिचुएशन यह होने वाली है कि 15 लोगों में से एक आदमी कैंसर से सफर कर सकता है इस कंट्री में। जब इतनी alarming position है, आपने infrastructure के लिए पैसा दिया, आपने कहा कि हमने 2 लाख 35 हजार करोड़ रुपया दिया, आपने कहा कि 35 हजार करोड़ रुपया आपने खाली Covid vaccine के लिए दिया है, जिसमें 99 per cent recovery है और one per cent death है - यहां पर डेथ सेंट परसेंट हो जाती है अगर डिले हो जाता है - तो और ये साढ़े आठ लाख लोग हर साल मर रहे हैं। Unfortunately, here its treatment is very limited. लेडीज़ में कैंसर बहुत कॉमन है, Man में oral cancer है, lung cancer है, Oeasophageal है, stomach cancer है, Women में cervical है, breast cancer है, oral है, cavity का है, सिचुएशन यह है कि इनका treatment ऑपरेशन है और ऑपरेशन के बाद यह flare up हो जाता है और इसमें radiation की जरूरत पड़ती है और radiation therapy के लिए, you need machines for radiation. Now, here the situation is that there is non-availability of radiation machines. इस कंट्री में 40 मशीनें - जितनी भी मशीन्स हैं, वे बाहर से आती हैं, इन्हें बाहर की कंट्री ही बनाती है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: एक स्वीडन में और एक यू.एस.ए. में है। Now, the point which I would like to make is that this infrastructure for the purpose of radiation machine, लोग लगाएं, इसके लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उसकी जगह जो पहले 20 per cent टैक्स था, अब it has been increased to 27.4 per cent which includes customs duty, health cess, social welfare and GST. So, I request the Government, in all earnest, to kindly look into this aspect. आपने खाली 120 करोड़ रुपये ही custom duty और इन taxes के माध्यम से कमाये हैं, लेकिन इस ट्रीटमेंट में मशीन लाने के लिए और लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं तथा infrastructure नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं आ पा रहे हैं। Since, I am

also running a charitable hospital, I was personally looking into this matter कि हम इसको कर सकते हैं but, we gave it up because of the 27.4 per cent tax. एक मशीन 13 करोड़ से 15 करोड़ तक की आती है, आपने उसमें 3 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में और ले लिए, इस तरह से आपने पूरे साल में 120 करोड़ रुपये कमा लिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको कंसिडर कीजिए और kindly take this into consideration कि जहाँ आपने कोविड महामारी के लिए इतना किया है, वहीं यदि आप यहाँ पर 120 करोड़ रुपये छोड़ देंगे, तो...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सतीश जी, we have to move on to the next speaker.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : शायद लोग afford करके इस infrastructure को बढ़ा सकेंगे और जो 8.5 लाख कैंसर पेशेंट्स मर रहे हैं, उनको इससे मुक्ति मिले। महोदय, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The next speaker is Shri Abdul Wahab; you have five minutes.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, first of all, thank you for giving me five minutes, because so far I was getting only three minutes.

The Budget presented by hon. Finance Minister has failed to meet the aspirations of citizens belonging to any sections of our society. It has not addressed any major issue that concerns common people of this country such as issues pertaining to unemployment, crisis in small scale industry and price rise of essential commodities, etc. The Budget has also disappointed all communities like it has betrayed farmers, students, migrant labours, minorities, backward communities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. A lot of subjects about which the Minister talked about in agricultural sector remain rhetoric.

Instead of announcing any major schemes or allocations in agriculture sector from the pocket of Government, this Budget has only increased the credit target of the banks in agricultural sector. Almost all the infrastructural fund announcements made by the Minister in agriculture, animal husbandry, rural infrastructure, micro irrigation should be taken with caution as many of the announcements made in previous budget and stimulus packages during Covid is neither sanctioned nor spent.

It is not surprising to see that Government has given minimal Budget estimate for important sectors such as Education and social welfare.

However, in her Speech, inclusive development for aspirational India, the Finance Minister has once again failed to give any attention to minority communities. In fact, this Government has once again reiterated its detestation with minority community by not spending Rs. 600 crores from its previous Budget and now, by further reducing it by 25 percentage in this Budget estimates.

The document provided by the Government proves its detestation with Scheduled groups and other vulnerable communities as well, as Government has failed to spend a major chunk of the fund from the previous year's Budget for the welfare of these communities.

The ongoing protest by the farming community makes it clear that Government and its previous Budget are documents without any vision and it has completely failed in its promise of doubling the farmer's income by 2022, as assured.

I request our Finance Minister; Minister of State, Shri Anurag Singh Thakur is here; intervene in all these areas. His name is being mentioned, so he will take two minutes from you and reply to it. I request hon. Anurag Thakur*ji*. I am mentioning your name; I feel that you will reply to this in two minutes. Fund for the development of Aligarh Muslim University, off campus at Malappuram, it is there only for the namesake नाम केवास्ते, but no fund is given, from the time, when Ms. Smriti Irani was the Minister, till this time. There is only one Kendriya Vidyalaya school in Ponnani Constituency and my personal interest is that there should be one Ekalavya Model Residential School at my place Nilambur, it comes under Ministry of Tribal Affairs because most of the tribals are living in our place. So, these are the three requests, I wanted to personally make to you.

Sir, I am telling one more thing, because I have some time. While coming to Delhi, one retired Air Force pilot was sitting near me. He was a Vir Chakra holder. He was there in the 1965 War and 1971 War. He was asking about the 'One Rank, One Pension' Scheme of the Government. He was telling me Modi*ji* announced everything. He was also having some contacts with Modi*ji*.

But, actually, they are not getting it. They have got a lot of difficulties. So, I told him that I would raise this case in the Parliament. Anurag Thakurji, I hope that you will do justice to retired pilots and Jawans because they are the ones who are protecting our land from foreign countries like Pakistan and China.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI ABDUL WAHAB: Conclude! ...(*Interruptions*).. I conclude with thanks.

AN HON. MEMBER: He is so obedient. ...(*Interruptions*)..

SHRI ABDUL WAHAB: I am always. ...(*Interruptions*)..

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, the hon. Member raised a very serious issue. He made three demands about his Constituency. I will forward these to the concerned Department, that I promise it. At the same time, he raised a very relevant issue of 'One Rank One Pension', which was pending for 30-40 years. When my father was MP, he raised it. The only person who is able to implement it, it is Narendra Modiji and thousands of crores of rupees have been given to the ex-servicemen. ...(*Interruptions*).. About the point raised by the hon. Member, I would like to seek the details about the concerned person. ...(*Interruptions*).. If there is anything which we can do, I will be more than happy to help that person. ...(*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Anuragji, you have made your point. ...(Interruptions).. Thank you. ...(Interruptions).. Hon. Member, Shri Ashwini Vaishnaw. ...(Interruptions).. You have ten minutes.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : जयराम जी, आपको खुश होना चाहिए कि सरकार इतनी सकारात्मक है कि साथ-साथ जवाब दे देती है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Anuragji, please. ...(Interruptions)..

श्री अश्वनी वैष्णव (ओडिशा): उपसभाध्यक्ष महोदय, दो दिन से सदन में बजट पर चर्चा चल रही है। मेरे वरिष्ठ मित्रों ने बजट में जितनी स्कीम्स हैं, जितने प्रावधान हैं, उनका विस्तार से वर्णन किया है, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊँगा। समय की मर्यादा है, मैं केवल तीन बातें कह कर अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। दो दिन पहले से और कल भी कांग्रेस के कई माननीय सांसदों ने पूछा था कि इस बजट से गरीब महिलाएँ और किसान आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। यह वाजिब सवाल है। 60-70 साल में आपने कभी यह सोचा भी नहीं कि कोई प्रधान मंत्री ऐसे आएँगे, जो उस तबके के बारे में सोचेंगे और उस तबके को आत्मनिर्भर बनाएँगे, उस तबके को मजबूत बनाएँगे, जिसके

बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं था। आप कहते हैं कि यह बजट अमीरों का है, पूरे देश को बेच दिया, इसको बेच दिया, उसको बेच दिया, कई गिनती गिनाते हैं - दो दूनी चार। शायद आपको अपना कार्यकाल याद आ रहा था! आपके बड़े-बड़े मंत्री थे, शायद आपको अपना कार्यकाल याद आ रहा था, जब आप कह रहे थे कि this Budget is for the rich, of the rich and by the rich. हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं होता। मैं कांग्रेस के सांसदों से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या 45 करोड़ जनधन एकाउंट्स अमीरों के हैं, 8 करोड़ उज्ज्वला गैस से जिन माँओं की आँखों की रोशनी बची, क्या वे गरीबों के लिए हैं या अमीरों के लिए? आपको इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। समाज पूछेगा, जनता पूछेगी आपसे। क्या 10 करोड़ शौचालयों से जो महिलाओं की, बहनों की गरिमा बढ़ी, क्या वे गरीबों के लिए हैं या अमीरों के लिए? क्या उससे देश बिका या हमारे समाज की नींव मजबूत हुई? 'आयुष्मान योजना' से जो गरीब के घर का खर्च कम हुआ, क्या उससे देश बिक गया, क्या उससे foreign capital आ गया? 'पीएम आवास योजना' से जो पक्के मकान बने हैं, क्या वे दो घरानों ने बनाए हैं, क्या वे industries ने बनाए हैं? जनाब, आप किस तरह के सवाल करते हैं! आज किसान सम्मान निधि directly किसानों के खाते में पहुँचती है। Migrant labours के लिए राशन काड्र्स की व्यवस्था की गई। याद कीजिए, अगर कोई migrant labour एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो उसका राशन कार्ड खत्म हो जाता था। आज 'One Nation One Ration Card Scheme' के तहत labour कहीं पर भी जाए, उसको राशन की सुविधा मिलती है। Micro irrigation 50 लाख हेक्टेयर है। क्या इससे किसान आत्मनिर्भर नहीं बनता है? सोलर ऊर्जादाता, 20 लाख farmers को Solar Pumps, क्या इससे किसान मजबूत नहीं बनता है? आप क्या बात करते हैं! 'ग्राम सड़क योजना', पूज्य अटल जी ने यह स्कीम शुरू की थी। 2000 से 2014 के बीच करीब 4 लाख किलोमीटर सड़क बनी, जबकि 2014 से आज तक 6 लाख किलोमीटर सड़क बनी। जो काम 14 साल में नहीं हुआ, उससे ज्यादा काम 7 साल में हुआ है। आप यह क्या industrialists की बात करते हैं! आपको थोड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आपका स्वभाव ऐसा है, आपके संस्कार की बात है। आपके नेता चाँदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, लेकिन हमारे नेता, मोदी जी संघर्ष के साथ उठ कर आए हैं। आपके नेता को Discovery of India करनी पड़ी थी, लेकिन हम तो उन्हीं गाँवों में पैदा हुए, जिनकी discovery आपको करनी पड़ती है। आप अंग्रेजों के 'divide and rule' को follow करते रहे, लेकिन 'सबका साथ, सबका विश्वास', मोदी जी ने यह मंत्र दिया, हम उस मंत्र पर चलते हैं। आपके नेता कहते हैं कि आलू डालो, सोना निकलेगा, लेकिन हमने किसानों को Soil Health Cards, Neem Coated Urea, Solar Pumps दिए। हमने आपकी तरह आलू डालो और सोना निकलेगा की बात नहीं की। आपके नेता कहते थे कि अक्साई चिन में क्या है? वहां तो घास का पत्ता भी नहीं उगता है। हमारे नेता मोदी जी ने surgical strike की, air strike की और दुश्मन को दांतों तले चने चबवा दिए। आपने 70 सालों में रेगुलेशंस का मकड़जाल बना कर रख दिया था। हमारे नेता मोदी जी ने 1,500 ऐसे कानून हटाए, जिनकी जरूरत नहीं थी और जिनके कारण आज देश भर में सुविधा हो रही है। आपके समय में 1 रुपये में मात्र 15 पैसे किसान तक पहुंचते थे।

माननीय उपसभाध्यक्ष, मैं ओडिशा से आता हूं। हमारी ओड़िया भाषा में कहते हैं - 'बाट्टो मारणा', जो यहां सही बैठता है। 1 रुपये में से 85 पैसे रास्ते में कहीं और चले जाते थे। हमारे नेता मोदी जी के समय में एक बटन दबाने से पूरे के पूरे पैसे किसानों के, गरीब माताओं के खाते में

पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको यह बात कैसे समझ आएगी कि गरीब आत्मनिर्भर कैसे बनता है? आपने इतने वर्षों में कभी इस तरह की बात सोची भी नहीं होगी।

उपसभाध्यक्ष जी, अब मैं अपने दूसरे विषय पर आता हूं। कल भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री चिदम्बरम साहब ने कहा कि यह बजट केवल supply-side Budget है, इसमें demand stimulate करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। वे पढ़े-लिखे विद्वान हैं, economist हैं, मैं तो economist नहीं हूं। मैं 1991 से बजट को पूरा पढ़ता आ रहा हूं और उसी को धीरे-धीरे समझने की कोशिश करता रहा हूं। मेरे मत में the hon. Finance Minister has struck the right balance between consumption and investment. The Budget has absolutely good provisions both for consumption and for investment. जैसा मेरे साथी सुधांशु जी ने कहा, इस बजट में तात्कालिक सुविधा भी दी गई है और long-term growth कैसे हो, इसके लिए प्रावधान भी दिया गया है। मैं इसके बारे में विस्तार से कहना चाहता था, लेकिन समय की मर्यादा है। Consumption के लिए 'किसान सम्मान नीधि' में 65,000 करोड़ रुपये दिए गए।

उसके बाद MNREGA की बात उठी। आप कहते हैं कि MNREGA के लिए allocation कम कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप यह किस तरह की बातें करते हैं? MNREGA is a demand-driven scheme. पिछले साल के बजट में इसके लिए 61,000 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए थे, लेकिन 1,11,000 करोड़ रुपये का actual expenditure हुआ। जहां जरूरत होती है, लेबर के लिए जहां demand होती है, वहां MNREGA में automatically allocation बढ़ जाता है। आप में से किसी को भी MNREGA के विषय में देश को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है, विशेषकर...

SHRI BINOY VISWAM: I am sorry for having said that. ...(*Interruptions*)...

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Viswamji, it is the reality. These are real numbers. This year also, the allocation is Rs.71,000 crore, but if the demand increases, it will be reviewed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Ashwiniji, please address the Chair.

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, कल माननीय चिदम्बरम जी कह रहे थे कि इस बजट में structural shift नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें structural shift है। इसमें Central Government Departments पर 5.5 लाख करोड़ रुपये का capital investment है और 2.2 लाख करोड़ रुपये, यानी कुल मिलाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये के capital investment का इस बजट में प्रावधान है। उसका impact हम सबको समझना चाहिए। मेरे पास इसकी detailed calculations हैं और इन calculations पर मैं किसी के साथ भी discuss कर सकता हूं। 7.5 लाख करोड़ रुपये की capital investment का मतलब है, GDP में 27 लाख करोड़ रुपये। मैंने 2003 से 2019 तक का multiplier देखा है और उसमें GDP के complete numbers मैंने calculate किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह 3.6 multiplier है। जब GDP में 27 लाख करोड़ रुपया ऐड

होगा.... मैं GDP के आंकड़ों में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो human angle है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे 30 लाख direct employment generate होता है और अगर हम indirect employment को भी जोड़ दें, तो इस capital investment से 80 लाख direct and indirect employment generate होता है। यह human angle है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Ashwiniji, please conclude.

श्री अश्वनी वैष्णव : दो मिनट, सर। Taxes, Rs.3.3 lakh crore. Wages, 3.6 lakh crore, जो सबसे important है। यानी 3.6 लाख करोड़ रुपया कामगारों के हाथ में जाएगा और इसका जो impact होगा, उससे MSME sector में 16 लाख करोड़ रुपये की डिमांड बढ़ेगी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह supply side का बजट है। यह pure and proper combination है। It is a very balanced approach और इसी एप्रोच से हम आगे जा सकते हैं, किसी दूसरी एप्रोच से आगे नहीं जा सकते हैं।

सर, मैं कन्क्लूड करूंगा। 1991 से मैं बजट को ध्यानपूर्वक पढ़ता आया हूं। 'The Hindu' में उसका पूरा supplement छपता था, उसको मैं पूरा का पूरा पढ़ता था। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एकदम रियलिस्टिक एस्टिमेट्स हैं। चाहे रेवेन्यू का एस्टिमेट हो, चाहे एक्सपेन्डिचर का एस्टीमेट हो, चाहे फिस्कल डेफिसिट का कम्प्लीट नम्बर उसमें लिखा जाना हो। This is for the first time that the most honest, most realistic Budget has been presented and this has been appreciated globally. उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बजट सामान्य मानवी को केन्द्र में रखकर बनाया गया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Ashwiniji, you need to conclude now.

श्री अश्वनी वैष्णव: विपक्ष के दिग्गज नेता कोरोना काल में ऐसी-ऐसी भयानक भविष्यवाणी करते थे, रनिंग कमेन्ट्री देते थे कि अगस्त में इतने नम्बर हो जाएंगे, सितम्बर में इतने लोग मर जाएंगे – उनकी कोई भी बात सच नहीं निकली। वे भूल गये कि यह मोदी जी के परिश्रम की पराकाष्ठा है, आज यह मोदी जी की तपस्या है कि कोरोना की कठिन घड़ी में भी हम याचक बनकर हाथ नहीं पसार रहे हैं, हम दुनिया भर को वैक्सीन, मेडिसन्स, पीपीई किट्स और मास्क्स भेज रहे हैं। महोदय, मैं इस बजट का तहेदिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद।

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में रखे गये इस बजट का स्वागत करने के लिए, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, सब जगह सिर्फ बातें हो रही हैं। अभी अश्वनी जी ने कितनी अच्छी-अच्छी बातें उन लोगों को सीखने के लिए कहा है कि ज़रा सीख लीजिए कि कम से कम नरेन्द्र मोदी की कथनी और करनी में तथा आपकी करनी में कितना अंतर है। ये दोनों बातें उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ समझाई हैं।

श्रीमन्, मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का व्यक्ति हूं। अभी ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में और कृषि के संदर्भ में भी बातें होती रही हैं, लेकिन यह जरूर है कि इस देश में तथा पूरे विश्व में जिस प्रकार से महामारी आई, भारत और दूसरे देशों को अगर देख लिया जाए, जिस प्रकार से हमारे नेता, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह नहीं देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या रहेगी, उन्होंने यह देखा कि हमारे देश के लोग कितने सुरक्षित रहेंगे और इस नाते देश की सुरक्षा पर पहले ध्यान दिया, लोगों की सुरक्षा पर पहले ध्यान दिया और उसी का परिणाम है कि आज भी विश्व के बड़े-बड़े विकसित देश भी इस महामारी से जूझ रहे हैं और आज भारत उसमें कहीं न कहीं पूरे तौर पर सक्षम हो गया है और इतना ही नहीं, बल्कि हम तो वैक्सीन बनाने में भी सफल हुए और अपने देश में भी लोगों को लगा रहे हैं। हम यह लाखों लोगों को लगा चुके हैं और साथ ही साथ हमने यह दूसरे देशों में भी भेजी हैं, सहायता के रुप में भेजी है, बिक्री के लिए भी भेजी है। आप लोग विदेशी मुद्रा की बात करते हैं, हम उससे भी इस देश के लिए विदेशी मुद्रा लाने का काम कर रहे हैं।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों के नाते ही भारत में यह स्थिति आई कि लोग भारत की सराहना कर रहे हैं। विश्व की हर संस्था, हर नेता यह कहता हैं कि इस कोविड-19 पर पूरी तौर पर कायदे से अगर किसी ने काम करने का काम किया तो वह इस देश के नेता, श्री नरेन्द्र मोदी हैं। यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है। अभी वहां से बहुत बातें की जा रही थीं। इसके पहले क्या बातें होती थीं कि ये लोग तो साम्प्रदायिकता करते हैं, केवल धारा-370 पर बात करते हैं, ट्रिपल तलाक पर बात करते हैं, राम मन्दिर की बात करते हैं। इन सबमें कहीं न कहीं हमारे लिए राष्ट्र छुपा हुआ रहा है, सबमें कहीं न कहीं देश छुपा हुआ रहा है कि किसी एक के साथ पैरिटी न हो, सबमें समानता हो, इस नाते यह बात आई थी। यह कहते थे कि सुधार कर ही नहीं सकते हैं। आज मुझे इस बात को कहने में खुशी हो रही है, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीया वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट दिया है, अब आप यह कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे कि सुधार ये जानते ही नहीं हैं। उन्होंने बजट का जो फार्मूला दिया, वह '3R' का दिया। पहला क्या है? उन्होंने पहला जो फार्मूला दिया, वह 'Relief for poor and unemployed' का दिया, गरीबों और बेकारों के लिए राहत का दिया। दूसरा क्या दिया - 'Recovery of the economy', जो रिकवरी पटरी से उतर गयी थी, उसको भी पूरे तौर पर पटरी पर लाने के लिए इस बजट में उन्होंने प्रावधान करने का काम किया। तीसरा क्या दिया - 'Reform of the financial system.' वित्तीय तंत्र में सुधार किया। ये तीनों फार्मूले देकर उन्होंने इस बात को बताया कि जो अर्थव्यवस्था होती है, वह क्या होती है। पहली बार बड़ी दृढ़ता के साथ माननीय वित्त मंत्री जी जब लोक सभा में अपना बजट रख रही थीं, तो सेंसेक्स उछलता जा रहा था। लोग कह रहे थे कि यह क्या हो गया, यह हज़ारों-हज़ार के प्वाइंट्स में उछल रहा है - तो यह हमारे सुधार की नीति है।

ये लोग जो अभी बैठे हुए हैं, कह रहे थे कि इस बजट से मंदी आयेगी। मैं वे वर्ष गिनाना चाहता हूँ। मान्यवर, 1958, 1966, 1973, 1980, इनमें कभी भी एनडीए नहीं रही है, आप इन चारों वर्षों की मंदी के आंकड़े को उठाकर देख लीजिए - तो आज तो कोविड के नाते भी मंदी आयी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ढही, भारत भी उससे प्रभावित हुआ है, लेकिन भारत ने अपनी बचत के आधार पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारा। अर्थव्यवस्था को सुधारने के साथ-साथ चुनौती देने का काम भी किया। मंदी की जो स्थिति ये लोग करते थे, वैसी स्थिति हमारे समय में नहीं रही

है। वे देश को ले जाकर मंदी में खर्च कर देते थे। आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी 9.5 की बात कह रहे थे। मैं जानता हूँ कि वह 6.3 पर आकर ठहरेगी और आप देखिएगा कि एक साल में वह स्थिति आ जायेगी।

श्रीमन्, इन 40 वर्षों में पहली बार - उसके बाद 40 वर्ष इधर हुए, जिस पर ये मंदी की बात करते थे कि मंदी आयी, लेकिन उसके पहले के जिन 4 वर्षों को हमने गिनाया, उनमें बहुत बड़ी मंदी थी। इस मंदी का कारण किसी नाते हमारी अर्थव्यवस्था नहीं रही, बल्कि यह मंदी पूरे विश्व की मंदी रही, इस नाते भारत में भी उसका असर होना था, जो हुआ भी। यह कहीं भी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की अर्थ नीति की गलती नहीं रही है।

श्रीमन्, बहुत सी बातें आयीं। मेडिकल में 2 लाख करोड़ रुपये का बजट आया। 35,000 करोड़ रुपये उसमें पूरे तौर पर केवल टीके पर दे दिये गये। उसके अतिरिक्त, जब यह विचार होता है - अभी अश्विनी जी कह रहे थे, उन्होंने विषय भी गिनाये - इन्होंने जो विषय गिना दिये, वे तो कभी उनके ध्यान में भी नहीं रहे होंगे, लेकिन आप यह बताइए कि इस बजट में ही - आदरणीया वित्त मंत्री जी ने जो बजट दिया, क्या उसमें गैस के कनेक्शन की बात आयी, क्या इस बजट में भी एक करोड़ और घरों में महिलाओं के लिए वह गैस का कनेक्शन नहीं आया? क्या अब 1 करोड़ और महिलायें धुएँ से नहीं बचेंगी? यह जो विषय आया, माननीय मोदी जी की सरकार सोच कर लायी, माननीया वित्त मंत्री जी लायीं। वह गरीब और गरीबी, इन दोनों को सामने रख कर लाया गया। पहले तो वहाँ से नारा दिया गया था - 'गरीबी हटाओ'। हम कहते हैं 'गरीबी हटाओ', तो वे लोग कहते हैं, हमें हटाओ। कभी वह नारा था, लेकिन आज स्थिति क्या है? सही यही है कि लोग जो कहते थे, जब वह हटी, तभी धीरे-धीरे करके इस देश से गरीबी हटने का काम हुआ। आज एक-एक स्थिति को देख लीजिए। 'किसान सम्मान निधि' गरीबों के लिए, किसानों के लिए मिल रही है, 'जन-धन खाता' गरीबों के लिए है। जब कभी पहले एक रुपया भेजा जाता था, तो 20 पैसे मिलते थे, 10 पैसे मिलते थे, लेकिन आज 'जन-धन खाता' होने के नाते एक-एक नया पैसा सीधे उनके खाते में जाता है।

1.00 P.M.

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 2024 तक इस देश की अर्थव्यवस्था ऐसी ही रही, तो यह आपके लिए बहुत सोचने का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सोचने का विषय नहीं है, क्योंकि माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इस प्रकार की स्थिति का निर्माण किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी - थ्री हो भी गई है, दो और की कमी है, वह भी हो जाएगी। श्रीमन्, मैं यह कहता हूँ कि माननीया मंत्री जी ने निजीकरण की बात कही है, 8 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करने की बात कही है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : कृपया आप conclude करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल : महोदय, मैं conclude कर रहा हूँ। 6 क्षेत्रों यानी हवाई अड्डे का निजीकरण, कोयला खनन - हम कोयला खनन के संबंध में इस नाते सुधार कर रहे हैं कि कम से

कम उसी बहाने भारत सरकार को मुद्रा मिलेगी। इन लोगों ने स्पेक्ट्रम भी बेचने का काम कर दिया था, जमीन तो छोड़ दीजिए, आकाश को भी बेचने का अगर किसी ने काम किया, तो यूपीए गवर्नमेंट ने किया और कोयले की दलाली में इनके मंत्री तक जेल में गए। हमारी सरकार सात साल बीतने के बाद भी साफ-साफ है। हम जो चादर ओढ़ कर आए हैं, उस चादर को वैसे ही रख कर जाएँगे। आप देख लीजिएगा, एक भी दाग उस पर नहीं रहेगा। हमारी सरकार निश्चित रूप से इस प्रकार से काम रही है। सर, आपने मुझे दस मिनट का समय दिया था।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आपके दस मिनट पूरे हो गए, इसलिए अब आप conclude करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल : सर, अब मैं conclude ही कर रहा हूँ। हमने टैक्स के मामले में भी इंस्पेक्टर राज को पूरी तरह से खत्म किया है, फेसलेस किया है। अब लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले नोटिसेज़ आ जाते थे, लेकिन अब नोटिस भी नहीं आएगा, अगर आएगा भी, तो वह प्रिंसिपल कमिश्नर के दस्तखत से आएगा। कमिश्नर भी नहीं, प्रिंसिपल कमिश्नर के दस्तखत से आएगा, बिना उसके दस्तखत किए किसी के पास नोटिस नहीं जा सकता है। इस प्रकार से पाँच स्तर से गुजरने के बाद ही कोई नोटिस आएगा और कुछ गलत रहेगा, तभी नोटिस आएगा। इस प्रकार से पूरी तरह से फेसलेस व्यवस्था कर दी गई है। पहले लोग इन्कम टैक्स विभाग को गाली देते थे, आज उस इन्कम टैक्स विभाग को भी इस सरकार ने पूरी तरह से सरल कर दिया है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, कृपया आप conclude करें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल : मान्यवर, इस सरकार ने जो जगह-जगह पर स्कूल्स खोले, अस्पताल खोले, मैं इनके बारे में बता कर अपनी बात समाप्त करूँगा। हम 100 नए सैनिक स्कूल, 750 मॉडर्न स्कूल खोलने जा रहे हैं, लद्दाख के भाइयों की शैक्षिक आत्मनिर्भरता के लिए वहाँ एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिया गया है, 'आत्मनिर्भर भारत' योजना के अंतर्गत...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : कृपया आप conclude करें, आपका समय खत्म हो गया है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल : मान्यवर, इससे सवा सौ करोड़ जनता खुशहाल होगी। इस नाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, उसको माननीया वित्त मंत्री जी ने एक रास्ता दिखाया है। अगर ये लोग उस रास्ते पर भी कभी सोचेंगे, तो भी इस सरकार को वाहवाही ही देंगे। मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, hon. Member, Shri G.C. Chandrashekhar. You have ten minutes. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, it is his birthday also today. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I see; Happy Birthday! ...(*Interruptions*)...

THE LEADER OF OPPOSITION(SHRI MALLIKARJUN KHARGE): He should then be given fifteen minutes, Sir. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): He can take one more minute. ...(*Interruptions*)...

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Thank you, Vice-Chairman Sir, for having given me this opportunity. At the time of presenting the Budget, the hon. Minister always mentions the quotes of great personalities. Those personalities are highly revered and followed by masses. So, people feel that those promises will be fulfilled without fail.

The people of Karnataka are led by the highest teachings of *Vishwa Guru* Basavanna and his Kaayaka Tatva. During the presentation of Budget of 2019-20, our Finance Minister had quoted the socio-economic principles of *kayakave kailasa* and *dasoha*. '*Kayakave kailasa*' means 'work is worship' and '*dasoha*' means 'serving food, health and education'.

Sir, the hon. Prime Minister also quoted Basavanna and his concept of Anubhavamantapa, on his 914th birth anniversary. In the 12th Century itself, Basavanna talked about the perfect model of Parliamentary system to increase the hope of the people in the Government. The people should believe that the Government will justify their promises, but the present Government failed and broke the promises, which they had made. The Government's rate of pending assurances rose from 11 per cent in the second sitting in July-August, 2014, to 89 per cent in January-February, 2019. The number of Government promises made in Lok Sabha, that have been left unfulfilled, increased by 300 per cent between the 15th and 16th Lok Sabhas. This shows how much they have followed Basavanna. This situation reminds me of a more meaningful *vachana* of Basavanna,
which says and I quote: *" Do not steal, do not kill, do not lie, do not become angry, do not feel bad about others, do not praise yourself and do not condemn others. This

---

* English Translation of the original speech delivered in Kannada.

is the purity of 'inner' and this is the purity of 'outer'. This alone is the way to win the God. It means, do not steal, do not kill, do not lie, do not become angry, do not feel bad about others, do not praise yourself and do not condemn others. This is the purity of 'inner' and this is the purity of 'outer'. This alone is the way to win the God.

Sir, since time given to me is very short, let me talk about how the Cental Government in this federal system stood with our State when Karnataka was facing problems. As you all know, Karnataka is the third highest tax-revenue generating State in the whole country. Karnataka has more than 12,000 full-time working IT companies and 750 MNCs. With this, our State contributes 40 per cent of IT revenue. It is the constitutional duty of the Central Government to help the State Governments when they are in distress. In 2018-19, Karnataka contributed Rs.79,000 crores as GST revenue. In return, we have got only Rs.10,754 crores as compensation. In 2019-20, Karnataka contributed Rs.84,000 crores and, in return, we got only Rs.18,628 crores. The Revised Estimates for 2020-21 fiscal, according to Budget documents, will result in Karnataka receiving around Rs.7,900 crores less than Rs.28,000 crores budgeted as GST devolution. The Revised Estimates project GST devolution for Karnataka at Rs.20,073 crores, which is 14 per cent lesser as compared to the previous year. Before 2019 Lok Sabha elections, the Centre had promised about Rs.39,000 crores in its Interim Budget. But in the Union Budget, presented after the elections, the Finance Minister revised the estimates to Rs.30,919 crores, that is, Rs.9,000 crores less, and the same has been further reduced in 2020-21, even before the recommendations of the Fifteenth Finance Commission came. The Fifteenth Finance Commission, to offset the loss in devolution and revenue deficit grants, recommended to the Government a special grant of Rs.5,495 crores to Karnataka for 2020-21. However, the Finance Minister rejected the recommendation and denied the grant to the State.

Sir, in the Fourteenth Finance Commission, we got Rs.44,206 crores, whereas in the Fifteenth Finance Commission, we got only Rs.31,180 crores. We got Rs.13,000 crores lesser than previous year's allocation.

Sir, as you are aware, karnataka faced three severe floods in two years. In 2019-20, during the first flood, the NDRF estimated Rs,35,000 crores as loss; second time, around Rs.4,000 crores and third time, it was Rs.15,000 crores. Out of Rs.54,000 crores, the Central Government released only Rs.2,300 crores. With this little allocation, how will the State manage the affairs? And, what about the distressed people? Sir, till today, they have not been rehabilitated properly.

Sir, till today, they are not rehabilitated properly. Sir, they are in the street even today.

About Suburban Rail, which is very essential to the Bangalore traffic, in 2018-19 Budget, the project was announced but they released only one crore rupees, and then again in 2019-20, they again announced the project and released only Rs. 10 Crores,

Sir, in the year 2014, the project cost estimated was around Rs. 12,000 crores. Now it has reached to around Rs. 18,000 crores.

Sir, I am not asking when this project is going to complete but I just wanted to know when this project is going to start.

Sir, I now explain the financial status of our State today that how it has happened.

In 2019-20, Karnataka's debt was Rs. 3.27 lakh crore. For this, we are paying around Rs. 19,000 crores as interest per annum. Sir, recently, our Karnataka CM said, "Before March, we are going to cross Rs. 4 lakh crores debt. For this, we are going to pay interest of around Rs. 24,216 crores per annum."

Sir, if the situation continues like this and also if the GST compensation period is not extended, then Karnataka will move from revenue-surplus State to revenue-deficit State. Money will have to be borrowed to even take care of salaries, administration and to service debt by leaving development activities.

Sir, I would like to quote an example. The Transport Department of Karnataka is under crisis today. During the Assembly Session last week, the concerned Minister has said, from last seven months, the State Government is struggling to pay the salaries.They paid only half salaries in December and yet to decide for the month of January. In the present situation, they could afford only fuel for the buses but not for the salaries.

Sir, the Bengaluru Metro Transportation Corporation, the BMTC, floated a tender asking the banks and financial institutions for a loan of Rs. 250 crore in December and, recently, the Department is thinking of mortgaging important valuable assets of the Department. Recently, they have mortgaged BMTC Head Office.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please start concluding.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: One minute, Sir. Unfortunately, even the Government is failing to pay the salaries of Mid-day Meal and Anganwadi workers.

Sir, Kannadigas have given 25 MPs, out of 28 MPs, to BJP Government and four Cabinet Ministers, now three. But for this, we are receiving so many gifts like this. It is our fate, I think.

Finally, about Karnataka, I would like to quote one more important promise made by the Finance Minister which is not fulfilled even today. It is regarding the IBPS exams. We have asked to conduct the exams in regional languages and also revoke the present notification as it was before 2014. But the FM has agreed to one of the demands and announced to conduct the exams in 13 regional languages on the floor of the House but till today it has not been implemented.

Sir, I will conclude in Kannada.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: * "Sir we had high hopes on Nirmala Madam, because madam comes from Karnataka, but till today she has not acted on her promise of conducting IBPS Exam in thirteen languages. Actually it's a huge insult to the people of Karnataka. Sir today Shri Anurag Thakur is here and through him and through you I would like to request the government to conduct IBPS exam in kannada."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. Please conclude.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: *"Sir I get hundreds of messages on social media, that in Karnataka 18,000 people have lost their jobs since 2014."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: "*Sir we are battling corona, people are not getting jobs and people are in trouble."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will have to move on to the next speaker. Please conclude.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: *"Thank you sir."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shri Rajeev Chandrasekhar. You have ten minutes.

---

* English Translation of the original speech delivered in Kannada.

SHRI RAJEEV CHANDRASHEKAR (Karnataka): Sir, this Budget is a landmark Budget. There is no other way to describe it. This Budget signals that the worst economic crisis that India has faced in centuries is behind it, and it marks an inflection point in the roadmap that the Prime Minister has laid out to expansion and prosperity.

Sir, I just would like to draw the attention of the House to a conversation that was happening here in September of last year. The 23.9 per cent contraction in the first quarter was used by my friends in the Opposition to create a doomsday scenario, of an imminent doomsday, about the Indian economy. But the Government was very confident that the various measures that it had put into place and public policy actions during Covid would allow the economy to recover. There was a projection that -10 per cent would be the extent of the contraction, but the reality is that even that has been surpassed, the economy has turned out to be more resilient and has recovered stronger with only a minus 7.7 per cent contraction. Sir, I just wanted to put it on record that there was a group of people here who were crying doomsday just a few months ago, and we are where we are today.

Sir, through you, I would like to inform the House and the country about a specific issue of what this minus 7.7 per cent contraction means. A minus 7.7 per cent contraction means a real loss of about 15 to 18 lakh crore rupees in the output of our economy. This is a real loss, and like any natural calamity causes losses to the economy and to livelihoods, the Covid pandemic was a natural calamity that has caused a real loss to our economy. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let us keep silence in the House, please.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: But this is a loss that is the nation's loss. This is a loss that we have to bear as a country. And so, Sir, this loss is not attributable to the fault of any State or the Centre; this loss of Rs. 18 lakh crores is directly attributable to a virus that was exported from China. So, we have to find the resources, we have to create the additional output of GDP, to bridge this loss. This once in a lifetime crisis is also a once in a lifetime opportunity to grow and rebuild the losses. Every country in the world is having to deal with the Covid-linked economic losses except, of course, China. Therefore, this Budget is about growth and jobs. This Budget is also being built on the momentum of a very strongly recovering economy post the lockdown. Government receipts are showing strong growth, through both direct and indirect taxes, indicating that there is minimum scarring in the real economy. India has received the highest FDI flows in this period and, for the first

time since Atalji's Government, we have posted a Current Account surplus. All of this has led to the IMF forecasting that India would be the fastest-growing economy in the coming year with 11.5 per cent growth. Sir, this is good news for us. It may not be the best news for the Opposition, but this is the reality of where we are today.

Sir, why is this Budget a landmark Budget? That is because it has been designed for growth; it has been designed for jobs. I don't have much time. I wanted to go into details of what the design is, but let me lay out the seven aspects of this Budget that are designs for growth. Firstly, Government spending would lead to growth and job creation; second, a big boost in infrastructure investments; third, increase Government execution capacity -- I would come to this point in a while, Sir -- fourth is, expansion in manufacturing; focus on wellness, not just wellness but wellness as a guarantor of sustained economic growth -- this is very important, just as we are recovering from a huge pandemic that has caused us huge economic loss -- and finally, financial sector expansion and transparency in budgeting.

Sir, I would just quickly touch upon a few of these points. Now, why is Government spending to lead growth and expansion and jobs so important? Why was it not possible to be done by a Government during the UPA period when they were also in a fiscal crisis? It is possible because five years of fiscal consolidation and fiscal prudence by the Narendra Modi Government in the first term has created a financial sector that is capable of fully, on its own, dealing with all the costs and all the losses of this Covid pandemic. It is an important point to understand the difference between Prime Minister, Shri Narendra Modi's approach towards economic management and the profligacy of the Government that he replaced. Sir, why do I want to touch upon 'increase Government execution capacity'? Shri Kapil Sibal, in yesterday's speech, said, 'यह सब छोड़ो, land clearance लेने में दस साल लेंगे, पांच साल लेंगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने में। During the COVID, the Government has financed and completed 217 projects from the National Infrastructure Pipeline that were kicked off only in 2019 at a cost of Rs.1.20 lakh crores. That is Government execution capacity that has been built up. सर, यहां wellness पर बहुत चर्चा हुई कि बजट यह है, बजट वह है। Just giving a simple fact. The budget for health and wellness in 2014 was Rs.27,000 crore when the UPA left. The budget today is Rs.2.35 lakh crores with an approach to wellness as a guarantor for sustained economic growth because we don't want any pandemic from China or any other country to any more derail our economy in the future. We want Indians to be well resilient and be able to combat any pandemic in the future. I think Kapil Sibal*ji* also said that there is jugglery of data. I just want to respectfully point out to the Opposition one thing. There was jugglery of data in 2014 when there were zero losses claimed; when fiscal deficit numbers were hidden in

OMC balance-sheets. This Budget shows to every Indian citizen where every rupees comes from and where every rupees goes. It sets a standard in transparency that every Indian should be proud of. Before I end, I want to touch upon three specific points that have been raised as criticisms of this Budget. First is disinvestment. I said Rs.18 lakh crores is the loss to our economy. Now this loss is real. If my friends from the Left, who are very close to China or my friends from the Congress who have an MoU with China can find a way to recover the money from China, we will not disinvest. ...(Interruptions)...

SHRI BINOY VISWAM: No, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI ABDUL WAHAB: What is this? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Abdul Wahab*ji*, please. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: If you have friends there, you please ask them to compensate India for the loss. You have the MoU, you have the relationship. You don't oppose the disinvestment then. ...(*Interruptions*)...

SHRI BINOY VISWAM: What is this?. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: This is the truth. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Rajeev*ji*, please address the Chair. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, I welcome my friends, who have MOUs and relationship with the country that exported the virus, to help us foot this loss. I leave the option open to them.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, ...(*Interruptions*)...

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, hypocrisy is the staple of opposition politics. This opposition to private sector expansion in our economy is from a party that has a long list to its track record of handing out public assets to private cronies -- 2-G spectrum, coal blocks, Public Sector Enterprise assets, land, taking contracts

away from Public Sector companies like HAL and giving them to private Italian companies and private Swiss companies for VIP helicopters and trainer aircraft. ये हमें सिखाते हैं, अपने fake socialism के साथ। ये हमें socialism सिखाते हैं। ....(**व्यवधान**).....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. WILSON(Tamil Nadu): Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

SHRI BINOY VISWAM: Sir, ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): It will be examined. ...(*Interruptions*)... Please address the Chair. ...(*Interruptions*)... Your time is almost over. ...(*Interruptions*)..

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: This is the irony of a party that talks about income inequality that created the most historic crony capitalism culture in the ten years which is called the loss decade.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...(*Interruptions*)... Chandrasekhar*ji*, please conclude. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, I just want to touch upon this textbook economics theory. The former Finance Minister yesterday talked about demand-side economics and he has been saying this for a long time. First of all, I want to remind the country of the Congress' disastrous record in this demand side economics in 2008. That cost is still being paid by the country. We know what happened to NPAs or what happened to the banking system. Simple common sense tells us today that demand is linked to consumer confidence. Consumer confidence will come when the vaccination takes place and the risk of the pandemic fades away. That is common sense. Today, if anybody looks at the data, bank deposits are growing in double digit. Which means what? People have money and they are saving it in banks. The moment consumer confidence restores after the vaccination is distributed, that saving will translate into consumption. This is common sense. This is not there in some Harvard textbook probably which is where the former Finance Minister is getting his economics knowledge. That is common sense; that is prudent economics. I will end by saying the following: This is a landmark moment in our economic history. A

chaiwalla who the Indians have made the Prime Minister has shown us that we can aspire to be a truely trusted global nation befitting our civilisational history. While the Milan pedigrees, Harvard degrees, Cambridge tennis courts, terrorists, separatists, Gretas and assorted andolanjeevis, may keep trying to slow down India's rise, let there be no doubt that Indians have rejected this politics and economics of cronyism, dynasties, fake socialism and vote banks once and for all in 2014 and will never return to that again.

India is moving from policies that arrested us to the past to the policies and thinkings that open up opportunities for the future. Atmanirbhar Bharat of a 130 crore Indians can aspire to grow, expand and play a bigger role in the changing world order. We will together, under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, continue our progress to a New India, an Atmanirbhar India, where mantra will always be *'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas'*. ...(Interruptions)...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

श्री उपसभापति : प्लीज़, बैठकर बात न करें। आप कन्क्लूड करें।

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: I am concluding, Sir. Last September, I concluded my intervention by saying this and I will repeat this today. Regardless of this deep shock in our lives and livelihoods, we must keep the faith. We must be united, we must be confident that we will prevail, we will grow and we will thrive. I end this speech, Sir, with my salute to the men and women who helped keep us safe during this pandemic. I also salute the brave men and women of our Armed Forces and para-military forces at the LAC, protecting our national integrity and sovereignty from all those that seek to violate it. Thank you, Sir. Jai Hind.

श्री उपसभापति: चौधरी सुखराम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, रूल 187 के संबंध में, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मुझे जानकारी हुई कि मेरा Twitter account withdraw कर लिया गया है, block कर दिया गया है, जबकि मेरे ऊपर ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है, जो सरकार की निगाह में गलत हो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, केवल किसानों की बातों का अनुरोध किया था, इसलिए ऐसा किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप इसका संज्ञान लें और मेरा जो विशेषाधिकार है, उसका उपयोग करते हुए जिन्होंने भी मेरा Twitter account withdraw किया है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: इसका एक due process है, इसलिए हमें आप लिखकर दीजिए। उसके बाद हम माननीय चेयरमैन साहब के पास उसको देंगे। इनके बाद मैं किसी और को इजाज़त नहीं दूंगा।

श्री दिनेश त्रिवेदी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदय, आप मुझे पांच मिनट दे दीजिए।

श्री उपसभापति : पांच मिनट का समय नहीं है। आप एक-दो मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त कीजिए। Please be brief.

श्री दिनेश त्रिवेदी: सर, बात यह है कि हर मनुष्य के जीवन में एक घड़ी आती है, जब उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है। मेरे जीवन में भी आज ऐसी ही घड़ी आई है। मैं यहां बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं? हम देश के लिए आते हैं, क्योंकि सबसे सर्वोपरि देश होता है। अभी दो दिन पहले...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

श्री दिनेश त्रिवेदी : बस दो मिनट। दो दिन पहले माननीय प्रधान मंत्री जी और गुलाम नबी आज़ाद जी - एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, दोनों की भावना देश के लिए थी। सर, आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है। जब वे रेल मंत्री थे, उस दिन में भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी कि जब निर्णय करना पड़ा था कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है या खुद अपने आप बड़े हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

श्री दिनेश त्रिवेदी : सर, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं।

श्री उपसभापति: मैं यह बात जानता हूं।

श्री दिनेश त्रिवेदी: जब मुझे Best Parliamentarian का award मिला था, तब भी मैंने यह कहा था कि मेरे गुरुजन, मेरे मां-बाप ने मुझे उस लायक बनाया। आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति है? आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। जब कोविड की महामारी हुई, तब दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। सभी ने बहुत अच्छी तरह से मिलकर यह काम किया और जैसे प्रधान मंत्री जी ने बताया कि हम 130 करोड़ थे, लेकिन नेतृत्व उनका था। मेरे कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से हमारे प्रांत में violence हो रहा है, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, उससे मुझे यहां बैठे-बैठे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं

क्या करूं? हम उस देश से आते हैं, जहां रबीन्द्रनाथ टैगोर, सुभाषचन्द्र बोस और खुदीराम जैसे महान लोग हैं। वह कविता है:*

असल में हम जन्मभूमि के लिए ही हैं और कुछ नहीं हैं। मुझसे यह देखा नहीं जा रहा है कि हम करें तो क्या करें, हम सीमित हैं। एक पार्टी में हैं, तो पार्टी का discipline है। I am grateful to my party that they sent me here. मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी आत्मा की आवाज़ आज यह कह रही है और स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, Arise, awake, and stop not till the goal is reached, तो आज मेरी आत्मा यह कह रही है कि यहां बैठे-बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि आप यहां से त्यागपत्र दो और जाकर बंगाल की भूमि में लोगों के साथ रहो।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः इसके लिए एक due process है। माननीय चेयरमैन साहब को...(**व्यवधान**)...

श्री दिनेश त्रिवेदी: मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा-हमेशा जिस प्रकार काम करता रहा, काम करूंगा। ...(**व्यवधान**)... आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः इसके लिए एक due process है। आप माननीय चेयरमैन साहब को लिखित में दें। इसके लिए एक due process है। Now, Shri G.V.L. Narasimha Rao. You have ten minutes' time.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to start my brief speech by quoting former American President Abraham Lincoln, who said, "No man has a good enough memory to be a successful liar." इतनी अच्छी याददाश्त किसी की नहीं होती है, जिससे वह कामयाब झूठा बन सके। बार-बार ऐसी कोशिश हमारे विपक्ष के द्वारा होती रही है। And, all the times, they have been making fake narratives and they try and make people believe those things but they fail because you cannot be a successful liar, as Abraham Lincoln famously said.

What is the fake narrative number one? Sir, in both the Houses, I have heard speakers saying that India's billionaires have suddenly become rich as if this has happened in the last five, six years, and, they often quote Oxfam Report. Let me quote from Oxfam India Inequality Report of 2018. What does it say? Four out of ten Indian billionaires have inherited their wealth and other six have actually acquired wealth, accumulated wealth, and, in 2010, 27 out of 69 Indian billionaires have

---

* Hon'ble Member spoke in Bangla.

accumulated wealth from the rent-thick sectors like the 2G spectrum, the 'coalgate' and things like that. The Report cites, rent-thick billionaires who account for 43 per cent of Indian billionaires have accounted 60 per cent of total billionaire wealth. I am quoting from the Report. Clearly, the wealthiest in India have made their fortunes from crony-capitalism rather than through innovation or rules of the market and the Report cites spectrum scam, coal scam. So, all the billionaires, whom you claim that they have suddenly become rich, have become rich during the UPA-era. So, the fake narrative busted.

The second fake narrative is that there is huge unemployment post-Covid now. You make it look as if unemployment continues to be a major challenge. It has always been a challenge but today, let me give you the numbers from the CMIE, which many of you love to quote. This is the CMIE Report of January, 2021. India's unemployment rate in January, 2021 is 6.53 per cent. It is much better than pre-Covid period. In March, 2020, before the lockdown, it was 8.75; in February, 2020 it was 7.76; and, today, it is only 6.53 per cent. Employment has come back but you still choose to quote the numbers of May, 2020 when the country was in lockdown. So, the fake narrative number two that there is huge unemployment in the country is busted.

Now, let me come to fake narrative number three. 'Universal cash transfers' is a remedy for all the problems. Particularly the main opposition party has this solution to offer. Even we have done cash transfers to the poor. More than two lakh crore rupees have been transferred to more than twenty crore people who need this kind of cash transfer. But the countries which have done universal cash transfers, only their savings rate has gone up. Their household savings vis-a-vis GDP ratios are perhaps at the century's highest. So, this has not resulted in spending. So, your so-called great economics, 'give money in their accounts, they will immediately spend', has been proved wrong. In fact, Modinomics has triumphed because we are able to generate employment; we are able to bring the growth back into the economy. As my colleague said, we have the projection of the highest growth in the next year. This is what World Economic Outlook, January, 2021 says. We will be the fastest growing economy in 2022. And the global business confidence has come back. Throughout the world, there is a concern about future business growth. In the US, in Japan, in Europe, the business confidence indices are all down. But in India, it is very much up. The global worries are about inflation. We have been able to contain inflation even during these periods. This is *The Economist* of yesterday - 'how rising inflation could disrupt the world's economic policies.' It says how countries which have given

large cash transfers are going to experience the worst inflation in many decades. So, your cash transfer theory is again busted.

I would now like to talk about investment. We are the only country in the world today to have the highest FDI inflows. This is Investment Trends Monitor, UNCTAD report. In developed economies, they are down by 69 per cent. India is the only country which has positive FDI inflows of 12 per cent. So, your next claim is also busted.

Let me now talk about the other claim made here about PSU privatisation. I think some Member said, 'you are actually selling the country.' These are very uncalled for and unfortunate comments, and they actually ought to have been removed. Let the country remember, जो सदस्य यह बात कह रहे हैं, आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लगते हैं असेम्बली सीट बेचने का, पार्लियामेंट सीट बेचने का, इसलिए देश के नाम पर जब हम संसद में बोलते हैं, we expect you to maintain some dignity. ऐसे असत्य बोलने से ...(**व्यवधान**)... हम यह आपकी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी और पार्टी के लिए बोल रहे हैं।

श्री उपसभापतिः प्लीज़, आपस में बात मत करिए।

SHRI G.V.L. NARSIMHA RAO: Sir, similar allegations were made by the speakers from the main opposition party. So, I think it is important that we conduct our debates in a dignified manner. We can throw the same allegations against you. I have tried hard with a number of data points, recent reports with references, but the Opposition does not want to understand. They don't understand when we speak in Hindi; they don't understand when we speak in English. हमारे कुछ मित्र संस्कृत में भी बोलते हैं, वे भी नहीं समझते हैं। So, let me now try something in Italian.

" chi e' senza peccato scagli la prima pietra "

What does it mean? It means people who commit sins should not be throwing stones. I think people who have committed mistakes, people who have committed blunders, people who have actually indulged in crony capitalism, people who have actually ensured that billionaires become much richer, they should not make allegations against the Government that is actually inclusive, pro-people, which has cared for the people who are in the lowest of the economic pyramid. So, now that I have advised our friends in a language they may possibly want to understand, let me say this. India is developing rapidly in every sector under Prime Minister Narendra Modi *ji*'s leadership in a mission mode. Today, when we say 'mission mode', we

refer to something happening at a very rapid pace. I think it would now be apt to say 'mission Modi'.'Modi' means 'fast'. 'Modi' means 'growth'. 'Modi' means 'a huge advancement'. The world will have to increasingly look towards India and 'Mission Modi' for its inclusive growth and for alleviation of poverty. Because we have shown to the world during the crisis of COVID period how we can really take care of the most vulnerable sections through cash transfers, how we can trigger faster economic growth, and how we can ensure that India's growth story really becomes much more successful after this COVID challenge. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति : श्री सैयद जफर इस्लाम, आप बोलिए। आप बैठकर बोल सकते हैं।

SHRI SYED ZAFAR ISLAM (Uttar Pradesh): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. I am sure you will not consider this as my maiden speech because I am a newcomer. You have promised that all the newcomers will get the opportunity to speak on the subject of their choice at a later stage.

श्री उपसभापति : सैयद जफर इस्लाम जी, आप बैठकर बोलिए। इससे आपको माइक की सुविधा मिलेगी और आवाज भी आएगी।।

SHRI SYED ZAFAR ISLAM: Sir, I take this opportunity to thank hon. Prime Minister, hon. Home Minister and my hon. Party President for having given me the opportunity to be here in front of all of you and to speak on this subject.

Sir, this year's Budget was presented in the most difficult times. Everybody has spoken about it. We had COVID; we had a lockdown; and there were no revenue streams. Revenue streams were completely shut. Then we had a huge expenditure to take care of the needy, those who needed support from the Government. And the Government had to spend because this is a sensible and responsible Government. We had to deliver. If I say that this was the worst time to present the Budget in the history of entire free India, probably I would be right, because she had a lot of problems to tackle. Yet she had presented it. She made a commitment that she would deliver the Budget of the century. She has not just delivered on her promise. But she has exceeded her promises as well.

Sir, let me remind you that the people have spoken about the growth number; the people have spoken about the IMF Report; and the people have spoken about the contraction in the economy. We all have spoken about it. Of course, personally I feel this is a thing of the past. Because now our economy is back in order and everything is looking very, very positive. This year's Budget is primarily a blueprint for the future

growth. We all aspire to see this kind of Budget. We are able to see this Budget purely because of the farsightedness of hon. Prime Minister and hon. Finance Minister.

This Budget, I personally feel, is a Budget for the entire nation, for everyone and more particularly for the areas which had been neglected by the previous Government. I am talking about the East in particular. The Budget also demonstrates *Purvodaya*. Nirmala Sitharaman *ji* has considered it and so a lot of opportunities are being created for the Eastern part of the country which has been neglected in the past.

Sir, some of the hon. Members like Kapil Sibal *ji* had raised a few issues. He had particularly mentioned about the *atmnirbharta* of minorities, *atmnirbharta* of farmers, *atmnirbharta* of the SCs and the STs, and *atmnirbharta* of the MSMEs. I can give enough data on other things. But my colleagues have spoken about it. Coming from a minority community, I would like to remind this to the hon. Member, Shri Kapil Sibal *ji*. When you say *atmnirbharta* or *atmnirbhar,* did you really make the minority community *atmnirbhar* or deeply dependent or make them struggle? If you say that I am making this kind of allegation, then I will request you to see the Sachar Committee Report, because it is a reflection of what you have done and how you have mistreated the community. Today, there is a Government which believes in the model of good governance. This is something which is visible, because this Government has believed in taking care of every citizen of this country, not because of any particular religion. There is no preference. It is fairness. Good governance suggests fairness and effectiveness. And if you really want to analyse the model of good governance, you see that we have been fair. This Government has been fair. We did not see the name of the beneficiary. We did not see what caste, creed or community they belong to. It is the citizen which needs support from the Government. And the 450 welfare schemes, which have been launched under the leadership of hon. Prime Minister, have effectively gone to every citizen of the country which needed those kinds of schemes. I must tell you that the DBT was used to make it effective. An amount of Rs.822 lakh crore was transferred in the last five years through DBT, which is 60 per cent of the welfare schemes, which has been delivered to our needy citizens. This is something which is huge compared to any other country and any other standard.

Sir, hon. Kapil Sibalji also observed one very important thing. He mentioned industrial investment growth. He gave numbers in percentage for five years of UPA-1, five years of UPA-2 and five years of NDA-1. He is a lawyer. I understand but very conveniently, he forgot to mention that at inception, what was the industrial

investment growth rate and at the end, when he left the Government, what was the industrial investment growth. Sir, I want to tell everyone and we must know. I will tell a story because I used to be a banker. There are certain stories which we must know and this august House must know because it is something which was completely misleading. When we left the Government in 2004, industrial investment growth was not in double digits, it was in upper double digits. When they left the Government, it was 1.6 per cent. When they calculate the average, they do not take this into account. What does that mean? जब हमने 2004 में सरकार छोड़ी थी, तो उस वक्त हम चंगे थे, हमारी economy चंगी थी और जब उन्होंने छोड़ी, तो हमारी economy ICU में थी। हमने policy paralysis के बारे में सुना है, अभी कोई बात कर रहे थे कि economy is in a bad shape. मैं उनको 2013 की बात याद दिलाना चाहता हूँ, जब आपको FCNR(B) Bond करना पड़ा, because economy was in a bad shape and the currency was in a bad shape. It was a freefall for the currency. We had to do it and today, just see the numbers. Take, for example, the foreign currency reserve. It is double. You had 296 billion; today, we have around 600 billion. For the first time, in the last sixteen years, we have a positive current account. We have very important numbers. If you see FDI, for ten years, you could attract only a quarter trillion dollars and in only seven years, we already have half-a-trillion dollars. That suggests about the economic policy of our Government.

Sir, Mr. Sibal talked about credit growth. He spoke about percentage terms in exports and percentage terms in imports. सर, import कम हुआ, तो अच्छा ही हुआ है। Import कम हुआ, उसकी वजह है कि हमने देश को आत्मनिर्भर बनाया। इसलिए import कम हुआ है। Percentage अच्छा है, आप उसका ज़रा ठीक से मुआयना कीजिए, अच्छा लगेगा। अगर आप उसको ठीक से देखेंगे, तो आपको देश के हित में बोलने का मौका मिलेगा। अगर आप percentage growth की बात करें, तो export में यह जो थोड़ा कम हुआ है, यह marginally कम हुआ है, ज्यादा कम नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है, जैसा हमारे सुधांशु जी ने कहा कि उस वक्त global economy में contraction हुआ था। India is not working in isolation. It is a part of the global economy; it is an integrated economy. इसलिए जब वहाँ contraction हुआ, तो यहाँ भी contraction होना ही था। जब global trade में contraction हुआ है, तो यहाँ भी export में फर्क पड़ना था। साथ ही जब global trade में चीन और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, सबको मालूम है कि उस वक्त पूरी दुनिया में उसका impact हुआ था, तो यहाँ भी impact हुआ था। ज़ाहिर है, थोड़ा marginal impact हुआ था, लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने policy लगाई है, जब हमने 13 सेक्टर्स को incentive scheme दी है, सरकार ने बहुत सारे अलग initiatives लिए हैं, policy decision लिया है, bold decision लिया है, उससे economy में सिर्फ अच्छा ही नहीं होगा, बल्कि हमारा export भी बढ़ेगा। हमने बहुत सारे ऐसे decisions लिए हैं, जिनसे बाहर की कंपनियाँ, जो अब तक सोच रही थी कि China Plus One कहाँ रखूँ, वे इंडिया में आ रही हैं, क्योंकि हमने tax rate कम कर दिया है। हमने ऐसी incentive scheme शुरू की है, जिससे हमारे exporters world में competitive बन जाएँ और जो बाहर की दुनिया की कंपनियाँ यहाँ निवेश

करें, वे यहाँ पर competitive रहें। वे हमारे यहाँ निवेश करें, क्योंकि हमारे पास cheap labour है, हमारे पास demographic dividend है, वे उसका भरपूर फायदा लें। इस तरह से उस decision के अच्छे नतीजे आ रहे हैं।

सर, उन्होंने कहा था कि credit growth नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 2008 से 2012 के बीच में अगर आप बैंक की balance sheet को analyze करेंगे, तो उस वक्त आपके बैंक की balance sheet, 1947 से 2008 तक सिर्फ 18 लाख करोड़ थी। उसके बाद 2008 से 2012 के बीच वह 54 लाख करोड़ हो गई। मतलब यह three times हो गई। सर, इससे यह समझ में आता है कि आपकी कंपनी उस हालत में नहीं थी, जिस तरह से आप loans freely बाँट रहे थे। सब लोगों ने, जिसने भी 'कौन बनेगा करोड़पति' देखा होगा, उस वक्त phone-a-friend चलता था। Phone-a-friend से economy बरबाद हो गई। उस phone-a-friend से NPA की जो problem है, उससे देश आज भी जूझ रहा है। आज निर्मला जी को बैंक bad asset नहीं बोलते हैं, जो Asset Reconstruction Company बनाई है। हमें Asset Management Company इसलिए बनानी पड़ी कि उस वक्त के पाप आज धुल रहे हैं।

सर, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि उस वक्त क्या किया गया था? मैं Opposition को challenge करता हूं, अगर वे मुझे गलत साबित कर दें। आप उस वक्त की कम्पनीज़ को जाकर देखिए, जिनको लोन दिया गया था। वह लोन किस बेसिस पर दिया गया था? There is a credit evaluation process. There is a method to madness where, actually, when you lend, you have to follow some process. इसमें जो सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, when you evaluate a credit, you discount all the future cash flows at a discounting rate, जिस पर lend कर रहे हैं। उसके बाद अगर EBITA positive आता है, तो उसका मतलब है कि उस company में जान है।

सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन कम्पनीज़ में जान ही नहीं थी, EBITA negative companies को धड़ाधड़ लोन दिए गए। किसलिए दिए गए? इसलिए दिए गए, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया, 'phone a friend'. 'Phone a friend' के कारण उनको धड़ाधड़ लोन दिए गए, जिसकी वजह से बैंकों की यह हालत हो गई कि बैंक पैसा pay ही नहीं कर सकते थे। उनके पास pay करने की क्षमता ही नहीं थी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, तो there is a report, which is not published by any Indian institution, not published by my company but it is published by a foreign bank which is called Credit Suisse. 'House of Debt' is a report, which, I think, everybody should read. You must know what exactly has been done during those four years.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, former Finance Minister कल fiscal deficit की बात कर रहे थे, लेकिन उनको इस सम्बन्ध में और चीज़ें भी देखनी चाहिए थीं। Fiscal deficit के बारे में हमारे बाकी वक्ताओं ने बताया कि हम उसमें कैसे transparency लाए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर globally हम fiscal deficit को

देखेंगे, तो हम फिर भी बहुत अच्छी हालत में हैं, despite the fact कि जो below the line items थे, उनको इस बार हमने सीधे fiscal deficit में दिखा दिया। अगर हम historically इसे देखें, तो अलग-अलग corporate में डाल कर वे बराबर इन चीज़ों को छुपाते रहते थे, लेकिन fiscal deficit में नहीं दिखाते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, मैं एक मिनट और लूंगा, मुझे यहां पर पहली बार बोलने का मौका मिला है, इसलिए मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए।

श्री उपसभापति : देखिए, अभी मेडन स्पीच का अवसर नहीं है। You have to conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर globally अब के समय के fiscal deficit को देखा जाए और जब उनके समय में fiscal deficit था, उसको देखा जाए, तो उनका 5.4 average fiscal deficit रहा है, वहीं हमारा fiscal deficit 3.67 था। इस बार पहली बार हमने यह किया है, because of extraordinary situation...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मैं दूसरे स्पीकर का नाम बुला रहा हूं।

श्री सैयद जफर इस्लाम : Extraordinary situation में fiscal deficit बढ़ा है, but fiscal roadmap पूरा clear दिया गया है। हमने उसमें दे दिया है कि कहां से कब यह काम होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, मैं 10 सेकंड और बोलूंगा। मैं अपने मित्रों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एक कोर्स है, 'Master Of Developing India'. I think, आप लोगों को इस कोर्स को ज़रूर समझना चाहिए। अगर अब तक नहीं पढ़ पाए हों, तो पढ़िए। 'Master Of Developing India' का मतलब है 'MODI'. I think, you should understand...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over, Sir. Thank you. माननीय महेश पोद्दार जी।

श्री महेश पोद्दार (झारखंड) : आभार रूप उपसभापति महोदय, समय कम है, मुझे भी और सरकार को भी सरकार को समय कम क्यों है, यह बात मैं बाद में बताऊँगा। सदी की सबसे बड़ी आपदा में और मौजूद परिस्थितियों से निपटते हुए, भविष्य के लिए उम्मीद पैदा करने के लिए

सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का और बहन निर्मला जी का अभिनन्दन महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की इन पंक्तियों से करना चाहूंगा,

"किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है,
है अँधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है ।।"

महोदय, सड़क किनारे की वो अम्मा, जिसकी माननीय प्रधान मंत्री जी ने चर्चा की थी, उसने भी विश्वास का दीया जलाया था। महोदय, 'यह कहानी है दीये की और तूफ़ान की' और मुझे गर्व है कि हमने न केवल दीया जलाए रखा, बल्कि उसे बचाए भी रखा है।

महोदय, इस बजट की बहुत सारी खूबियां हैं, जिन पर एक-साथ चर्चा करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि समय सीमा की एक मर्यादा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर क्षेत्र के लिए बजट में कुछ न कुछ है। किसी ने कहा कि बजट में 'defence' शब्द नहीं है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि शब्द की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश already defended है। कल हम सबने रक्षा मंत्री जी के वक्तव्य पर मेज़ें थपथपाई थीं, इसलिए हम फिर यह बात कह सकते हैं कि हम defended हैं।

महोदय, इस Budget of hope के मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका यह होगा, हालांकि हमने काफी विस्तार में राजनीतिक पंडितों से अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में सुना, लेकिन मैं अपने कुछ business leaders की सार्वजनिक टिप्पणियों को सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। ये टिप्पणियां हमारी बहस को सम्पूर्णता की ओर ले जाएंगी, क्योंकि उनको धंधे का काफी ज्ञान है, इसलिए उनकी टिप्पणियां भी काफी महत्वपूर्ण है। Sir, Shri Uday Kotak, President, CII has said, "Budget presentation marks an ongoing process rather than a one-off approach in making the recovery process more robust and equitable." श्री दीपक जैन, प्रेसिडेन्ट, एक्मा, जो ऑटोमोबाइल कम्पोनेन्ट्स की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने कहा - "It is also heartening that the Budget Outlay for the MSME sector has been doubled. The auto component industry is dominated by MSME." श्री दिनेश कुमार खारा, चेयरमैन,एसबीआई ने कहा, "The Budget has rightly envisaged a substantial jump in capital expenditure that has a strong multiplier impact on the economy." Shri Deepak Goradia, President, Maharashtra Chamber of Housing Industry ने कहा, "This Budget will continue to provide support to accomplish the 'Housing for All' Mission."

अगर हमारे कुछ मित्रों को देसी बिज़नेस लीडर्स से अधिक विदेशी बिज़नेस लीडर्स से प्रेरणा मिलती हो तो बजट पर उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लें। Gerry Rice, Director of Communications at the International Monetary Fund (IMF), "We welcome the Indian Government Budget's focus on growth. Fiscal policy can and should play an important role in facilitating a strong and inclusive economic recovery." Mr. M. Nugent, V.P., Financial Services at US-India Strategic Partnership Forum," उन्होंने कहा - "The FY22 Budget, Finance Minster Sitharaman unveiled on February 1 presents a credible policy framework for the coming fiscal year and an important shift

from short-term disaster relief to medium-term economic recovery." The Wall Street Journal उन्होंने लिखा, Sir, called the Budget's expenditure outlay "ambitious", highlighting the importance of spending on infrastructure, roads, health and education to bring the country back to high growth. Their reportage claimed that stocks jumped on the news of the Budget as investors had not foreseen such a large expenditure outlay. Therefore, I would say that it's a Budget of hope, ambition, future, growth, health, better infra and much more. We are springing back after every pause. It was just a pause but it was a forced pause on us. We all know wisdom of stock market pundits. They are not Harvard educated but record sensex, record forex reserves, complete the story for the moment and the journey is on.

महोदय, इस देश में सर्वहारा के नाम से राजनीति करने वालों ने सर्वहारा गरीबों को झंडे दिये, नारे दिये, परन्तु जिन्हें हम पूंजीपतियों की पार्टी बोलते हैं, उन्होंने उन्हीं सर्वहारा वर्ग को घर, बिजली, पानी और गैस भी दी और कोई इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन-स्तर में काफी ड्रामेटिक सुधार इन पिछले 6 सालों में हुआ है।

महोदय, हवाई यात्रा सुविधा में जो विस्तार हुआ, वह किसने किया? एयर इंडिया ने तो नहीं किया, निजी क्षेत्र ने किया, लेकिन कुछ लोगों का दिमागी दिवालियापन देखिये, आज भी चाइना के निजी क्षेत्र की प्रशंसा करते हैं, उनकी उपलब्धियों का गुणगान करते हैं, लेकिन अपने निजी क्षेत्र की उपलब्धियों की बात करेंगे तो कहेंगे - लूट लिया। हर धंधा करने वाला वैल्थ क्रिएट करने वाला लुटेरा होता है, इस संकीर्ण भावना से हमें निकलना पड़ेगा। वैल्थ क्रिएटर का समाज में सम्मान भी होना चाहिए।

(सभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

श्री सभापति: महेश जी, अब आपको समाप्त करना पड़ेगा, दो बजे मंत्री जी का रिप्लाई है।

श्री महेश पोद्दार: सर, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। हम तो बचपन से यह भाव रखते हैं कि हम सब भारत मां के सपूत हैं, आज यहां पर कपूत और सपूत की बात हो रही थी। हम सबमें भारत मां का खून है। कौन यहां सपूत है और कौन कपूत है, यह कौन बोल रहा है, उन्हें यह अधिकार किसने दिया? चूंकि आपने मुझे कह दिया कि जल्दी खत्म करना है, इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि दरअसल सरकार की आर्थिक आयोजना में जो फ़र्क आया है, वह संस्कारों की वज़ह से है। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण भवन है - यह जिस सड़क पर है, पहले उसका नाम रेसकोर्स रोड था। रेसकोर्स यानी जहां लोग घोड़ों पर दांव लगाते हैं। अब वह सड़क लोक कल्याण मार्ग के नाम से जानी जाती है। नाम का यह बदलाव दरअसल उस भवन में निवास करने वाली हस्ती के उद्देश्यों और लक्ष्यों में बदलाव का सूचक है और वह लक्ष्य पंडित दीनदयाल जी के 'एकात्म मानववाद' अंत्योदय से प्रेरित है।

श्री सभापति: पढ़ना नहीं है।

श्री महेश पोद्दार: संघ के विचारों से कई लोग चिढ़ सकते हैं, लेकिन उनसे चिढ़ने से कुछ बनता-बिगड़ता नहीं, अंत्योदय का जो लक्ष्य इस सरकार ने निर्धारित किया है - वह सार्वजनिक है, अलानिया है और इसमें उन्हें कोई संकोच नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है।

2.00 P.M.

महोदय, हमारे झारखंड की जनता इस बात से खुश है कि हमारी सरकार ने वर्षों से पिछड़े हुए वर्ग के उत्थान के लिए 7,524.87 करोड़ रुपये का बजट दिया है, जो कि tribal affairs के लिए अभी तक का सबसे ज्यादा Budget allocation है। महोदय, साथ ही अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिए 750 एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल्स का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रौशन होते हैं। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार एक नये भारत, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया की फैक्टरी भारत, विश्वगुरु भारत की रचना के यज्ञ का आह्वान कर चुकी है। विघ्न-बाधाएँ भी आयेंगी, समर्थन के सुर भी आयेंगे, जिनकी जैसी भूमिका होगी, इतिहास उन्हें याद करेगा और उनकी भूमिका को भी याद करेगा। मैं तो यही चाहूँगा कि इस सदन में बैठे हरेक माननीय सदस्य को हमारी भावी पीढ़ी 'आत्मनिर्भर भारत' का शिल्पकार माने। आप सकारात्मक आलोचना करें, सुझाव दें। 'अन्त्योदय' का दायित्व जितना हमारा है, उतना ही आपका भी है। मेरा पूर्ण समर्थन इस बजट को है, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। जो समय का पालन करेंगे, मैं सदा उनको याद रखूँगा। ...(**व्यवधान**)... Now, Shri Vivek Thakur. You have to complete in five minutes. आपको आगे देखेंगे।

श्री विवेक ठाकुर (बिहार)**:** सर, मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की 'रश्मिरथी' की कुछ पंक्तियों से अपनी बात प्रारम्भ करना चाहूँगा। समय का अभाव है और मैं अन्तिम वक्ता भी हूँ।

"सच है, विपत्ति जब आती है,
कायर को ही दहलाती है,
सूरमा नहीं विचलित होते,
क्षण एक नहीं धीरज खोते।
विघ्नों को गले लगाते हैं,
काँटों में राह बनाते हैं।
मुँह से न कभी उफ़ कहते हैं,
संकट का चरण ना गहते हैं।
जो आ पड़ता सब सहते हैं,
उद्योग-निरत नित रहते हैं।

शूलों का मूल नशाते हैं,
बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं।"

महोदय, आज इस landmark Budget पर आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, मैं यही समझता हूँ कि यह कालखंड जब इतिहास के पन्नों में जायेगा, तो मानव विपत्तियों का एक ऐसा कालखंड लिखायेगा, जिसके बाद, इस बजट के बाद, पूरी दुनिया की, विश्व के एक नये world order की नींव रखी जा रही है। सभापति महोदय, यह बजट बहुत मायनों में अलग है, क्योंकि यह एक complete directional change का बजट है। यह सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है, भारतीयता की झलक के साथ है, जिसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, अन्तिम का उदय हो और 'आत्मनिर्भर भारत' का निर्माण हो, यह ऐसा बजट है।

चेयरमैन सर, तुलनात्मक स्थिति का निर्माण लगभग इसी तरह 1933 में Great Depression के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था में देखने को मिला था, जिसमें contraction के साथ-साथ बेरोज़गारी 4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक चली गयी थी। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट ने हिम्मत करके अमेरिका को पुनर्जीवित करने के लिए एक नयी नीतिगत व्यवस्था निर्मित की, जिसे 'New Deal' बोला जाता है। The New Deal focused on three yards; relief for the poor and unemployed; recovery of the economy and reform of the financial system that had all but collapsed. Apart from an expansive monetary policy and injecting liquidity into the banking system, Roosevelt launched a major programme to build infrastructure, including roads, schools, dams, airports and hospitals to provide jobs and income to unemployed millions, and the devastated America sailed through.

महोदय, 2020 का यह जो pandemic हुआ है, इसने विश्व की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को झकझोर दिया है। हमारा GDP 40 सालों में पहली बार negative हुआ है और लगभग 122 million लोग इस lockdown में बेरोज़गार हुए हैं। प्रधान मंत्री मोदी जी के पास negative GDP growth के पूर्व के चार उदाहरण थे - 1958 के, 1966 के, 1973 के और 1980 के, लेकिन इन सभी चारों उदाहरणों के समय havoc इतना बड़ा नहीं था। इस विपत्ति ने पूरी सोच और मन:स्थिति को परिवर्तित कर दिया है और भारतीय स्थिति की 'New Deal' की कल्पना की गयी है, जिसमें wellness and wealth पूरे राष्ट्र के हित में समाहित हैं।

महोदय, पिछले दो दिनों से बजटीय चर्चा भी चल रही है। तरह-तरह की बातें आयी हैं और अलग-अलग स्वर देखने को मिले हैं। पूरे माहौल में स्थिति में सुधार है, कोरोना से डर भी समाप्त है और आन्दोलनजीवी भी दिख रहे हैं, आलोचनाजीवी भी दिख रहे हैं। कल भारत के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब यहाँ बोल रहे थे। Sir, I am a new Member to the House but I did not like the language that he used with regard to the hon. Finance Minister. It was an extreme case of rudeness when he said that he knew it, the Corona did not come because of you and it is not going because of you. Sir, I am too small a person and too new a person to say anything on such a knowledgeable person. But, all I would like to say is that he should have been gracious enough to also say that because of

whom, we all are living, we are seeing the Corona going; the Covid management of Prime Minister, Mr. Narendra Modi. सर, आज हम लोग जिस बजट की चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले भी तीन-चार मिनी बजट आ चुके हैं। कल उन्होंने डा. गीता गोपीनाथ की भी चर्चा की। उन्होंने यह सुझाव हेतु कहा, लेकिन यह नहीं बोला कि डा. गीता गोपीनाथ ने IMF की अपनी रिपोर्ट में यह कहा, यह रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा, 'Indian economy to be fastest growing at 11.5 per cent in next financial year'. उन्होंने यह भी नहीं कहा कि ऐसा गीता गोपीनाथ ने क्यों कहा। खैर...

Sir, this Budget reflects due to the pandemic to convert crisis into an opportunity with a complete change of approach that the Government seems to be betting on the front-foot, not at the expense of equitable growth, fiscal prudence but by spending, being conscious of the fact that even if the fiscal deficit balloons from 3.5 per cent to an estimated 9.5 per cent for financial year 2020-21 with an absolute focus on growth and employment. It is a changed approach. The markets have reacted euphorically to the Budget. But, we have all forgotten so far that we are in the second year of a global pandemic. This Budget provides a foundation for the country that India will be in the next decade and signals some move to return India to a higher growth trajectory. अगर फंडामेंटल लेवल पर देखें, तो आज ग्रोथ को fiscal consolidation के ऊपर चुनना sensible निर्णय है, क्योंकि इंडिया का per capita GDP बहुत low है and it continues to hover around 2,000 dollars.

सर, मैं प्रोविज़न्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूँगा, बहुतों ने capital expenditure, रेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, डीएफआई, स्वास्थ, well being आदि सबके बारे में बोला है, लेकिन बिना पूर्वोदय के भारत का सही उदय नहीं हो सकता है और प्रधान मंत्री जी ने निरंतर इस बात को कहा है, किया है और वे इस बात के लिए जीते हैं। हम पूर्वोत्तर भारतीय हैं और हम प्रधान मंत्री जी का भरपूर आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम आज तक कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि 'One Nation-One Gas Grid' से बिहार में भी गैस मिलेगी, 'One Nation-One Ration' से हमारे श्रमिक भाई जहाँ जाएँ, वे वहाँ राशन पाएँगे, दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा, functional भी हो जाएगा, घोषणा तक सीमित नहीं रहेगा, पटना में AIIMS as Centre of Excellence होगा, ICMR की हाई पावर्ड संस्था होगी, मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का 200 बेड्स का कैंसर हॉस्पिटल खुलेगा। सभापति महोदय, यह नहीं सोचा था। यही हाल सभी पूर्वोत्तर राज्यों का है और इस बार पश्चिमी बंगाल भी विकास का नया अनुभव महसूस करेगा। जनहित में सिर्फ अवरोधक न खड़ा किया जाए।

MR. CHAIRMAN: You have one minute more to speak.

श्री विवेक ठाकुर : सर, मैं एक चीज़ ही बताना चाहूँगा, मैंने आपके आदेश के अनुसार काफी चीज़ें छोड़ दीं और वह यह है कि एग्रीकल्चर लॉ को लेकर हाहाकार है। मैं लॉ पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। It is a typical case, as former Finance Minister, Arun Jaitly*ji*, once said in this

august House, it is a case of rent-a-cause for agitation. सर, मैं कुछ figures बताना चाहता हूँ। India's farm sector is a plateful of paradoxes. मैं शुरुआत करता हूँ। भारत दूध, ऑयलसीड्ज, दाल, कॉटन, आम, पपीता और केला के मामले में दुनिया का largest producer है। इसके साथ ही भारत चावल, चीनी, चाय, सब्जी और मछली के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा producer है। आज भी एफसीआई के गोदाम में, कोरोना काल में बाँटने के बाद भी जितना गेहूँ और चावल है, उससे अगले दो साल पीडीएस पर आश्रित परिवारों को खिलाया जा सकता है। शायद यह सुनने में सुखद लगा होगा।

सर, अब contradiction सुनिए। जब भारत आज़ाद हुआ, तब जीडीपी में कृषि का शेयर 54 प्रतिशत था और आज उसका शेयर 17 प्रतिशत है, लेकिन वह देश के 56 प्रतिशत वर्कफोर्स को employ करता है। समय बीतने के साथ cultivable land का साइज़ भी टूटता गया और आज 87 प्रतिशत किसानों के पास वह औसत मात्र 2 हेक्टेयर तक रह गया है। पिछले दस साल में एक कृषक की कृषि से आमदनी, जिसको real income कहते हैं, वह जस की तस है और आज 52.5 प्रतिशत भारतीय किसान कर्ज में है। प्रति कृषक परिवार औसत कर्ज 1.04 लाख रुपए है, जो शहरी परिवार से 36 प्रतिशत ज्यादा है। सर, यह सारा डेटा भाजपा की किसी पत्रिका का नहीं है, बल्कि नाबार्ड के 2016 की report on rural Financial Inclusion का है।

MR. CHAIRMAN: Right, Vivek; please.

SHRI VIVEK THAKUR: Sir, I am about to finish in two minutes. According to National Crime Records Bureau Report...

MR. CHAIRMAN: No, you cannot take time for yourself.

SHRI VIVEK THAKUR: Sir, I am just concluding. सर, कृषि से संबंधित 28 व्यक्ति प्रतिदिन सुसाइड करते हैं। यह वर्ष 2019 में भी देखा गया। एग्रीकल्चर में private funding is only 2.4 per cent; public sector funding is 19.4 per cent और कृषक का घर का लगा हुआ पैसा 78.2 परसेंट है। सर, perishables के export का क्या हाल है, वह मैं नहीं बोलूँगा। इन हालातों के बाद अवरोध पैदा करना -- ठीक है, हम और आप तो सुलट लेंगे, लेकिन उस बेचारे किसान का क्या होगा? यह भारत की किसानी का डेटा नहीं है। यह आज की अध्ययन की हुई कृषक जन्म कुंडली है। "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" भी इसी सोच के तहत जनवरी, 2018 में आई और दस करोड़ से ऊपर किसानों के खातों में 6,000 रुपए निरंतर जा रहे हैं। इस पर उन्होंने विश्वास किया है और आपके 72,000 को नकारा है।

श्री सभापति : प्लीज़।

श्री विवेक ठाकुर : सर, मैं खत्म कर रहा हूँ। कोविड वैक्सीन की बहुत बात हो गई, लेकिन एक बात किसी ने नहीं कही कि इस बजट के मार्फत pneumococcal vaccination भी राष्ट्रव्यापी होने

जा रहा है। इसके अभाव में 50,000 बच्चे सालाना मौत के घाट उतर जाते हैं और कोई चर्चा भी नहीं होती है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। सर, अगर R&D की बात करें, तो इसके लिए इसमें 50,000 करोड़ के NRF की स्थापना की बात है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI VIVEK THAKUR Sir, I am just concluding, the last point. सर, disinvestment के विषय में एयर इंडिया की बहुत बात होती है कि बेच दिया, बेच दिया। अगर maintenance को जोड़कर एक एवरेज एयरक्राफ्ट की बात करें, तो ideally सवा पाँच सौ से छः सौ लोगों का employment होना चाहिए और जब इनका राज था, तब per aircraft 3,200 लोगों तक पहुंच गया था। अब इन हालात में पीएम मोदी को तो जनता ने चुनकर 2014 में बैठा दिया है। अगर 70,000 करोड़ का ऐसा legacy baggage दिया है, तो इसे disinvest करना होगा या नहीं, यह सदन तय करे। आप कहेंगे, बेच दिया और हम कहेंगे, क्यों किया सत्यानाश?

श्री सभापति : प्रहलाद जोशी जी हैं? ऐसे youngster वक्ताओं को पहले ही मौका देना चाहिए था। Hon. Members, I want to say that 48 hon. Members of the House have taken part in the Budget discussion. Now, I will call upon hon. Minister of Finance, Shrimati Nirmala Sitharaman to reply to the Debate.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, as you in time pointed out, about 48 Members have spoken and in very great detail and, therefore, I think, it is my honour to be here and respond to many of the observations made by the hon. Members. Members have taken very keen interest and have also gone through the details of the Budget which is presented; a Budget which is for 'Atmanirbhar Bharat'. So, it is a Budget which clearly draws on the experience, the administrative capacities and also the exposure that the Prime Minister has had during his long elected tenure both as Chief Minister and as Prime Minister of this country, known for his commitment towards development, growth and reforms. So, these three things are essentially infused in the Budget, which is now speaking for itself in the sense, it is the instrument through which 'Atmanirbhar Bharat' is to be attained.

Sir, post-pandemic and post-global contraction, economies have suffered all over the world, and as I said during my Budget Speech, though attempt made in this Budget is to provide stimulus, provide a strong stimulus and provide such a stimulus which can bring in that kind of a multiplier effect and, therefore, instead of finding quick short-term solutions even as we provide short-term quick relief for those people who so desperately need it, we are also looking at medium-term and long-term

sustainable growth which will keep India in that kind of a growth trajectory which will maintain us as one of those fastest-growing economies in the world. So, the Government has heard views, opinions, suggestions from experts, from various policy makers around in the country, economists from several parts of the country and also some from outside and then placed all the thoughts together to produce this Budget, which has been tabled in the House. Building an Atmanirbhar Bharat actually reflects the aspirations of the people of India, 130 crore people of India, many of whom, two-thirds of whom are youth who are looking for opportunities, looking for dignified ways in which they can live the lives, contribute towards building of this country and, therefore, are looking not merely for just assistance from the Government but also facilitation and building of such ecosystems with which they can contribute to the economy. So, the stimulus is for revival and systemic reforms even during the pandemic that the Prime Minister has taken up, and those reforms are the ones which are going to sustain the growth, sustain ease of doing business and sustain India as the leader in terms of entrepreneurial skills and, therefore, the blend of looking at stimulus provision and also not losing out on the opportunity that we can derive even though we are living in a pandemic situation to reform and make India better managed, better governed country for our youth. So, the relief and succour which was so required for our poor, for those people who were very much outside of their villages, outside of their States, were so distinctly provided. I think, many of us have observed it, many of them have been repeated, but it is worth mentioning just once that 800 million people were provided free foodgrains, free cooking gas provided for 80 million people and cash directly was given to 400 million people, farmers, women, Divyang and also the poor and needy. So, an immediate response, as soon as the lockdown was announced, has actually provided that so much required succour which is absolutely necessary to support our citizens, PM Garib Kalyan is valued at Rs.2.76 lakh crores which is a timely measure that was necessary to be taken. Now, even before I get into some of the details which many of the hon. Members have raised as issues saying that 'can we have a bit of clarity, will it assure some kind of steps, and so on'; I just want to straightaway address one issue? Mr. Chairman, Sir, it has now become a sort of habit for some in the opposition to constantly allege that whatever this Government is doing, in spite of all that we are doing for the poor and more needs to be done, and that is not denied at all, in spite of various steps, obviously these steps taken for helping the poor and needy of this country, a false narrative is created to accuse saying, oh, this Government works only for cronies. I just want to come up with some details before I get into some of the details in the Budget to say that under PM Awas Yojana, Sir, more than 1.76 crore

houses have been completed. Is that for the rich? Households which are being electrified under Saubhagya since 2017 October, are more than 2.67 crores. Is that for the rich? Total value of orders placed on Government e-market place, it is Rs. 8,22,077 crores, which is more than eight trillion of rupees. Are they being given to big companies? They are being given to MSMEs. So, we have helped out small and medium companies to ensure themselves getting a market. Is that for the rich and the big capitalists?

The length of the roads sanctioned under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, strictly between 2014-15, is 2,11,192 kilometres. Those roads go to villages. Are they villages only for the rich? Or are these the villages where the people belonging to the lower sections of the society also live? Are there villages where the poor don't live? So, whose life-line are these roads? Unthinkingly, before just throwing allegations saying, 'Oh, this is for crony capitalists; this Government is working only for the rich!', please answer these questions. Total verified applications on the national scholarship portal are 9 crore people, all of whom are getting scholarships. For whom are these scholarships going? Are they going to the rich? Are they going to the capitalists? Are they going to the cronies, who the UPA Government had happily encouraged? Now, you stand up each time, creating a false narrative. Before I get into the details of the Budget, I want these questions to be kept in mind much before false narratives are thrown at us. The number of farmers registered on e-NAM are approximately 1.69 crore. Thanks entirely to the hon. Prime Minister's efforts to make sure that the farmers are connected all over the country, the farmer is not constricted by the local markets. If he has better opportunities anywhere else, he should have it. Are these farmers rich corporate? No, not at all. They are the small farmers. The number of digital transactions via UPI from August, 2016 till January, 2020 amount to more than Rs.3.6 lakh crore. UPI is used by whom? The rich? The corporate? No, not at all. The middle-class, the small traders, all of them use the UPI. Who are these people then? Is the creation of this UPI for facilitating digital transactions to benefit some rich cronies, some *damad*s? No, not at all. It is for helping only the poor. The number of farmers registered under PM Fasal Bima Yojana is almost 9 crore. The farmers who benefit out of PM Fasal Bima Yojana are not large corporate farmers. So, when you allege us saying that we are not taking care of small and medium-size farmers, the Prime Minister, while standing and speaking in response to the debate on the President's Address, spoke extensively about the small farmer. I want to remind you of this number, the people who get benefits from PM Fasal Bima Yojana. For whom is that?

Sir, as regards loans sanctioned under MUDRA Yojana, more than Rs. 27,000 crore has been given under it. Who takes loans under MUDRA Yojana? *Damad*s? Therefore, please don't you allege against us before ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति : प्लीज़, आप बैठ जाइए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। आप unnecessary क्यों force करते हैं?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I didn't think it is a trademark of the Indian National Congress. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, this is not fair. ...(*Interruptions*)...

श्री सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक): *

MR. CHAIRMAN: It is not going on record. Why are you wasting your energies?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: दामाद हर घर में होता है, मगर इंडियन नेशनल कांग्रेस में 'दामाद' एक specialized नाम है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let us not get disturbed about *damad*s. ...(*Interruptions*)...

श्री सैयद नासिर हुसैन: *

श्री सभापति : आपकी आवाज़ रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, आपका vocal cord खराब हो जाएगी।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the total number of beneficiaries under the PM Kisan Samman Nidhi Yojana; Rs. 6,000 is directly given to small and medium-size farmers. Eleven crore farmers have received PM Kisan Samman Nidhi Yojana. I can go on like this to say enough and more evidence exists.

AN HON. MEMBER: Enough, enough.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No, it is not enough. You don't have the patience to hear more.

---

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: He is satisfied Madam, you may continue. He is saying that he is satisfied.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sometimes, running commentaries are useful to remind, Sir. So, this Government's efforts are visible with credible proof of who the beneficiaries are, which are the major schemes, and, therefore when the Budgetary provisions are made, it is made for the poor, dalits, tribals and the students who desperately need all the benefits. Therefore, if you want to speak out, think of how many women got benefited by Ujwala Yojana. We have extended it to one crore more women. For whom would Ujwala be delivered? Delivery and performance in terms of the last mile connectivity is where we have distinctly shown even on some instruments which you have created. Even if it is MGNREGA, I will give you the data to prove how ...(*Interruptions*).... No, no; you don't need to thank me, but you will have to answer some questions where MGNREGA has greater provisions in actual numbers during our time and effectively using it. I will give you the data in a minute. Therefore, stimulus, giving stimulus, to such an expenditure, the capital creating expenditure, creating infrastructure, is one of the main features of this Budget, especially the one that it is coming after a pandemic. The other, as I said earlier, is not losing out on this opportunity of the pandemic, continuing with reforms and that is governed by the principle which Prime Minister spoke about even in 2014. In fact, deriving from that, one of our leading newspapers, which I wouldn't think will ever support disinvestment, has written an editorial to say, 'Belated, but bold', belated because Prime Minister had assured in 2014 that he would ensure that disinvestment process happened, and to have a policy coming in 2021. The paper rightly says 'belated' but calls it 'bold' too and we shall show how minimum Government and maximum governance will be achieved. Fiscal reforms, with a clear trajectory of showing how the deficit is going to be managed, and, above all something which will be reminded over and over again, is bringing transparency in Government's accounts, accounting for everything which is there and I shall pick it up from the speech of the former Finance Minister, 'figures are suspect in this Budget'. I will give three concrete evidences of how accounts were suspect. I am not using that word. ...(*Interruptions*)... I am not certainly using that word, but it became suspect with a benefit of hindsight. I can give you clear proof of how data became suspect in times which were not under the leadership of Prime Minister Modi. We have brought everything on to the Budgetary accounting mechanism. What you get as Budget is what is there in it, no pushing things under the carpet. So, these are essentially the features I want to highlight in this Budget, and many Members have duly recognised

it. I am very grateful that Members have recognised that the Budget has come out boldly on many things, clearly and openly stated what the Government's position is. Therefore, admittedly, the fiscal deficit number is what it is and we have not even hurried to say, 'Okay, next year we will quickly get the deficit number to something which all of us would like to see.' Not at all. We are going to be careful about how we are going to come down that path without affecting or creating any hurdle in the growth path of this country. Sir, I want to say one word on the disinvestment policy, disinvestment of CPSE policy. As I said, obviously newspaper editorials and many newspapers have also said that it is bold and some newspapers felt that ideologically it is forthright. I wish to say one line here. Repeatedly, we hear how 1991 and the reforms of 1991 were very important. Yes, they were very important. There is no doubt about it, but then, the entire range, which the Congress Party covered from high socialism, hybrid socialism, with Indira Gandhiji's Congress also reaching a level of socialism, was nothing but licence quota raj, and from there to 1991, without blinking an eyelid, without even saying that we are opening up the economy, they moved from that high socialism to come down to opening globablisation and everything else.

Today, it is clearly coming out that it is a position which is consistent with BJP and Jan Sangh's ideology of taking care of people at the bottom of the rung — Antyodaya — and, at the same time, respect wealth-creators and respect taxpayers. All our citizens will have to be respected. So, this certainly is in line with and consistent with the policy of our earlier version — Jan Sangh — and the present BJP. So, this policy has consistently been maintained and entrepreneurs in India have always shown their strength, achieved glories and we should respect them; rather than, constrict them through all kinds of holding, regulations and licence. Therefore, the route in which we have gone in order to achieve the stimulus is to fund infrastructure in several areas, like rail, road, bridges, ports, waterways, agriculture and health.

Of course, it was rightly pointed out that I did not mention about Defence. However, allocations for Defence, whether you look at pensions or capital expenditure or revenue, have not come down. Data will certainly show that in pensions between last year and this year there is, definitely, lesser number being shown because of discharge of part liabilities. So, obviously, the number was much higher and it is stabilized now. But, on all three counts — if you account for arrears — there is only increase. In fact, there is 18.8 per cent increase, if I am right. I will show you the figures. The figure has gone up in terms of capital expenditure for Defence.

Sir, I did mention about reforms. I also mentioned about licence quota raj and how we have clearly moved away from that.

Now, I will go item-by-item, Head-wise, on which several hon. Members have asked questions. Hon. Members have asked questions on Health, Defence and so on. I am not responding one-by-one taking the name of each hon. Member. But, I am responding topic-wise and hope to cover the issues raised by each hon. Member during his/her speech.

Sir, it was felt, by bringing drinking water and sanitation into health, we are, probably, not showing the entire picture and, probably, the core allocation for health — it is known as Department of Health and Family Welfare's Budget — has come down. If I just compare the BE to BE, it is not fair. However, I would like to bring in the WHO's observation which justifies bringing in water and sanitation into health. Sir, WHO mentioned and I quote, 'Safe drinking water, sanitation and hygiene are crucial to human health and well-being...' — it is WHO's WASH — '...Safe and sufficient WASH plays a key role in preventing numerous Neglected Tropical Diseases such as trachoma, soil-transmitted helminths and schistosomiasis. Diarrhoeal deaths as a result of inadequate WASH were reduced by half during the Millennium Development Goal period 1990—2015 with a significant progress on water and sanitation provision playing a key role.' So, increased allocations for water have been based on the objective to provide tap water to ensure health for all in the long-run. So, even if we just look at allocations made to the core health departments, there is a substantial increase in their allocations. I will just read out three Heads to prove the point. Sir, BE for the Ministry of Health and Family Welfare in 2020-21 was Rs. 65,012 crores and in BE 2021-22 the allocation is Rs. 71,269 crores which is a 9.6 per cent increase. That is core.

The allocation for the Ministry of AYUSH, which is again core health, was Rs. 2,122 crores in 2020-21, which went up to Rs. 2,970 in this Budget. This is a 40 per cent increase in the AYUSH Ministry. The highest allocation, amongst all these three, goes for health and family welfare. For health research, it was Rs. 2,100 crores in 2020-21; whereas, it went up to Rs. 2,663 crores in this Budget, constituting 26.8 per cent increase. Just these three, which are normally seen as core departments of health, and not bringing in water and sanitation, you have 9.6 per cent, 40 per cent and 26.8 per cent for the three categories. So, let us not be carried away by this debate -- Oh! you brought in health here; you brought in water and sanitation here; you brought in *poshann* here. In the core three, which everybody looks up for figures, we have increase, increase, and increase. That's about the health.

I, once again, come to defence. I did mention a minute ago on defence expenditure. It is always easy to club it all together and say defence expenditure is this or that. ...(*Interruptions*)... Yes, I am coming to that. We will have to divide it into three compartments -- the revenue, the capital, and the pension. Just to give you a comparison, I will first read the figures of 2011-12 and 2012-13. In 2011-12, the revenue was Rs. 95,216 crores, capital was Rs. 69,199 crores, and pension was Rs. 34,000 crores. Now, I come to 2012-13. The revenue was Rs. 1,13,829 crores, the capital was Rs. 79,579 crores, and pension was Rs. 39,000 crores. I don't want to go year-by-year. I come straight to the year, which is ending now, that is, 2020-2021, where the revenue is Rs. 2,09,319 crores as against Rs. 95,216 crores in 2011-12. It is just on revenue account! The capital in 2011-12 was Rs. 69,199 crores. It is now Rs. 1,13,734 crores. The pension in 2011-12 was Rs. 34,000 crores. Now, it is Rs. 1,33,825 crores. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: What about last year? ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Last year, revenue, capital, and pension grew at 3.7 per cent, 10 per cent, and 19.4 per cent respectively. Now, I come to this year's allocation. In 2021-22, revenue was Rs. 2,12,028 crores, which is 1.3 per cent more than BE of last year. It is BE to BE comparison and no mixing up. Capital was Rs. 1,35,061 crores, which is 18.8 per cent increase in this Budget. Pension was Rs. 1,15,850 crores, which is a fall from last year because last year's number had a huge addition because of arrears, because of court cases or queries on pension arrears which had been paid, which is one-time, and that got rationalized now. But, even then, it is much higher than 2019-20. So, on every count, even the Defence Budget is higher, although you would tell me that in your speech, you did not mention Defence at all. Here are the figures. It is available in the Appendix of the speech; it is available in the documents of the Government expenditure.

On PM Kisan Samman Nidhi Yojana, I think, broadly, I have given the figures. It has been said that the figure '10,000' has become reduced.I wish the hon. Members who had raised that question — I am glad they have raised it and have given me an opportunity to answer -- would have had a look at what, actually, the figure is. First of all, benefits worth Rs.1.15 lakh crores have been transferred into the bank accounts of 10.75 crore farmer families under the Scheme since its inception. Let us be clear; Rs.1.15 lakh crores have been transferred directly into the accounts of farmers. The cash in the hands of the farmers is what is Rs.1.15 lakh crores. Now, in the B.E. 2019-20 and also the B.E. 2020-21, an allocation of Rs.75,000 crores each

year was made under this Scheme. In R.E. 2020-21, the allocation has been rationalised to Rs.65,000 crores, which is what is being pointed out to us, saying, You cut down Rs.10,000 crores. Not at all! A similar allocation is also provided in 2021-22. But I will tell you why the rationalisation had to happen. Sir, one of the main reasons for rationalisation to happen is, in the allocation of PM Kisan Samman Nidhi Yojana, approximately 69 lakh estimated farmers from West Bengal have not received any benefits under this Scheme. ..(*Interruptions*).. We had taken them on board. But when the provision could not be utilised because their list was not even given to us, obviously, in the R.E., the number will be different and the provisioning that we will have to make for the next year will also be dependent on it. We took the entire country. We wanted farmers of every State to receive this. But if there is one State which refuses to give its list, then, the amount remains, and, therefore, the amount which has to be given to all the farmers in the B.E. next will be reflective of that number which is not coming on board. So, '10,000 crores' is not going anywhere else, Sir; it is because one State has not given us the list. So, that is on PM Kisan Samman Nidhi Scheme, where you felt that the numbers are different.

Sir, I would want to go on to a very important issue, which pertains to what have we done about the people who have been thrown out of their jobs, what is happening to MNREGA, and so on. I will first go to the MNREGA. Sir, year on year, the enthusiasm with which, particularly, the Members in the Opposition belonging to a particular party own it all up, saying, MNREGA is ours, you don't claim any credit on that. The MNREGA is ours; you don't talk about it. ..(*Interruptions*).. Oh my God! ..(*Interruptions*).. To give birth to a scheme is yours, no doubt. ...(*Interruptions*).. But there was mess, and it was poorly utilised, leading to even CAG's report, mentioning as to how the people who should have got it did not get it. They did not even have the actual numbers of farmers or workers who got enrolled on demand. Therefore, the first submission, hon. Chairman, Sir, is, we create a scheme, we give B.Es, but every year, we have utilised far lesser than the B.E. That is our credibility about MNREGA, but you want to speak about it with ownership! Whereas what we have done after the Prime Minister, Shri Narendra Modi, took charge in 2014, is, we removed all the ills out of that Scheme, and utilised it effectively, which the data proves. ..(*Interruptions*)..There is no point in heckling because the data proves.

MR. CHAIRMAN: Don't worry, it is not going on record.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I seek your indulgence, Mr. Chairman, Sir, because I will give the numbers. Sir, 2009-10 BE was Rs. 39,100 crore; RE was also

Rs. 39,100 crore. But the actual number, which was actually spent, was only Rs. 33,539 crore. Now, similarly, for 2010-11, 2011-12, I will read the numbers. Rs. 40,100 crore BE; Rs. 40,100 crore RE. But you actually spent Rs. 35,841 crore. Down; 40 again down to 29 in 2011-12; in 2012-13, 33 down to 30; in 2013-14, 33 down to 32. Then in 2014-15, 34 down to 32. Every year, it is lesser and lesser and lesser. In BE, you claim that you have given that much, and actually no utilization happens. All right.

Sir, in 2015-16, after our Government comes, 34 is 37 in actual utilization; 38 in 2016-17 is 48 in actual utilization. In 2017-18, 48 becomes 55 in actual utilization. In 2018-19, 55 becomes 61 in actual utilization. And, in 2019-20, Rs. 60,000 crores becomes Rs. 71,000 crores in actual utilization. In 2020-21, which is the year of the Pandemic, Rs. 61,500 crore is the amount that we gave, prior to the Covid coming in, in February, 2020 Budget; 61 which was 1,500 more than the BE of the previous year. But because during the Covid period we had to come in with greater help, we went on giving, through the Supplementary Demands and so on, Rs. 1,11,500 crore and, as of now, the actual utilization is Rs.90,469 crores, the highest ever; and without hesitation, we kept giving, proving our track record that the BE could be something but, actually, we also provide for more of it, whereas, you gave BEs, and, at the end of the day, you forgot it. ...(*Interruptions*)... Whatever or little which was utilized was far lesser than your BE. So, your track record is that, not for just one year or two years. Your track record is, BE provision, and at the end of the day, utilization 'God knows', anybody's number. ...(*Interruptions*)... Never, never, your BE was matched. So, higher BE to BE!

Now coming to this year's provision, Rs. 61,500 crores was February, 2020, just prior to Covid. Now, Rs. 73,000 crores is given in this BE, which is higher than the BE last year, having in-between provided during the pandemic for MGNREGA. So, I want on 'MGNREGA' less emotional but more factual debate. Ownership alone doesn't gum in, but come, talk the details, talk the facts. ...(*Interruptions*)... MGNREGA, MGNREGA, you have not done anything on MNREGA! This is what we have done on MGNREGA. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, also this question about what you have done in terms of unemployment. I want to just very quickly list out the things that we have done for unemployment. Yes, a lot of people suffered during pandemic. But immediately, after the *Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana* was announced, we came

up with the *Garib Kalyan Yojana* within which we provided for the employees to draw money from their accounts but sooner we also said, 'both 12 per cent employees' share and the employer share will be provided if a certain number of total number of employees would take up the job, those who were being dispensed with, and, for that, Rs. 2,567 crores have been credited upfront into the EPF accounts. So, it is not a promise we gave and we sat back. We actually gave that amount towards 12+12 of the PF amount which had to be given, and that money was paid into 38.82 lakh eligible employees' accounts. This is something that I wanted all of you to know. This money has been given to 2.63 lakh establishments.

Sir, other than this, we have also come up with the *Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Yojana*, which is partly covered under the MGNREGA. In nearly 116 districts, spread over six States, which received migrant labourers back, nearly Rs. 50,000 crore were paid through this particular scheme. This was for migrant workers who went back to their respective districts, so that when they reached home, they didn't face a situation of having no employment, and some kind of money was paid to them. So, Rs. 50,000 crore has been given to them.

Sir, under the *Pradhan Mantri Swanidhi Yojana*, 15 lakh street vendors have benefitted and Rs. 10,000 has been given to each one of them for a one year period as working capital. Then, Agriculture Infrastructure Fund for the farm gate also enables a lot of income-generating activities. That is very important and we have to take cognizance of that. Then, we came up with the *Atmanirbhar* package in which several such extensions, particularly, the one which was last announced, were made, which is used when employers take back workers. That provision exists for all workers who were thrown out of their jobs between 1st March, 2020 and 30th September, 2020. If the employer takes back all those who had been sent out of their jobs, we have agreed to pay the employees' contribution for the next two years. That would be up to 31st May, 2023. As it is, a lot of people have started enrolling in it. Sir, 1.46 lakh establishments are already registered; 7,75,000 people are new joinees and those who are coming back to the same jobs are 1,78,369, as of 1st February. We need to continuously keep updating these figures.

Sir, that was about MGNREGA and unemployment. A lot of people questioned us about what we have done about MSMEs. I would tell them very quickly.

MR. CHAIRMAN: Just a second, Nirmala*ji*. You are making an elaborate reply. There is no problem with that. The only thing is that we have to conclude by 3 o'clock. I am equally concerned about the health of the Members. Lok Sabha would be meeting at 4.00 p.m.

SOME HON. MEMBERS: Sir, health of the economy....

MR. CHAIRMAN: Yes, health of the economy. If people are there, economy would be there. If economy is there, people would be there. That is what she is explaining also.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I would just elaborate a bit on the MSMEs. I would probably, if necessary, answer Members on Covid-related measures, which I wanted to elaborate on, but then a bit of the conclusion also. I hope to finish, Sir, in reasonable time.

Sir, in 2019, there was this UK Sinha Committee, which had submitted a lot of recommendations for helping the MSMEs. We have been, since 2019, taking a lot of steps so that MSMEs get all kinds of assistance in different levels of stress that they may be in. We still wanted to help them. So, there was a Self-Reliant India Fund, which was given some money with which five times more monies were to be raised by Daughter Funds, which would come out of the Rs. 10,000 crore that were given as anchor money. The National Small Industries Corporation Limited was to execute it, and they are executing it. An initial Rs. 500 crore has been allocated for this year and the next and, therefore, we expect that to go on helping out our small and medium units. During the pandemic, as you are aware, we came up with an Emergency Credit Guarantee Liquidity Scheme.Earlier, it was a scheme for three lakh crores and as of 10th February, 91 lakh borrowers, all MSMEs, have benefited from that scheme. The total sanctioned amount is Rs.2,43,440 crores, of which Rs.1,78,000 crores have already been disbursed. So, the money is actually going in the hands of MSMEs who want additional working capital without any additional security being asked for. With the existing security, people got additional working capital and an amount to the extent of Rs.1,78,000 crores has been given to them. A Subordinate Debt Scheme was also brought in wherein stressed MSMEs, almost on the verge of NPA-kind of MSMEs, also could borrow in the name of their promoters. They took equity and borrowed money, and then put it as equity into their businesses and thereby raised the company out of the stressed situation and became eligible for other benefits which banks could extend. Rs. 4,000 crore were given as corpus for this and MSMEs which were completely stressed have also benefited from that scheme. Besides that, a lot of other smaller schemes and definitional changes in MSMEs have helped many of the MSMEs to come out of the difficulty. I don't want to go on elaborating it; it is available in records for people to see it.

Sir, there was this feeling that development sector allocations have not really been kept up because you have been constantly talking only of funding CapEx. That is not true. I want to tell you very quickly in terms of numbers. In Department of Health and Family Welfare, I have given you the disaggregated figure, there is 21.3 per cent increase. In AYUSH and Health Research, it is 93.4 per cent. In the RE of 2021, following important Departments, apart from subsidiary Departments, have seen substantive growth in their allocation. I just want to read that out: Pharmaceutical, 41 per cent; Rural Development, 64.3 per cent; Railways, 54 per cent; Labour and Employment, 13.7 per cent; Defence Capital, as I told you, 18.3 per cent; DFSS, 131 per cent and DPIIT, 14.8 per cent. You are also aware that we have taken a lot of steps during the COVID so that companies don't come under stress. We have suspended the IBC implementation. We have also given a lot of relief through the Debt Recovery Tribunals and so on. A lot of processes have been held back so that companies are not pulled into insolvency or any kind of litigation. I will stop going into details here since you have told me that everything has to get over by 3 o'clock.

MR. CHAIRMAN: I am sorry. But what can I do?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I understand it. I just want to highlight that this Budget is a Budget for *Aatmnirbhar Bharat*. We respect honest tax payers that their money which is paid as tax should be properly utilised. We should be accountable for the money that we get as tax and, therefore, we came up very clearly to show every money which is being spent on the Budget itself, rather than keep it outside. A classic case is the onboarding of food subsidy and the impact on the FCI balance-sheet. We have onboarded food subsidy budget and, therefore, then cleared the loans which were due to the NSSF. I just want to elaborate on that because it has very serious and important positive implications. The balance-sheet of FCI has improved and that is so important for MSP-based procurement; it is so important for keeping the health of FCI very good because it is important for our food security.

3.00 P.M.

Their outstanding loans from NSS, that is, National Savings Scheme, are estimated to be reduced from Rs.3.39 lakh crores to Rs.1.19 lakh crore by the end of the current Financial Year and to only Rs.0.58 lakh crore by the end of the next of Financial Year. The Government has been completely responsible and careful to repay the debts

which are taken by the FCI from the NSSF. Additionally, we have provided an amount of Rs.2,500 crores as capital infusion into the FCI, and, therefore, keeping them healthy to continue with their procurement and storage operations. This will strengthen the financial position of FCI and reduce the debt servicing cost of FCI, which will ultimately borne by the Government of India.

Sir, if that is one thing, I just want to, because it is important, refer to the speech of the former Finance Minister who responded to the Budget of this year. I am quoting from his speech. He said, "Major numbers are suspect in this Budget." I just want to highlight three instances where there was an artificial increase in the CAPEX figure, CAPEX growth. The first was shown in 2007-08 when the former Finance Minister was the Finance Minister. An increase of 62 per cent was shown, BE to BE, in 2007-08 Budget. Actually, now, with the benefit of hindsight, all of us can say, "Suspect, indeed!" Sixty-two per cent increase! ...(*Interruptions*)... I will definitely explain why I am saying that. In 2007-08, the jump in the Capital Expenditure was on account of a routing exercise, routing entry, in which Rs.40,000 crore was made for acquiring RBI stake in SBI, which was actually a fiscally-neutral transaction, designed for whatever reason at that time. If that 62 per cent was actually offset for this Rs.42,000 crore, which was a fiscally-neutral transaction, and if you strip that off, the growth rate in CAPEX that year was only 9 per cent. If that 62 per cent growth in CAPEX, which was claimed, is not suspect, then what else? And, saying that it was the highest ever CAPEX spent; not at all. The highest ever CAPEX is the 34.5 per cent which we have done now, and that CAPEX is getting split between Railways at 53 per cent, Roads at 32 per cent and Defence at 18.7 per cent. That is what an honest statement is and the FCI onboarding in the Budget is an honest statement. These are not suspect. The former Finance Minister, and I seriously take every word of what he said...(*Interruptions*)... and, therefore, I am telling that it was a wrong statement to make. We have come up with onboarding on factual matters and we have not shown this kind of fiscal neutral routing as claimed for Capital Expenditure. This is the actual figure.

Secondly, Sir, special bonds were issued in lieu of cash subsidy, which is absolutely something which all of us will be shocked at but it is worth stating for the records. Special bonds worth Rs.1.7 lakh crores were issued to oil marketing companies in lieu of cash subsidy. The issuance started in 1997-98. The Petroleum Minister is here and he would also know the details when the oil bonds to the tune of Rs.12,984 crores were issued. Again, special bonds worth Rs.27,500 crores were issued to fertilizer companies. Show it on your Budget. Why did you not do that? And, our numbers are suspect when you have done this!

Special bonds worth Rs. 27,500 crores to fertilizer companies in lieu of cash subsidy beginning 2007-08! This is not our practice, Sir. Again, special bonds worth Rs. 16,200 crores to FCI; that FCI, whose loans, we are now paying back and getting them on board. Sir, special bonds worth Rs. 16,200 crores to FCI in lieu of cash subsidy beginning 2006-07, and, then if my balance sheet looks attractive, you know why?

Sir, I just want to quickly finish it with the last thing, which, I remember, Shri Arun Jaitley, after taking charge as Finance Minister in 2014, had to pay up and clean up, is that the oil companies were asked to foot the petroleum subsidy bill. The oil companies were asked to do it, and, when we came back after the Vote on Account in July of that year, it was realized that in 2014-15, an amount of Rs. 63,427 crores was artificially kept under, " Compensation to Oil companies for under recoveries on account of sale of sensitive petroleum products." In 2014-15 July Budget, Shri Arun Jaitley, after the NDA came to power, realized that there was an under-provisioning. Now, that word is very important because we have been alerted that quite a few under-provisioning has happened; you should take care. Former Finance Minister says this. Under-provisioning was done during his time, Madam. In 2014 Budget in July, ...(*Interruptions*).. Yes, Mr. Chairman, Sir, because there was a reference by one of the Members. ...(*Interruptions*)... No, no. A madam's running commentary has to be drawn. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please don't worry. There are Madams also sitting that side. Madam is looking to Madam. Please don't worry. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: A running commentary, Sir, by a Madam will have to be drawn. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... You don't worry. You don't worry about me; you worry about yourselves.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am concluding, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: You don't worry. ...(*Interruptions*)... They are so much concerned about the Chair.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, in 2015-16, in July Budget, the NDA Government realized that there was under provisioning and the oil marketing

companies were being asked to foot the subsidy bill, labeling it as" Compensation to Oil companies for under recoveries on account of sale of sensitive petroleum products" and interestingly, on that, and, earlier also, see the kinds of expressions which were used. Anyway, I do not want to take much time. The then Finance Minister corrected what was pushed on to the balance sheet of oil marketing companies. That is what makes Budget suspect for the common citizen; not what we have done this year.

Sir, in order to conclude, I just want to say that false narratives were created. ...(Interruptions)... Yes, yes; competent also to keep fudging, maybe, and, I do not want that competency. Prime Minister Modi does not depend on fudging and competency does not arise out of that.

Sir, there is a lot of grudge in the speech of the former Finance Minister. I just want to read those little sentences just for the context. Under provisioning was a reference made and I have explained that. He said, "I have complimented you in writing and I compliment you here". This is at one place. At another place, "While I have given you half a compliment and I have to hold back the other half of the compliment." At third place, while quoting Dr. Gita Gopinath -- who said that it is mechanical that growth happens and all that -- he said, "Don't claim credit for that growth". It is also a little assertion by the former Finance Minister and I am quoting from his speech.

So, I feel that there is a little grudge not to recognise how hon. Prime Minister handled the Corona crisis. Today, the entire world is seeing how we, in India, have had less deaths per million. We, in India, have less active cases when there are countries which are seeing wave after wave. And this handling is entirely due to coming upfront and leading from the front by the Prime Minister. And the common people of India had common cause with the way he was dealing with it. Sir, I need to say just one last sentence. The former Finance Minister.. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Please, please. You are not making a speech. It is not going on record. You have made your speeches. She is replying. Apply your mind to the reply and keep it for future discussions.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, you have just given me the context to say something. Please pardon me if I am taking it a bit light. I will seek your indulgence, Sir. The former Finance Minister gives me a feeling that he is trying to imitate you. ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: No; he has spoken. She has to respond. ..(*Interruptions*)..

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I get the feeling that the former Finance Minister is imitating you, but he has been a miserable failure in the impact that he created, unlike you, who creates a good impact. I will tell you why. The imitation and the copy of the Chair in coming up with rhyming words, texts, pretexts, sub-texts, contexts, he used all these trying to imitate you who spontaneously do it. You have a sense of timing. All of us rejoice in that kind of banter and light-hearted way in which you use the rhyming words. It brings a different sense in the House. Trying to imitate it and having absolutely no impact absolutely proves that it was a contrite speech which had nothing to accuse this Budget of, but verbose, craftsman of words, we can say what we want and get away with it. 'It is a Budget by the rich, of the rich', was a statement given by the former Finance Minister. I explained right at the beginning that roads, Ujjwala, electricity and also direct benefit transfer do not go to the rich. They go to the poorest of the poor whose cause the Prime Minister champions. Therefore, Sir, I think, the Opposition's questions, doubts, I have tried attempting, giving them a response. I quite welcome any Member who wants any further clarification. Thank you for this opportunity.

MR. CHAIRMAN: Please, the time is very less.

SHRI KAPIL SIBAL (Uttar Pradesh): Sir, may I just seek a clarification? The first thing, I want to congratulate the Finance Minister for at least accepting the fact that we want to make India *aatma nirbhar*, not yet *aatma nirbhar*. I am very happy that she has accepted that. The clarification I want is that you have reduced the allocations. It is the *kisan* who is hurt, the *kisan* who is sitting there, and you have reduced the allocation. I want to ask: Why have you reduced the allocations for agriculture? As far as the...

MR. CHAIRMAN: Right, Sibal *ji*.

SHRI KAPIL SIBAL(Uttar Pradesh): Just one second, Sir. You have also reduced the allocations for education. Please clarify to the House as to why you have reduced the allocations for agriculture and education. And there is one other thing.

MR. CHAIRMAN: No, no. One cannot go on asking the clarifications.

SHRI KAPIL SIBAL: You had promised the defence personnel...

MR. CHAIRMAN: No, no.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, just one second.

MR. CHAIRMAN: No, no. I have previous instances also. ..(*Interruptions*)..

SHRI KAPIL SIBAL: You had promised the defence personnel that every five years you will increase the pension of the defence personnel. Why did you not increase the pension this year?

MR. CHAIRMAN: Anybody else?

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I have one clarification. Allocation for MIS-PSS for 2021-22 was Rs. 1,500 crores. It fell by 25 per cent from 2020-21 and was half of 2019-20. Allocations under ..(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: What is the clarification?

MR. CHAIRMAN: What is the clarification?

SHRI BINOY VISWAM: Allocation for the most important funds meant for the MSP has been reduced. Why?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, with due respect, hon. Member, Shri Kapil Sibal *ji*, asked me about the education allocation, actually, it has not been reduced. Total allocation for the Department of School Education and the Department of Higher Education is Rs.93,224 crore in 2021-22 B.E. which is 4.2 per cent higher than the actual expenditure of 2019-20 and 9.6 per cent more than the current R.E. That I want to explain, Sir. Similarly, under the National Programme of Mid Day Meal in schools, the allocation in B.E. of 2021-22 is Rs.11,500 crore which is higher than the Rs.11,000 crore in the B.E. of 2020-21. It has actually not been reduced.

On Defence, I did explain that under no category have we reduced it. On the contrary, we have only increased it. On increasing of pension, it is not just about the

Government of India. It will have to have a whole lot of exercise. ...(*Interruptions*)... It is not something which within one year...(*Interruptions*)... The hon. Member, Shri Binoy Viswam, asked. ...(*Interruptions*)... I am sorry, Sir, through you I want to tell this. Agriculture MSP reduction! I have read out even during the Budget Speech as to how much of procurement under the MSP for each one of those will be done. Twenty-two crops are listed. And all 22 we are opening up for MSP procurement. And from where is this imaginary...(*Interruptions*)... 'Oh, you have reduced it!' This is why I humbly submit and appeal, Sir, through you, to the Members that please do not buy fake narratives. Have a look at the Budget. Actual numbers are there.

OBSERVATIONS BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Thank you.

Hon. Members, a two-week long first part of this Budget Session concluded today. I am happy to inform you that this part of the Session has been quite productive with the House clocking 99 per cent productivity. The productivity of the House during this week has been 113 per cent as against the productivity of 82 per cent during the first week. As against the total scheduled time of 45 hours 4 minutes, net of only 30 minutes have been lost due to disruptions. This part of the Session has been one of debate and discussions with a total of 27 hours and 11 minutes, accounting for over 60 per cent of the total functional time spent on discussing the Motion of Thanks to the President and the General Budget for 2021-2022. About 100 Members spoke on these two subjects alone. As against the total loss of 4 hours 24 minutes during the first week, the Members sat for an extra 3 hours 54 minutes during the second week. A total of 88 issues of public importance have been raised. These include, 56 Zero Hour mentions and 32 Special Mentions. Fifty-five Starred Questions were orally answered. Three Bills were passed - The J&K Reorganisation (Amendment) Bill, 2021; The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) (Amendment) Bill, 2021; and The Major Ports Authority Bill, 2020. This is the position as of now. We still have to go for the second part. I only appeal to the Members not to miss any Standing Committee meeting. Please see to it that you attend all the Standing Committee meetings and make contribution also.

I feel sorry, I will miss you, Shri Ghulam Nabi Azad *ji*, Mir Mohammad Fayaz *ji*, Shri Shamsher Singh Manhas *ji*, and Shri Nazir Ahmed Laway. I wish you all the best as I have said earlier.